राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १] तृतीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६२ का १७वां दिवस [संख्या ११

गुरुवार, दिनांक २९ मार्च, १९६२।

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[विद्युत, स्वायत्त शासन, सार्वजनिक निर्माण, यातायात एवं कर-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री भीमसेन।

भाखरा योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण

४५. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

जामसर, ऊदासर आदि गांवों को भाखरा विद्युत शक्ति कब तक उपलब्ध हो सकेगी ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : ऊदासर १९६१-६२ के विद्युतीकरण कार्यक्रम में सम्मिलित है और इस पर कार्य हो रहा है।

जामसर के विद्युतीकरण की १९६२-६३ में सम्भावना है।

प्रश्न संख्या ४६

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४७

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये।)

श्री विजयसिंह झाला।

ग्राम इशवाले से माहोली (उदयपुर) तक सड़क-निर्माण

४८. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा):

Page No 2

(श्री विजयसिंह झाला)

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या नाथद्वारा तथा माहोली क्षेत्र में रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑफिसर, उदयपुर के मार्फत ग्राम इशवाले से माहोली तक सड़क शीसवी-सिन्दू होकर जाने की कोई सर्वे सन् १९६१ में हुई थी ?

(२) यदि हां, तो इस सर्वे के अनुसार इस सड़क का कार्य सरकार कब तक प्रारम्भ कर देगी ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) इस विभाग द्वारा ऐसी कोई सर्वे सड़क की नहीं हुई है।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विजयसिंह झाला : क्या कोई सर्वे सब-इन्सपेक्टर श्री बाघसिंह आर. टी. ओ. में सब-इन्सपेक्टर है, उसने बी. डी. ओ. को साथ में लेकर नहीं की ?

श्री भवानीशंकर नदंवाना : बस रूट की सर्वे की होगी ।

श्री विजयसिंह झाला : सुनाई नहीं दिया ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : बस रूट पर सर्वे होगी ।

श्री अध्यक्ष: बस रूट की सर्वे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट करता है, सड़क की सर्वे पी. डब्लू. डी. वाले करते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : यह बस रूट का सवाल है ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : सड़क का सवाल पूछा है, उसका जवाब दे दिया है ।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न बस रूट के बारे में नहीं है, बल्कि सड़क, निर्माण के बारे में है ।

श्री जीवराज ।

जिला झुंझुनू के अन्तर्गत बननेवाली सड़कों की योजना

४६. **श्री जीवराज**(गुढ़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :-

(क) जिला झुंझुनू के अन्तर्गत किस मार्ग पर पक्की सड़कें बनने की सरकारी योजना है ?

(ख) क्या झुंझुनू से गुढ़ा होते हुए उदयपुरवाटी तक पक्की सड़क बनने की योजना है ? यदि हां, तो वह कब तक पूरी हो जावेगी ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री-भवानीशंकर नन्दवाना) : (क) सूची प्रस्तुत है ।

(ख) जी हां । आशा है, योजनानुसार तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला ।

Page No 3

राजस्थान स्टेट रोडवेज़ की बसों पर नियुक्त कर्मचारी

५०. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर से अजमेर तक जो राजस्थान स्टेट रोडवेज़ की बसें चलती हैं उन पर कुल कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं ?

(२) इन कर्मचारियों को कितने समय ड्यूटी देनी पड़ती है ? क्या इसके कोई नियम हैं ?

(३) इससे पूर्व जो बसें चलती थीं, उनके कर्मचारियों को नियुक्त करने की क्या व्यवस्था की गई ?

यातायात मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जयपुर से अजमेर चलने वाली राजकीय रोडवेज़ में नियुक्त किये गये कर्मचारियों की संख्या १३२ है।

(२) व (३) : इन कर्मचारियों को ८ घंटे तक की ड्यूटी देनी पड़ती है। यह ड्यूटी नियमानुसार है। उन कर्मचारियों को नियुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि राष्ट्रीयकरण होने पर इस मार्ग पर चलने वाली गाड़ियों को दूसरे मार्गों पर चलने की परमिट्स दी जा रही हैं। यदि ऐसे कर्मचारी राजस्थान स्टेट रोडवेज़ में नियुक्ति के लिए प्रार्थना-पत्र देते हैं तो उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह जो राष्ट्रीयकरण किया है इसमें अभी तक किसी ऐसे कर्मचारी को नियुक्त किया गया है जो प्राइवेट बस में काम करता था ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने अर्ज किया कि नियमानुसार उनको नियुक्त किया जाता है, वैसे उनको प्राथमिकता दी जाती है।

श्री विजयसिंह झाला : सवाल यह उठता है कि क्या ऐसे प्रार्थना-पत्र आये और क्या उनको नियुक्त किया गया या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास यह सूचना नहीं है कि नियुक्त किया गया या नहीं; लेकिन मैं समझता हूं कि दे दिया गया होगा।

श्री विजयसिंह झाला: दरअसल में प्रश्न यही था। अगर उनको नियुक्त किया गया है तो उनके वेतन के बारे में क्या होगा ? मेरी समझ में आपके पास सूचना पूरी नहीं आई, और अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब नहीं दें; यह अच्छा नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र : आपका प्रश्न क्या है ? आपने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब दे दिया कि उनको प्राथमिकता दी जाती है। वैसे ओनर्स का सवाल है और उनका जो स्टाफ है उनको रिप्लेस करते हैं, दूसरा रूट मिलता है। लेकिन जो सरप्लस हैं और ट्रान्सपोर्ट में आना चाहते हैं तो उनको प्राथमिकता देते हैं। लेकिन डेफिनिट कोई ऐसा नहीं है कि उनको नियुक्ति देनी पड़ेगी।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : प्रश्न यह

Page No 4

(श्री कुमारानन्द)

है कि जो बसेज़ में काम करते थे आपने पूछा है कि उनकी नौकरी के लिए क्या गारन्टी है ? उनकी छंटनी होगी, क्या होगा; यह प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न फिर दोहरायें।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं समझा नहीं।

श्री कुमारानन्द : प्रश्न यह है कि यह लिखा हुआ है कि इससे पूर्व जो बसें चलती थीं उनके कर्मचारियों को नियुक्त करने की क्या व्यवस्था की गई ? इस पर प्रश्न हुआ है।

श्री हरिश्चन्द्र : हमें क्या व्यवस्था करनी है ? सरकार कोई व्यवस्था नहीं करती। अगर वे एप्लाई करते हैं तो उनको प्राथमिकता दी जाती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या इस प्रकार की विज्ञप्ति निकाली है।

श्री अध्यक्ष : पहले उस प्रश्न का उत्तर आने दीजिए।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने अर्ज किया कि प्राथमिकता देते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : बड़ा सवाल यह उठता है कि जिनके प्रार्थना-पत्र आये उनको दरअसल में क्या प्राथमिकता दी ? क्या उनकी नियुक्ति हुई ? अगर हुई तो क्या उनका नया अपोइन्टमेंट माना गया या उन्हें वही वेतन जो मिलता था दिया जायगा ? जैसे ड्राइवर को वहां १०० मिलते थे और यहां ८५ कर दिये गये ?

श्री हरिश्चन्द्र : जो कन्डीशन्स स्टेट ट्रान्सपोर्ट की होगी, उन पर ही आना पड़ेगा।

श्री विजयसिंह झाला : पुरानी सर्विसेज़ थी, उनके बारे में क्या किया ?

श्री हरिश्चन्द्र : नई सर्विस स्टेट की होगी। हमारे साथ उनका कोई मेल नहीं था। They will come as new recruits.

श्री विजयसिंह झाला : आपने कहा कि अपोइन्टमेंट दिया गया। अपोइन्टमेंट पहले ही दे दिये गये, लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद जिन डाइवर्स की दरख्वास्तें आई थी उनको रिजेक्ट किया गया। ऐसी किसी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया ?

श्री हरिचश्न्द्र : यह अलग प्रश्न है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : क्या सरकार वाजिब समझती है कि पुरानी सर्विसेज़ को जोड़ दिया जाय ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह अलग प्रश्न है। इसके लिए नोटिस चाहिए।

श्री दलपतसिंह : यह पॉलिसी की बात है कि जो कर्मचारी पहले दूसरी बसों में नियुक्त थे और जिन्होंने प्रार्थना-पत्र दिये हैं, तो क्या सरकार वाजिब समझती है कि पुरानी सर्विस उसको जोड़ दिया जाय ?

श्री हरिश्चन्द्र : उनको सर्विस में लेने

Page No 5

(श्री हरिश्चन्द्र)

के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है । लेकिन मैं समझता हूं कि प्राइवेट ओपरेटर्स से उनको मुआवजा मिलना चाहिए । सर्विस स्टेट की नई होगी ।

श्री दलपतसिंह : क्या गवर्नमेंट की प्राइवेट बसेज़ पर काम करने वालों को नौकरी में लेने की कोई सिक्योरिटी नहीं थी ? मेरा तो यह निवेदन है कि अगर कोई ऐसा कर्मचारी है जो पहले प्राइवेट बसों पर काम करता था और जब बसें बन्द कर दी गई तो क्या उसकी पुरानी सर्विसेज़ बेकार चली जावेंगी ? गवर्नमेंट को उनकी सर्विसेज़ को आगे के लिए कन्सीडर करना चाहिये और यह देखना चाहिये कि उनकी पुरानी सर्विसेज़ यों ही न चली जावें ।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : It is just a question of suggestion.

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या सरकार ने कोई इस प्रकार की विज्ञप्ति निकाली थी कि उन लोगों को नौकरियों में लेने के लिए सरकार तैयार है ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : किस तारीख को निकाली थी; अगर कोई तारीख याद हो तो बताने की कृपा करें ?

श्री हरिश्चन्द्र : मुझे तारीख याद नहीं है । मैंने यह कहा है कि रूल्स के अनुसार हम एप्लीकेशन्स इन्वाइट करते हैं और जरूरत होती है तो ले लेते हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जब आपने एप्लीकेशन्स इन्वाइट कीं तो....

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है । आपको जो प्रश्न पूछना है वह स्पष्टतया पूछें । अगर आपको निश्चित रूप से कोई शिकायत है कि अमुक आदमी को नहीं लिया गया तो उसके लिए आप पूछें ताकि उस शिकायत को भी दूर किया जा सके ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जीवराज ।

नीम का थाना से उदयपुरवाटी जाने वाली पक्की सड़क का निर्माण

५१. **श्री जीवराज** (गुढा) : क्या मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) नीम का थाना से उदयपुरवाटी जाने वाली पक्की सड़क का निर्माण कब तक हो जावेगा ?

(ख) क्या उसके लिए कोई ठेका दिये जाने की तजवीज़ है ?

(ग) यदि हां, तो कब तक उस कार्य के पूर्ण होने की आशा है ।

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (क) आशा है तृतीय योजना काल में ।

(ख) जी हां ।

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

(ग) तृतीय योजना काल में।

श्री जीवराज : आपने ठेके की तजवीज थी उसके लिए क्या किया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : दे दिया।

श्री जीवराज : किसको दिया गया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ठेकेदार का नाम मालूम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामानन्द।

चूड़ियों पर बिक्री कर

५२. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या मंत्री, कर विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य में औरतों के पहिनने की चूड़ी पर भी सेल्स टैक्स लगता है ?

(२) क्या सरकार को विदित है कि पड़ौसी राज्यों में; जैसे कि दिल्ली, बम्बई, मध्य-प्रदेश इत्यादि में इस वस्तु पर सेल्स टैक्स नहीं है ?

(३) क्या सरकार चूड़ी पर से सेल्स टैक्स हटाने का इरादा रखती है ?

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) :

(१) यह ठीक है कि कांच की चूड़ियों पर राजस्थान में बिक्री कर लगता है। लेकिन दूसरी किस्म की चूड़ियों पर जो कि लाख और हाथीदांत और टोपाली वगैरह से बनती हैं कोई टैक्स नहीं लगता है, बशर्ते कि बेचनेवाले ने १०) रु० सालाना फीस जमा कर मुक्ति प्रमाण पत्र हासिल कर लिया हो।

(२) माननीय सदस्य को बराय इत्तला अर्ज है कि दिल्ली राज्य में हर किस्म की चूड़ियों पर सेल्स टैक्स लगता है। गुजरात राज्य (गुजरात, बम्बई राज्य) में कांच और हाथी दांत की चूड़ियों पर, जिन पर कोई सजावट का काम नहीं किया गया हो टैक्स नहीं लगता है, लेकिन और दूसरी किस्म की चूड़ियों पर टैक्स लगता है।

मध्य प्रदेश में कांच और लाख की चूड़ियों को छोड़ कर हर दूसरी किस्म की चूड़ियों पर टैक्स लगता है।

(३) कोई ऐसा अब तक सवाल सरकार के जेर गौर नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार इस पर विचार करने के लिए तैयार है ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं इसका जवाब दे चुका हूं। अब तक कोई ख्याल नहीं है।

हो सकता है डिस्कशन्स हो रहे हैं उसके दौरान में सरकार की राय बन जाए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हरिराम।

तिजारा तहसील में भाखराकी बिजली

५३. **श्री हरिराम** (तिजारा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 7

(श्री हरिराम)

(१) क्या यह सही है कि भाखरा की बिजली को तिजरा सहसील में लाने की योजना है ?

(२) यदि हां, तो क्या यह बिजली की लाइन कोटकासिम तक ले जाने की योजना है ?

(३) इस पूरी योजना से कुल कितने गांवों को बिजली मिल पायेगी ?

(४) यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) :

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) इस समय केवल तीन गांवों को बिजली मिल सकेगी।

(४) इस कार्य को १९६२ तक पूरा करने की संभावना है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : जिन गांवों को बिजली मिलेगी उनके नाम कृपया बतावें ?

श्री हरिश्चन्द्र : कोटकासिम, शाहबाद और तिजारा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इतने ही गांवों को चुनने में क्या मसलात है ?

श्री हरिश्चन्द्र : कोई मसलात नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन्हीं गांवों को क्यों चुना गया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : भाखरा से जो लाइन आती है और जहां पर पंजाब और अपनी सीमा मिलती है उसके अन्दर बोर्डर एग्रीमेंट पंजाब और हमारे बीच हुआ है उसके अनुसार उनको बिजली मिलेगी।

एक माननीय सदस्य : क्या यह........

श्री अध्यक्ष : श्री हरिराम ! प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

श्री हरिराम : क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि बाकी गांवों को बिजली क्यों नहीं आ रही है जब भाखरा की बिजली चौतरफ आ रही है ? बाकी गांवों में नहीं लाने का क्या कारण है, यह बताने का कष्ट करें ?

श्री हरिश्चन्द्र : अर्थ-अभाव के कारण।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या माननीय मंत्री महोदय बतावेंगे कि ये गांव जिनमें बिजली लाई जा रही है सीधे एक लाइन में हैं या नहीं ? क्या यह वास्तविकता नहीं है कि एक गांव इधर है और दूसरा उधर है ?

श्री अध्यक्ष : आप स्पष्ट ही बतला दें कि आप क्या चाहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ग्राम जीवाना को सीधी लाइन से हटा कर एक विशेष लाइन से ले जावें।........

श्री हरिश्चन्द्र : लोड के अनुसार चलते हैं, यह जरूरी नहीं है की सीधा ही हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मंत्री महोदय मेरा प्रश्न ठीक प्रकार से नहीं समझ पाये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय संभवत: यह कहना चाहते हैं कि उन गांवों को लिया गया है जो लोड के अनुसार लिये जाते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या माननीय मंत्री यह कह सकते हैं कि लोड के आधार पर गांव चुने गये हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां।

प्रश्न संख्या ४४

श्री अध्यक्ष :

श्री सम्पतलाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४५

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास

नगरपालिका, बीकानेर के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

४७. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या स्वायत शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि फरवरी ६२ में बीकानेर म्युनिसिपेलिटी के कर्मचारियों ने कोई हड़ताल की थी ?

(२) यदि हां, तो वह हड़ताल किन किन मांगों को लेकर की गई थी ?

(३) क्या प्रशासक ने उन की मांगों की पूर्ति की सिफारिश सरकार से की थी ?

यदि हां, तो सरकार ने उसे क्यों नहीं मान्य किया ?

(४) क्या यह सत्य है कि हड़तालियों की सरकार ने सजा दी तथा जेल में मारपीट की गई ?

उप-मंत्री-स्वायत्त शासन : (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां। जनवरी–फरवरी, १९६२ में तारीख २७. १. ६२ से २०. २. ६२ तक हड़ताल की थी।

(२) मांगों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) प्रशासक ने विशेषतया ग्रेड रिवाइज़ करने के लिए ही निर्देशक, स्थानीय निकाय से निवेदन किया था जिस पर अब सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(४) हड़तालियों के विरुद्ध सिर्फ कानूनी कार्यवाही की गई थी जिसके परिणामस्वरूप अदालत द्वारा उनको सजा दी गई। जेल में कोई मारपीट नहीं की गई।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

Page No 9

श्री मुरलीधर व्यास : प्रश्न(३)के उत्तर में कहा है कि जो मांग थी वह विचाराधीन है। क्या उस समय हड़ताल का समय था वहां से जो एडमिनिस्ट्रेटर ने सिफारिश की थी तो उस समय सरकार ने यह क्यों नहीं लिख कर फौरन भेज दिया कि यह सरकार के विचाराधीन है; ताकि महीने भर तक हड़ताल चालू नहीं रहती और लोगों को दिक्कत नहीं होती।

श्री दौलतराम सारण : एडमिनिस्ट्रेटर ने लिखा और उसके बारे में अधिक जानकारी सरकार को चाहिये थी वह जानकारी मंगाई गई और उसके बाद में जब जानकारी दी गई तो फिर से सूचना दी।

श्री मुरलीधर व्यास : आपकी ओर से २५ दिन तक हड़तालियों को दिक्कत उठानी पड़ी। आपने क्या सूचना दी ? हम निर्णय कर रहे हैं और लोग जेलों में पड़े हैं; इसका क्या कारण था ?

श्री दौलतराम सारण : उन्होंने जो हड़ताल की थी वह गैर-कानूनी तौर से की और पहले जो हड़ताल की थी उसमें चेयरमैन के साथ कर्मचारियों का एग्रीमेंट हुआ था उसमें कुछ शर्तें थीं कि उन शर्तों को सरकार के पास भेज देंगे; ताकि बजट में प्रोविज़न रख देंगे। न तो सरकार को लिखा, न कोई तय किया; इसलिये जल्दी में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता।

श्री मुरलीधर व्यास : आप कहते हैं कि हड़ताल गैर-कानूनी थी। आप किस आधार पर कहते हैं कि वह गैर-कानूनी तरीके पर थी। जब उनकी टॉक फेल हो जाती है तो हड़ताल कर सकते हैं।

श्री दौलतराम सारण : नगरपालिका अधिनियम के अनुसार एक महीने का नोटिस देना चाहिए था।

श्री मुरलीधर व्यास : नोटिस तो दिया था। जब आपस में बातचीत हो रही हो और टॉक फेल हो जाती हो तो उसमें नोटिस की कोई बात नहीं रहती। नोटिस पहले दिया गया था। तीन वर्ष पहले भी इसी मुद्दे पर हड़ताल हुई थी। फिर आम लोगों को दिक्कत होगी।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था कि नगरपालिका के चेयरमैन और वहां के कर्मचारियों के बीच में आपस में जो एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट को सरकार के सामने पेश नहीं किया। बिना प्रोपोज़ल के सरकार क्या एक्शन लेती ? जब सरकार के पास यह मामला आया तो एडमिनिस्ट्रेटर के लैटर पर सरकार ने जानकारी चाही और उसका जवाब आया और अब जल्दी ही फैसला कर दिया जावेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : नगरपालिका के प्रेसीडेन्ट कोई चीज आपके पास नहीं भेजें और फिर वे लोग हड़ताल करें तो दो दिन के अन्दर सारी चीज मंगाई जा सकती है। अब तो बीकानेर में नगरपालिका के अध्यक्ष नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो उनसे शिफारिश मिलने के बाद क्यों नहीं तुरन्त कदम उठाया गया ?

श्री दौलतराम सारण : मैं उत्तर निवेदन कर चुका हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : प्रेसिडेन्ट ने रिपोर्ट नहीं भेजी तो अब किस आधार पर कह रहे हैं ?

Page No 10

श्री दौलतराम सारण : एडमिनिस्ट्रेटर के लैटर पर।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : जो म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और ५ रुपया ग्रेड इन्क्रीमेंट का दिया है वह दूसरी जगह भी स्वीकार कर लिया गया है?

श्री दौलतराम सारण : यह अलग प्रश्न है, अलग से पूछें तो उत्तर दिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : आपने तो दूसरी सारी जगहों के लिये पूछ लिया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : बहुत जरूरी है पर इससे रिलेवेन्ट नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि एडमिनिस्ट्रेटर ने कर्मचारियों की यूनियन के अधिकारियों को आश्वासन दिया था कि १२ तारीख से जो वे भूख हड़ताल कर रहे थे उसको एक हफ्ता के लिये रोक दें तो २० तारीख को उन्होंने रिकमन्डेशन्स भेज दी थीं; तो क्या मन्त्री महोदय यह उचित नहीं समझते थे कि एडमिनिस्ट्रेटर ने ऐसी रिपोर्ट पेश की तो फौरन कदम उठाते?

श्री दौलतराम सारण : २० तारीख को उनका पत्र आया था, बाद में उनको लिखा तो उनका दूसरा पत्र २३.२.६२ को आया। मैंने कहा कि वह मामला विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री मुरलीधर व्यास : कब तक हो जायगा?

श्री दौलतराम सारण : शीघ्र हो जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि जिनको सजाएं दी गईं, सिम्पल इन्प्रिज़नमेंट दी थी उनसे जेल में मेहनत का काम लिया गया, उनके साथ........

श्री दौलतराम सारण : यह जो कहा गया है........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़! हर एक का उत्तर न दें; कोई रिलेवेन्ट होता है, कोई रिलेवेन्ट नहीं होता है।

प्रश्न समाप्त हुए।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सही है कि मार-पीट से काम लिया?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर प्लीज़!!

प्रश्न समाप्त हुए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या यह सही है कि....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर प्लीज़!! अब कोई प्रश्न नहीं पूछा जावेगा। प्रश्न समाप्त हुए।

Page No 11

(११. २५ म. पू.)

कार्य-सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष, मैं कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन को स्वीकार करे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

आयव्ययक, १९६२-६३ पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जो वित्त मन्त्री........

श्री अध्यक्ष : आप बोल रहे हैं क्या ?

श्री मुरलीधर व्यास : जी हां।

श्री अध्यक्ष : मैं कहूँगा तब बोलेंगे न।

कल श्री मोहनलाल बोल रहे थे।

श्री मुरलीधर व्यास : वे नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ?

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री नारायणसिंह।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, हमारी नई विधान सभा का नया बजट हमारे वित मन्त्री ने बड़े ही पुख्ता शब्दों में रखा है और कई माकूल बातें कही हैं और उनसे कई बातों से कुछ ऐसा इशारा मिलता है कि वित्तीय मामलों में कुछ नये ढंग से जहां चला जायगा, कुछ नई बातें आयेंगी और पुरानी खराबियां खत्म होंगी। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे विषय भी हमारे सामने उपस्थित हुए हैं जिनसे चिन्ता का विषय हमारे सामने आया है और हमें यह सोचने का मौका मिला कि पुरानी अर्थ व्यवस्था जिस प्रकार से चली आ रही है वह कुछ ढिलमिल है, कुछ लोच खाती हुई चल रही है, सही ढंग से नहीं चल रही है। उन्होंने इस ओर भी इशारा एक-दो बार किया है कि सेंट्रल टैक्सेज़ और ग्रान्ट-इन-एड द्वारा कुछ स्थितियां यहां की सम्हाली गई हैं, अन्यथा यह स्थिति सुधारने में काफी गड़बड़ी होती और उन्होंने जो भाषण दिया उसके अंग्रेजी अनुवाद में से ये शब्द उद्धृत कर दूं तो यह चीज स्पष्ट होती है :

"It will be noticed that substantial improvements occurred only in the share of Central Taxes and Central grant-in-aid, while major short falls were in LandRe venue and Extraordinary Receipts........"

और इसके अलावा भी एक और जगह ये वाक्य कहे गये हैं कि :

Compared to the revised estimates

(श्री नारायणसिंह)

for 1961·62, imporvements are expected mainly in the share of Central Taxes and in the grants-in-aid from the Centre.

इस ओर उन्होंने खास तौर से इशारा किया। कुछ अपने भाषण में नॉन प्लान एक्सपेन्डीचर की ओर भी काफी इशारा किया है कि जहां नॉन प्लान एक्सपेन्डीचर बढ़ा है वहां हमारा प्लान्ड एक्सपेन्डीचर है उसमें इतना इजाफा नहीं हुआ है और इसमें वाकई चिन्तास्पद स्थिति की ओर हमें संकेत मिला है। इन सब बातों को देखते हुए हमें चिन्तापूर्वक कुछ बातों पर विचार करना पड़ता है। राजकीय अर्थ का क्या रुख है, इसको देखने के लिए मैंने कुछ बजट स्टडी की और जो कई फीगर्स मेरे सामने आये उनसे इस चीज को समझने की कोशिश की। सालों से बनते हुए बजटों का जो रुख हमारे सामने आता है उससे यह स्पष्ट होता है कि रेवेन्यू रिसीट्स का जो इन्डेक्स ५१-५२ का १०० है उससे वह आगे जाकर ६१-६२ में २९७ तक पहुँचा और ६२-६३ में ३८३ इन्डेक्स में संकेत किया जाता है।

इसके अलावा रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर का भी जहां ५१-५२ में १०० है उसका इन्डेक्स ३०६ हो गया है ६१ में ६२ में और ६२-६३ ३५७ की ओर इशारा किया जाता है। इससे एक बात स्पष्ट मालूम पड़ती है कि जहां हमारी रेवेन्यू रिसीट्स का इन्डेक्स है वहां रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ी हैं, खर्चा बढ़ा है; २९ और रेवेन्यू रिसीटस हैं वे खर्च से कम रह जाती हैं।

डेवलपमेंट एक्सपेन्डीचर के बारे में यही लिखा गया है इसमें कि डेवलपमेंट एक्सपेन्डीचर ४२.५ सन् ५१-५२ में था वहां ६१-६२ में ५७.४ की ओर इशारा है। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेन्डीचर ५७,५ था वहां ४२.६ होता है। तो डेवलपमेंट एक्सपेन्डीचर का रूख है वह हमारे सामने है और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेन्डीचर में भी उन्होंने संकेत किया है। वह साफ है, फिर भी हमें वाकई इस अनियोजित एक्सपेन्डीचर के ऊपर पूरे जागरूक रहने की आवश्यकता है। लेकिन इसकी स्थिति भी जब हम देखते हैं तो जो टोटल एक्सपेन्डीचर ९,९१,३३,००० सन् १९५१-५२ में थी और उससे बढ़ कर २६,२२,५०,००० हुआ है इसमें यदि हम जो डेट सर्विसेज़ के, फेमीन के आंकड़े मद्देनजर रखें तो डेट सर्विसेज़ और फेमीन को मिला कर ५१-५२ में ७४.२१ लाख रहा है और अब ६२-६३ में ६१८.१० लाख के फीगर तक बनते हैं। इसका मतलब जो टोटल का इन्डेक्स है उसमें १०० से २६५ का अधिक इन्डेक्स बनता है और डेट सर्विसेज़ और फेमीन का इन्डेक्स निकाला जाय तो जहां ५१-५२ में १०० है तो वहां ६०८ बनता है; ५०८ का डिफरेंस आता है। इस दृष्टि से यदि विचार करें तो इस नॉन डेवलपमेन्ट एक्सपेन्डीचर में जो अधिक भारी चीज मालूम पड़ती है वह डेट सर्विसेज और फेमीन है। यह हमें निर्विवाद रूप से स्वीकार करना पड़ेगा कि नॉन-डेवलपमेन्ट एक्सपेन्डीचर में डेट सर्विसेज़ भारी तुलती हैं और जो एमर्जेन्सीज, फेमीन इत्यादि की हैं खड़ी हो जाती हैं उस स्थिति में अधिक खर्चा करना पड़ता है और राजस्थान जैसे प्रान्त में जहां कि अनिश्चित रेनफॉल की

(श्री नारायणसिंह)

स्थिति बनी रहती है वहां दूसरे-तीसरे साल कुरिया तो तीसरे, चौथे साल अकाल की स्थिति बनी रहती है। उस हालत में फेमीन में अधिक एक्सपेन्डीचर हो जाता है। नॉन डेवलपमेन्ट एक्सपेन्डीचर भी बड़ा जरूरी है और उसमें कुछ ऐसे कार्य भी जन-साधारण के उपयोग के लिए होते हैं जो बचाये नहीं जा सकते। और जिसके कारण वह एक्सपेन्डीचर बढ़ता है। फिर भी जो हमें वित्त मंत्री महोदय ने नॉन डेवलपमेन्ट एक्सपेन्डीचर की ओर इशारा किया है उसको जहननशीन करना है और यह देख लेना है कि नॉन डेवलपमेन्ट एक्सपेन्डीचर इतना न बढ़े जिससे हमारी जो नियोजित अर्थ-व्यवस्था है इन योजनाओं के द्वारा करना चाहते हैं उसमें कोई फर्क आ जाय।

मैं इस बजट को तीन, चार विचार शैलियों में बांट कर इसका विवेचन करना ठीक समझता हूं। कुछ तो हमें यह देखना पड़ेगा कि बजट को सालो साल बनाते हुए उसका रूप क्या है और दूसरी बात यह रहेगी कि सुदृढ़ अर्थ व्यवस्था की ओर दूसरे राज्यों के साथ तुलनात्मक क्या चित्र बनाता है और तीसरा कर पद्धति क्या है; जिसके अनुसार रिसोर्सेज़ बढ़े हैं और करों के अलावा साधनों की समृद्धि के क्या उपाय हमने सोचे हैं। अगर हम इस प्रकार से बजट की जांच करें तो हमें कुछ आशा की झलक तब तब मालूम पड़ सकती है जब जब इस त्वरित गति से चलते हुए विकासोन्मुख हमारे कदम सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इस बात की तसल्ली दिला दें।

मैं सालो साल बनते बजट के रूप के बारे में कुछ फीगर्स पेश कर चुका हूं। जो दूसरे राज्यों के मुकाबले हमारी तुलनात्मक स्थिति बनती है उसमें मैंने देखा है कि पर-केपिटा टैक्स रेवेन्यू में जो सेन्ट्रल टैक्सेज का शेयर हमारा है उसमें करीब सारे १५ राज्यों में से हम १३ वें नम्बर पर आते हैं। यह उन फीगर्स को देखने से साफ प्रतीत होगा। और पर-केपिटा टैक्सेज में हम सबसे आखिर में जाते हैं और पर-केपिटा एक्सपेन्डीचर में १० वें नम्बर पर स्थिति रहती है। इस दृष्टि से यह स्पष्ट हो जाता है कि खर्चा हमारा जो चल रहा है वह आज की स्थिति को देखते हुए काफी ठीक ढंग से चल रहा है और उसके बावजूद भी केन्द्र पर जितना भार डालना आवश्यक है उतना ही डालने की फिक्र कर रही है। जब केन्द्र पर भार डालने की बात हम सोचते हैं तो इससे स्पष्ट है कि हमारा राज्य और हमारे राज्य की सरकार जागरूक प्रतीत होती है कि यदि अनर्गल भार केन्द्र पर डाला जायेगा तो उनको जो साधन उसके लिए जुटाने पड़ेंगे उसका प्रभाव सारे देश के करदाताओं पर पड़ेगा। इस दृष्टि से यदि हम केन्द्र पर कम भार डालते हैं तो उस चीज के लिए हमें संतोष ही मानना चाहिये। तीसरी चीज इसमें यह भी मालूम पड़ जाती है कि पर-केपिटा टैक्स बढ़ाने में पर-केपिटा एक्सपेन्डीचर के बराबर भी मुस्तैदी रखें तो सारे राज्यों में हमारा १० वां नम्बर बनने की ही स्थिति वहां भी रहेगी। तो यह मानना पड़ेगा कि जो यहां की कर प्रगति रही है उस और स्थानीय निम्न आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए ही, आर्थिक हैसियत को मद्देनजर रखते हुए ही सरकार ने विचारशील कदम उठाया है।

उसके साथ हमारी डेट पोज़ीशन पर भी

Page No 14

(श्री नारायणसिंह)

दृष्टि जाती है। केपिटल अकाउन्ट की नेट स्थिति के नक्शे को देखें तो ५१-५२ में १०३.०५ लाख की स्थिति रहती है और उसके बाद ५५-५६ में ६०-६१ तक ४४६.८० लाख तक वह बढ़ जाता है। ६०-६१ से ६२ तक ६८७.३० लाख का बढ़ावा है। इन फीगर्स को जब हम देखें तो जरूर इसमें कुछ चिंता की आवश्यकता पड़ जाती है और जरूर सोचना पड़ता है और कॉम्प्लीसेन्सी में नहीं रह सकते हैं। ५५-५६ से लगाकर ६०-६१ तक ४४६.८० लाख उसमें बढ़ा है तो हमें सोचना चाहिये कि ६०-६१ में जाकर ६८०.८० लाख एकदम बढ़ गया है तो वह किन कारणों से बढ़ गया है।

अब इसमें ६२-६३ की ओर जो इशारा किया गया है उससे हमारी डेट (Debt) पोज़ीशन ३,०५२.४० लाख नीचे गिरने की ओर इशारा है। अगर हम इस बात को पूरी तरह से जो फीगर्स दिये हैं उनके अनुकूल प्रमाणित कर सकें तो वाकई मैं कहूंगा वित्तीय व्यवस्था के अन्दर इजाफा होगा, सुधार होगा। लेकिन कुछ ऐसा देखा जाता है जो फीगर्स शुरू में बनते हैं वे आखिर तक कायम नहीं रहते उनमें लोच आ जाती है। इसलिए मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि साधारणतया जिस प्रकार से सभी जगह के वित्त मंत्री महोदय का एक दस्तूर रहता है, शुरू शुरू में कम या ज्यादा फीगर्स बता देते हैं लेकिन बाद में सप्लीमेन्टरी डिमान्ड्स में वे सब साफ हो जाते हैं; ऐसी चीज नहीं बननी चाहिये। अगर कही गई स्थिति ही बनी रखी गई तो नये साल में हमारे वित्त मंत्री महोदय मुबारिकबाद के पात्र होंगे।

पब्लिक डेट (debt) के बारे में इसमें कुछ जिक्र है। इसमें जो आंकड़े बताये गये हैं उनके अनुसार स्थिति को मैंने समझने की कोशिश की है। पब्लिक डेट ५७-५८ के अन्दर एक अरब के करीब है। इस तरह से इन रकमात की पोजीशन अच्छी है और वही करीब करीब आज भी बनी हुई है। सन् ६१-६२ में वही साठ करोड़ की रकमात की पोज़ीशन है जो उत्तम नजर आ रही है। ५७-५८ के अन्दर जरूर पब्लिक डेट की स्थिति काफी नीचे दायरे में पहुंची हुई थी, उसके साथ साथ रकमात माकूल थी। अगर हम इस ओर दृष्टि रखते हैं तो इसमें ज्यादा चिन्ता का विषय नहीं रहता। आज की विकासोन्मुख स्थिति में जिस वक्त हमें ताकीद है, हमारी विकास की गति में रुकावट पैदा न हो, जब कि हमें न केवल फंक्शनल डेवलपमेन्ट करना है; बल्कि दूसरे समृद्धिशाली अर्थ व्यवस्था वाले देशों से हमारा सन्तुलन बैठाना है वैसी स्थिति में स्ट्रक्चरल डेवलपमेन्ट का ख्याल करके आमूलचूल परिवर्तन हमारे यहां की अर्थ व्यवस्था में लाना है तो हमें इन संकटों की तरफ ध्यान देना होगा और जो कुछ भी फाइनेन्शियल लोच है उसको हमें कुछ स्वीकार करना पड़ेगा और डेट पोज़ीशन की तरफ भी ठंडी नजर रखनी पड़ेगी। आज केवल जिस प्रकार से एक विरोधी दल के माननीय सदस्य ने और स्वतंत्र पार्टी के नेता महोदय ने कहा था कि "कट योवर कोट अकोर्डिंग टू योर क्लोथ"। इसका जवाब दूसरे माननीय सदस्यों ने दिया भी था लेकिन मैं यह कहूंगा कि आज के इस विकासोन्मुख युग में जब कि हमें यह ताकीद है कि हमें दूसरे देशों के बराबर स्थिति कायम करनी है उस

(श्री नारायणसिंह)

समय 'Cut your Coat according to the cloth'; इस सिद्धान्त पर कायम नहीं रह सकते । अगर हमारा शरीर बढ़ रहा है और हमारे पास कपड़ा नहीं है तो we shall borrow the cloth for the coat but we shall be very careful in the repayment of what we borrow. अगर हम यह चीज कर सकते हैं तो हमें "cut your coat according to the cloth" पर भी जम जाने की आवश्यकता नहीं। यह वाक्य जो है वह केवल निजी प्रयोग के लिये है, व्यक्तिगत प्रयास है; उसके लिये कि वह अपने घर को देख कर चले । हमें भी अपने घर को जरूर देखना है । लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि कितने रिसोर्सेज़ पोटेन्शियल हमारे देश में हम कायम कर सकते हैं । वह रिसोर्सेज़ पोटेन्शियल घट तो नहीं हो रहा, यह हमें देखना चाहिये। मसानी महोदय ने जो स्वतंत्र पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं एक दफा पार्लियामेंट में कहा था कि हमें कन्यूमर गुड्स के उत्पादन की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिये। उन्होंने वालेन्टियरी loans की तरफ भी इशारा किया था और दूसरी चीजों के बारे में उनका कहना था कि निजी प्रयास से जिस प्रकार चल रहा है उसी प्रकार चलने दें। लेकिन आज के इस युग में जहां हम एक मिश्रित इकोनोमी को लेकर चल रहे हैं, वस्तुस्थिति को देखते हुए और इस भूमिका में कि हम समाजवादी समाज की रचना करने जा रहे हैं हम केवल निजी प्रयासों को यथावत स्थिति में कायम रखते हुए आगे नहीं बढ़ सकते । हमें जो सारी दुनिया के पहलू दबाव दे रहे हैं उनकी ओर भी हमें दृष्टि फैंकनी पड़ेगी । हमें साधारण स्तर को भी ऊंचा उठाने की तरफ माकूल प्रयास करना पड़ेगा । जिस वक्त मसानी महोदय ने कन्ज़्यूमर गुड्स के उत्पादन के बारे में बात कही थी और ताना दिया उस समय केन्द्र के योजना मंत्री महोदय ने बड़ा माकूल जवाब दिया था : 'We shall not eat steel.' हमें कम से कम ऐसी इन्डस्ट्रीज़, बुनियादी इन्डस्ट्रीज़ कायम करनी होंगी जिससे हमारी अर्थ व्यवस्था का ऐसा प्रसार हो जाय जिससे हम समृद्ध हों । पिछड़ी इकोनोमी में ऐसी स्थिति नहीं बनती कि हम पहले कन्ज़्यूमर गुड्स के बारे में कदम उठायें । आज हमें दूसरे देशों की प्रगति की ओर भी झांकना पड़ेगा । यदि हम उस ओर ध्यान नहीं देते हैं तो हम पिछड़ जायेंगे और हम कर्जदारी में उत्तरोत्तर बढ़ते जायेंगे, अगर हमने बेसिक इन्डस्ट्रीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया तो । अगर हम रिसोर्सेज़ पोटेन्शियल को समृद्ध बना देते हैं तो वह भी स्थिति आ सकती है जिससे एक दिन कन्ज़्यूमर गुड्स के बारे में जिस प्रकार मांग की जाती है उस ओर बढ़ जायं । रूस के अन्दर भी कन्ज़्यूमर गुड्स को प्लान्ड इकॉनोमी के शुरू शुरू में स्थान नहीं दिया गया । चतुर प्लानिंग पिछड़ी इकॉनोमी में पहले पहले कन्ज़्यूमर गुड्स से दूर रहता है । जहां जहां भी विकास की ओर कदम उठाये गये हैं कन्ज़्यूमर गुड्स को दूसरी स्थिति दी गई है ।

इसी प्रकार से उन्होंने वालेन्टियरी सेविंग्ज़ के बारे में भी कहा था; उस समय के केन्द्रीय सरकार के प्लानिंग मिनिस्टर महोदय ने इसका जिक्र किया था और कहा था कि आज हम जब विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं उस

Page No 16

(श्री नारायणसिंह)

हालत में केवल वालेन्टियरी सेविंग्स पर आधारित नहीं रह सकते, आज के प्रगतिशील देश इसको स्वीकार नहीं कर सकते। अगर हम वालेन्टियरी सेविंग्स पर ही आधारित रहते हैं तो हमारी आर्थिक स्थिति पिछड़ी हुई रह जायेगी। हम जब कि बैकवर्ड इकोनोमी में हैं वैसी हालत में कन्ज्यूमर गुड्स के बारे में हम रुक नहीं सकते और न वालेन्टियरी सेविंग्स द्वारा ही हमारी प्रगति का औचित्य अटकाव कर सकेगा। आज जब कि हम देश की आर्थिक व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन लाने जा रहे हैं उस समय केवल इन सेविंग्स का इन्तजार करते रहें जिससे हमारी अर्थ व्यवस्था में इजाफा पड़ेगा तो हम निश्चय ही खयाली पुलाव पका रहे हैं।

इसका मतलब यह नहीं कि सेविंग की दिशा में पब्लिक डेट और स्माल सेविंग की दिशा में कदम ही न उठावें जिससे वालेन्टरिली सेविंग भी आ सके। परन्तु यह सिद्धान्त जो स्वतन्त्र पार्टी ध्रुव मान कर चलती है आज की स्थिति में पूरी तरह से बैठ नहीं पाता।

मैं थोड़ा आज की कर-पद्धति पर कहना चाहूँगा। इस प्रगतिशील युग में जब कि हम एक कल्याणकारी और समाजवादी राज्य के निर्माण में प्रयत्नशील हैं टैक्सेशन का स्ट्रक्चर हमें ऐसा बनाना पड़ेगा कि जिसमें डिस्पेरिटी न होने पावे, डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ वैल्थ बराबर हो और इसके साथ साथ सारी इन्कम में कुछ ऐसी स्वस्थ परम्पराएं कायम हों जिससे वह माकूल तौर से आगे बढ़ सके और निर्यात की स्थिति भी ऐसी बने कि जिससे निर्यात से हमें पूरी फोरिन एक्सचेन्ज मिल सके। जिन वस्तुओं से निर्यात बढ़ता हो उन पर हमें या तो टैक्स फ्री करना होगा या टैक्स कम लेना होगा। तो इस सिद्धान्त को हमें इस बारे में लेकर चलना होगा।

यह मैं कह चुका हूँ कि राजस्थान में जो टैक्स लगाये गये हैं उस दृष्टि से मैं निवेदन कर सकता हूं और भी कि आज हम लास्ट हैं इस दृष्टि से टैक्स लगाने वालों में; सारे १५ राज्यों में आखिरी दर्जे पर हैं।

ये टैक्स यहां की जनता की आर्थिक स्थिति का ख्याल किये बिना लगा दिये गये हैं, ऐसा तो नहीं है; पर फिर भी जो मौलिक सिद्धान्त हैं उनको हम साफ ध्यान में रख कर आगे नहीं बढ़े हैं। साधारणतया बजट के महीने, दो महिने पहले विभागीय सलाह मशविरे के बाद कुछ चीजों पर से कर हटा दिया और कुछ पर लगा दिया। इस तरह के तरीके से हम आगे बढ़े हैं। पर इन टैक्सों को कैसे लगाना चाहिये, इनका किन स्थितियों पर क्या असर पड़ेगा; इसका शायद पूर्ण विचार नहीं किया। इसके लिये मैंने विगत विधान सभा के बजट सत्र में भी कहा था और उसी को पुनः दोहराकर कहने में आज भी मैं कोई आपत्ति नहीं समझता कि हमें बजट बनाने से पहले साधारण जनता के जितने तबके हैं उनकी सामान्य शक्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिये कि किस प्रकार के टैक्स का इन पर क्या असर पड़ सकता है। इसके बाद नीति का निर्धारण करना चाहिये। यह वैज्ञानिक ढंग है। अगर इस तरह से स्टडी करके हम कर लगावेंगे तो जनता के उपालम्भ के हम या तो पात्र कभी

(श्री नारायणसिंह)

नहीं बनेंगे या कुछ लाजिम तौर पर कर लगाने भी पड़े तो कम उपालम्भ के पात्र होंगे। दो, चार दिनों में शासन में बैठे लोगों से सलाह मशविरा करके कुछ चीजों पर कर लगा देने से ही हम काफी उपालम्भ के पात्र बनते हैं।

इसके साथ ही हमें यह सोचना होगा कि जो टैक्स डाइरेक्ट अथवा इनडाइरेक्ट हम लगाते हैं उनसे किस प्रकार का आर्थिक ग्रुप हमारे देश में बनेगा और जो बनेगा वह स्वस्थ बनेगा या नहीं या उससे हमारे निर्यात में तो बाधा नहीं आयेगी। अगर इन बातों को ध्यान में रख कर हम टैक्स का निर्धारण करते हैं तो हमारे टैक्स गलत रास्ते पर नहीं जा सकते।

अब हमने जो टैक्स लगाने का प्रयास किया है वह इनडाइरेक्ट की तरफ ही अधिक किया है। डाइरेक्ट से इन डाइरेक्ट टैक्स कुछ छिपे माने में बड़े खतरनाक होते हैं। कुछ वित्तीय स्टेटिस्टिक्स की बात मैं कह रहा हूं। कलकत्ते में अलग अलग इन्कम की सेम्पल सर्वे की एक राष्ट्रीय संस्था है। उसकी एक रिपोर्ट है। मैं पहले उसे कोट भी कर चुका हूँ। उन्होंने अलग तबकों की इन्कम की स्टेडी की है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इनडाइरेक्ट टैक्स का असर नीचे के तबके पर अत्यधिक पड़ता है। मुझे ध्यान है, मैंने पहले भी यह बात कही थी जिनकी आय १०० से २०० तक है उन पर प्रतिशत टैक्स का भार उन्होंने बताया है; चार पड़ता है जब कि ५०० से ऊपर की आय वालों पर केवल एक प्रतिशत पड़ता है। तो इनडाइरेक्ट टैक्स लगाते वक्त अधिक सावधानी बरतनी चाहिये।

पर जो नये टैक्स लगे हैं उनके बारे में स्पष्टतया कहूं तो और के बारे में तो ऐतराज नहीं, पर एक तो दालों पर और दूसरा जानवरों पर जो लगाया गया है इससे मुझे काफी हैरानी हुई। आज हमारे राजस्थान के फूड प्रोडक्शन के फिगर देखे जावें तो मालूम होगा कि जहां हमने ५५-५६ का सौ अंक माना वहां ६०-६१ तक १२८. ८६ आता है सीरियल में और पल्सेज़ के प्रोडक्शन में १४४.१६ से १५२. ०२ आता है। तो आज मैंने देखा कि पल्सेज़ में काफी प्रगति हुई, औरों में नहीं हुई। अब ये पल्सेज़ साधारण कृषक के नित्य उपयोग की चीज है तथा साथ ही हमारे प्लानर्स ने प्रत्येक व्यक्ति के खाद्य के विषय में एक वैज्ञानिक मापदण्ड बनाया हुआ है कि इतनी सीरियल और पल्सेज़ एक व्यक्ति के खाद्य में सम्मिलित होनी चाहिये तो आज हम ऐसी चीजों पर भी टैक्स लगा देंगे तो मैं नहीं समझता कि क्या यह असल जरूरत पर कर नहीं कहलावेगा।

इसके अलावा जो जानवरों पर टैक्स लगाया गया है उससे तो मुझे डर है कि आज यदि हम इस भारी संघर्ष के बाद ८९ की तादाद में ही यहां चुन कर आये हैं तो शायद फिर आगे ४०-४५ तक न रह जावें।

(१२.०० मध्यान्ह)

क्योंकि मुझे मालूम है मेरे ही चुनावों में कई जगह पर मुझे इन बातों का सामना करना पड़ा कि वहां के लोगों ने कहा कि यह सरकार तो आगे जाकर चूल्हों पर टैक्स लगा देगी जानवरों पर भी लगा देगी। तो आज यदि पहले ही सत्र में हम जानवरों पर टैक्स लगा देते हैं तो वह सीधा यही कहेंगे कि जो

Page No 18

(श्री नारायणसिंह)

हमने कहा था , यह जानवरों पर टैक्स आ गया। यह मवेशी इत्यादि का बिक्री और व्यापार कोई इतना सुगठित व्यापार नहीं है कि हर एक कृषक इसका हिसाब रखे। हर एक किसान अपने अपने तरीके से जब आवश्यकता होती है तो अपने मवेशी खरीद लेता है या बेच देता है। आज पहले से ही उनको रेवेन्यू और पुलिस की तरफ के दबाव अखरते हैं तो फिर एक बिक्री-कर-प्रशासन का दबाव तो उन्हें और भी अधिक अखरने लगेगा। ऐसी स्थिति में हमको उन्हें इस दबाव से बचाना चाहिए। न तो वे इतना हिसाब और आंकड़े रख सकेंगे कि एक एक मवेशी की बिक्री के आंकड़े दें सकें और सेल्स टैक्स से छुटकारा पा सकें; बल्कि उनके अशिक्षित होने की अवस्था में उसका लाभ दूसरे ही लोग लेंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस पर निश्चय दुबारा विचार करें। लेकिन मैं इसकी जरूर हमारे वित मंत्री महोदय को दाद दूंगा कि एक्साइज़ ड्यूटी उन्होंने बढ़ाई है। वह ठीक है कि बजाय प्रोहीबिशन के हम शराब की चीजों पर ज्यादा ड्यूटी बढ़ा दें, यह एक बिल्कुल मानने लायक सिद्धान्त है। इस ओर आपने जो कदम उठाया है उसके लिए मैं अवश्य ही मुबारकबाद दूंगा लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में जो उन्होंने इजाफा किया है उसके लिए मैं केवल इतनी सी चेतावनी उन्हें देना चाहता हूं कि जहां जानवरों पर कर लगा कर उन्होंने अपनी आमदनी बढ़ाई है उससे हमें गांवों में गालियां मिलेंगी; वहां इस इलेक्ट्रिसिटी के इजाफे से शायद हमें शहरों की भी गालियां खानी पड़ेंगी। कम से कम अगर शहरों की गालियां खाने के लिए तैयार हैं तो गांवों की तो हमें गालियां खानी न पड़े ऐसा वित्त मंत्री महोदय को सोचना चाहिए।........

श्री बालकृष्ण कौल (वित मंत्री) : और शराब के पीने वालों की गालियां हमको पड़ेंगी।

एक माननीय सदस्य : वे तो थोड़े ही हैं।

श्री अध्यक्ष : वे तो पीकर कुछ भी कह देंगे। कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री नारायणसिंह : अब टैक्सेशन के ही विषय में दो, चार बातों की ओर और इशारा करना आवश्यक समझता हूं। हम यदि एक नई प्रकार की टैक्सेशन की पद्धति यहां आरम्भ करना चाहते हैं और हम अपने आर्थिक आधारों को नये तरीके से बढ़ाना चाहते हैं तो हमें यह आवश्यक है कि कुछ ऐसे टैक्सेज़ जो पुराने ढंग के हैं और परम्परागत चले आ रहे हैं उनमें भी हमें कुछ परिवर्तन लाना चाहिए। मसलन जो लैण्ड रेवेन्यू है वह एक प्रकार से प्रक्रियात्मक टैक्स है, पुराने ढंग से चला आ रहा है, प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं है। इसके बजाय एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स के बारे में हमारे पहले कृष्णमाचारी, केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने भी इशारा किया था कि आज यह परमावश्यक है कि हमारा यह जो लैण्ड रेवेन्यू आता है उसका हिसाब लगायें तो मालूम होगा कि लैण्ड रेवेन्यू का बजट ५ से ७ करोड़, और ७ से ८ करोड़ और अब जाकर ८ करोड़ से ८.७५ करोड़ का आता है। यह काफी बड़ी

(श्री नारायणसिंह)

धन राशि है । लेकिन हमें एक ऐसी इन्क्वायरी इन्सटीट्यूट करनी चाहिए जो कि इस बात की जांच करे कि इतनी आमदनी जो हमारे लैण्ड रेवेन्यू से आती है जो एक प्रकार से प्रक्रियात्मक कर-पद्धति का नमूना है उसके बजाय एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स स्थापित कर दें कि जो कुछ ऐसी न्यूनतम आय से शुरू हो जो कि सारे कृषक और ग्रामीणों को अखरे नहीं तो वह बिल्कुल सही तरीके का कदम होगा । स्वतन्त्र पार्टियां भी कई वायदे कर आई है कि वे राजस्व बिल्कुल हटा देंगे । यह वास्तव में स्वतन्त्र पार्टी ने जो नारा उठाया मैं समझता हूँ कि हमारे यहां केन्द्र में जो श्री मुरारजी के पहले वित्त मन्त्री थे उन्होंने लैण्ड रेवेन्यू उठा कर एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स की ओर इशारा किया था उसी को शायद उन्होंने पकड़ लिया है, उसी बात को उन्होंने चुनाव के दौरान में प्रकट किया है और दोहराया है । मैं समझता हूँ कि यह बुनियादी तौर पर हमारी और केवल हमारी बात है और हम इसको शीघ्र कार्यान्वित करने का प्रयास करेंगे ।....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, आपके वित्त मन्त्री से पहले डॉक्टर लोहिया ने यह बात कह दी । उसका श्रेय आप लेने की कोशिश न करें ।

श्री नारायणसिंह : अब समय का संकोच है । अब मैं राज्य के साधन-वृद्धि के बारे में कहूँगा । हमारे साधन बढ़ने के लिए मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय भी कहा था कि जिस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था हम बनाना चाहते हैं और जिस प्रकार से समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं उसमें उतरोत्तर बढ़नेवाला जो पब्लिक सैक्टर है उसकी ओर हमारा ध्यान होना चाहिए । अब पब्लिक सेक्टर की ओर जो हमारा प्रयास है उसको देखते हैं तो जरूर मायूस होते हैं । चन्द लाखों की आमदनी वह हमको देता है और इसमें स्टेट ट्रेडिंग ऑफ फूडग्रेन्स भी आ जाता है जो कि कोऑपरेटिव इत्यादि से होता है । इसमें ट्रान्सपोर्ट सबसे बड़ी चीज है और इसी प्रकार के कई स्टेट एन्टरप्राइज़ेज हैं । मैं इस विषय में पहले ही कह चुका हूँ । बन्दोबस्ती मामले में जो आर० ए० एस० और आई० ए० एस० ऑफिसर्स को ही व्यापार पर नियुक्त करते हैं तो यही काफी नहीं होगा । इसके साथ साथ हमें इस प्रकार को कॉमर्शियल सर्विसेज़ का निर्माण करना पड़ेगा कि जिससे निकल कर जो पब्लिक सैक्टर के धन्धे हैं उनको वे ठीक तरह से चला सकें और उनमें आमदनी बढ़ा सकें । जिस समय मैंने पब्लिक सैक्टर और प्राईवेट सैक्टर की बात की थी मुझे बहुत खेद हुआ कि एक अखबार ने यह लिखा कि आपने उद्योगों के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने पर बोल दिया । यह बिल्कुल उल्टी बात थी । मैंने वास्तव में निजी क्षेत्र के बजाय पब्लिक सैक्टर को बढ़ाने के लिए ही जोर दिया था और इसके लिए हम बड़ी सतर्कता से काम कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है । शायद स्वतन्त्र पार्टी यह उपालम्भ दे सकती है कि हम राज्य का दायरा इतना बढ़ाना चाहते हैं कि व्यापार के सारे क्षेत्र को शक्ति से उपरान्त हथिया लेना

Page No 20

(श्री नारायणसिंह)

चाहते हैं। लेकिन यहां मैं यह याद दिलाता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि हमने एक मिश्रित इकोनोमी का आदर्श लिया है और उसके बाद समाजवादी समाज की स्थापना के लिए हम कटिबद्ध हैं। यह प्रयास एक वह प्रयास है कि जिससे हम प्रजातन्त्रीय ढंग से बिल्कुल प्रत्यक्षवादी रहें, प्रेक्टिकल रहें और उसी दृष्टि से हम सामाजिक न्याय को कायम कर सकें। हमारा यह प्रयास है कि कहीं समाजवादी समाज की रचना करने की जल्दबाजी में ऐसा कदम न उठा जायें कि जिससे हमारे यहां एकतन्त्रीय शासन, टोटेलिटेरियन पद्धति का शासन कायम हो जाय। हम प्रजातन्त्र को सजीव रखते हुए ऐसा प्रयास करना चाहते हैं जिससे समाजवादी समाज का निर्माण एक अनूठे ही ढंग से कर सकें।

यह विनोबाजी कई बार कह चुके हैं।

"ईशावास्य मिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्" ईश्वरीय वृत्ति को कायम करें कि हम यानि हम बांट कर खाना सीखें न कि बांटा खायें। एक विचार-धारा तो वह है जिसमें बराबर बराबर सब को बांट दिया जाये और उसमें सलाह मशविरे की जरूरत नहीं। गाय भैंस को हम बराबर बांटा बांटते हैं, लेकिन आज हम मानव समाज को उसी ढंग पर नहीं आंक सकते। वह तो रोटी और कपड़े को भी छोड़ देगा, अपनी जान कुर्बान कर देगा अगर उसकी आजादी में किसी प्रकार का दखल आता है। उस आजादी को कायम रखते हुए यदि हम आगे कदम बढ़ाते हैं बांट कर खाने की ओर तो वास्तव में वह इस प्रकार का कदम होगा जो गांधीवाद की बुनियाद पर होगा। इसमें हमने एक मिश्रित अर्थ-व्यवस्था पकड़ी है वह इसलिए कि यहां की वस्तुस्थिति ऐसी है कि जिसमें निजी प्रयास भी एक ढंग से चल रहा है। आज हम पब्लिक सैक्टर को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसमें कई प्रकार की रुकावटें हैं। हमारे पास कई अनुभवों की कमी है, हमारे पास टैक्निकल पर्सोनल काफी नहीं हैं, हमारे पास और कई बातों का लेकुना है तो भी जिस प्रकार से एक एक बात बनती जायेगी हम निजी प्रयास के साथ मिल कर पब्लिक सेक्टर को आगे बढ़ायेंगे।

एक कोआॅपरेटिव सेक्टर की बात भी आती है तो वह भी इसी प्रकार से है। लेकिन बड़े धन्धों में आज हमने कॉर्पोरेशन पद्धति अख्त्यार की है कई बातों में और मैं समझता हूँ कि उसको और भी अधिकाधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस कॉर्पोरेशन पद्धति से हम निजी प्रयास और सार्वजनिक प्रयास को साथ मिलाते हैं और तो यह तो मैं मिश्रित इकोनोमी का एक अनूठा नमूना समझता हूँ और ऐसी ही भूमिका में हम बड़ी सतर्कतापूर्वक आगे चलना चाहते हैं। स्वतन्त्रपार्टी का यह कहना है कि हम बिल्कुल ही निजी प्रयास को खत्म कर देना चाहते हैं, गलत है। हम तो जन-मानस को परिवर्तित करके शनैः शनैः सारे ढांचे में इस प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं कि वह समाजवादी समाज का समीचीन स्वरूप बन जाय। हम इस प्रकार का प्रयास कभी नहीं करना चाहते हैं कि जिससे प्रजातन्त्र की कड़ी टूट जाय और हमारे मानस के परिवर्तन के बगैर जोर

(श्री नारायणसिंह)

जबरन हम ऐसी स्थिति पैदा कर दें कि धुरी एकतन्त्रवाद की ओर हठात् ले जाये बैठ ही जायं। उसी दृष्टि से एक मिश्रित इकोनोमी का प्रयास चालू हुआ है और मैं समझता हूँ कि हमारे यहां पब्लिक सेक्टर से ज्यादा कॉर्पोरेशन पद्धति को प्रोत्साहित करना चाहिए और जिस जिस जगह; जैसे स्टेट ट्रान्सपोर्ट और स्टेट ट्रेडिंग ऑफ फूडग्रेन्स हैं उनके अन्दर जो भी कमियां हैं उनको हमें तुरन्त संशोधित करके इस सेक्टर को इतना बलवान बना देना चाहिए जिससे कि हमारा आर्थिक स्तर बिना टैक्स के भी ज्यादा बढ़ सके।

आज जो इन्डस्ट्रियल इन्डाइसेज़ यहां राजस्थान में मिलती हैं उन इन्डस्ट्रियल इन्डाइसेज़ को जब मैंने देखा तो करीब करीब स्टेन्डस्टिल स्थिति मिलती है-फिगर १०० का १०० ही रहा है। यह चीज़ वास्तव में विचारणीय है और हमें जिन चीजों में संशोधन करने की आवश्यकता है वहां तुरन्त करना चाहिये।

इसके अन्त में मैं इतना और अवश्य कहूँगा कि जब हम एक नियोजित अर्थ व्यवस्था कायम करना चाहते हैं और एक नियोजित पद्धति से आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे रिसोर्सेज़ को बढाना चाहते हैं और कई प्रकार के चेनल्स में हम बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो बेसिक डेटा, बेसिक सर्वे जब तक नहीं होगा तो उन प्रयासों में थोड़ी ढील रह सकती है। इस विषय में चाहे स्वतन्त्र पार्टी के नेता महोदय ने यह कहा हो कि फीगर्स सच्चे नहीं हैं, आंकड़े ठीक नहीं हैं, वह होगा; लेकिन मैं इस जगह पर यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि राजस्थान का इस प्रकार का पूर्व प्रशासन रहा है कि जहां आजादी के पहले कोई आंकड़े ठीक थे ही नहीं। यह सारी अंकन पद्धति का प्रयास इसके बाद शुरू हुआ है। कई प्रकार के बेसिक डेटा मौजूद नहीं हैं। मौजूद नहीं होते हुए भी १०-११ सालों में जो कुछ प्रयास किया गया है वह सराहनीय है। फिर भी हमें कम्प्लेसेन्सी का एटीट्यूड लेने की आवश्यकता नहीं है और बेसिक सर्वे हो और जहां जहां नहीं है उन सब को ठीक करना है।

एक तो इस विषय को करना होगा कि राजस्थान में पे कमीशन नियुक्त होना चाहिए जो पे इत्यादि के मामलों की पूरी तरह से जांच कर सके इन्डाइसेज़ के साथ।

दूसरी जो हमारे यहां पर-केपिटा इनकम के लिए विरोधी पक्ष से संकेत आया है तो जिस तरह से केन्द्र ने इस विषय में कमेटी नियुक्त की है कि डिस्पेरिटीज़ कहां कहां हैं, किस-किस प्रकार से इन्सीडेन्सेज़ ऑफ टैक्सेशन पड़ रहे हैं, डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ वैल्थ सिद्धान्त में कहां कहां लोच आ रही है। वैसी कमेटी की यहां पर आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की एक कमेटी, इस प्रकार की एक योजना हमारे यहां भी बनानी चाहिए जो पर-केपिटा इनकम अलग अलग लेवल पर अलग अलग प्रकार के कन्ज़ूमर्स की, उनकी इनकम्स की, अनिवार्य खर्च की, पूरी तरह से जांच कर सके और उसके ऊपर विस्तृत रिपोर्ट दे सके।

तीसरे, इन्सीडेन्सेज़ ऑफ टैक्सेशन के

(श्री नारायणसिंह)

बारे में मैं कह चुका हूँ। अलग अलग प्रकार के कन्ज्यूमर्स पर इस प्रकार से हमारे टैक्सेज़ का इन्सीडेन्स किस प्रकार से पड़ रहा है उसकी पूरी तरह से जांच करनी चाहिए।

लैण्ड रेवेन्यू एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स से रिप्लेस हो, इस बारे में मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इसकी भी जांच की आवश्यकता है।

पॉवर सर्वे: बिजली के लिए हमने काफी बड़ा प्रयास किया है और लाखों किलोवाट बिजली चम्बल और भाखरा से उपलब्ध करने का प्रयत्न हो रहा है और कई जगह पर शीघ्र ही बिजली पहुंच भी जायेगी। इन्डस्ट्रियल सेन्टर्स पर बिजली पहले पहुंचेगी। माइन्स बेस्ड इन्डस्ट्रीज़ पर पहले पहुंचेगी, इनके अलावा कृषि क्षेत्र में भी उस बिजली की आवश्यकता है। तो जब तक पॉवर की पूरी तरह सर्वे, पॉवर रिक्वायरमेंट्स की पूरी तरह सर्वे इस राज्य में न हो जाय हमें यह सही ढंग से मालूम नहीं पड़ सकेगा कि कितनी बिजली की आवश्यकता कौन कौन से अलग अलग क्षेत्र में हो सकती है और जब तक यह मालूम नहीं पड़े तो हमारे कई प्रकार के लोप साइडेड (Lop sided) और अनर्गल प्रयास जरूर हो सकते हैं। लेकिन जहां जिस प्रकार की प्रायोरिटीज़ देनी चाहिए उसमें भारी कमी रहेगी।

सर्वे ऑफ इकोनोमिक डेवलपमेंट इन रिलेशन टू दी रिसोर्सेज़: जो जो इन्डस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं हमारे यहां पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर अथवा कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ अथवा स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़, उनके लिए भी एक निर्देशक कमेटी की आवश्यकता है। मुझे इस बात की खुशी है कि जैसी कि माइन्स और मिनरल्स के बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसमें इस बात का संकेत किया गया है कि इस प्रकार की एक कमेटी, जो इन बातों पर राय देगी, बन चुकी है। वह जहां भी इन्डस्ट्री लगेगी अपनी रॉ मेटीरियल सर्वे के आधार पर राय देगी। जो भी इन्डस्ट्री लगेगी उसके आयात--निर्यात की क्या पोज़ीशन रहेगी, उसका पूरी तरह से मार्गदर्शन देगी। और अगर इस प्रकार की कमेटी है और वह इस पद्धति से मार्गदर्शन कर सकेगी तो मैं समझता हूं कि हमारा जो यहां पर उद्योग का विस्तार होगा वह बिल्कुल सही ढंग का होगा। तो इन चन्द बेसिक सर्वेज़ के बाद हम वाकई सुदृढ़तया आगे बढ़ सकेंगे।

मैं अन्त में एक थोड़ा सा जो स्वतन्त्र-पार्टी के नेता महोदय ने कुछ इन्फ्लेशन के बारे में कहा वहां मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा और पहले ही श्री मसानी महोदय को किस प्रकार से जवाब दिया गया था उसके बारे में कह चुका हूं और उसका मुद्दा पहले आ चुका है। लेकिन यहां आज जब हमको नियोजित पद्धति से बौद्धिक त्वरित आमूल विकास करना है तो प्राइसेज़ और इन्फ्लेशन इत्यादि के बारे में हमें उनके हर महत्त्व को स्वीकार करना पड़ेगा। आज प्राइसेज़ की पोज़ीशन इस प्रकार से है कि आज हमारे यहां पहले तो बढ़ती हुई आबादी का खयाल करना है। जब खानेवाले मुंह ज्यादा बढ़ते हों और पैदावार कम, उपज के साधन कम हों तो एक साधारण सी स्थिति है कि उससे कीमत बढ़ेगी ही। उसके अलावा भी कई प्रकार के बड़े बड़े विकास के

Page No 23

(श्री नारायणसिंह)

कार्य चालू हैं और इन विकास कार्यों के चालू होने से जो लोग आज तक अनएम्पलोएड थे उनके एम्पलॉयमेन्ट के अवसर मिले हैं। पहले यदि एक घर में चार आदमी थे और उनमें से एक आदमी काम पर लगा हुआ था तो आज इस प्रकार की स्थिति बन पड़ी है कि कम से कम इस प्रकार की योजनाओं से छोटे बड़े कामों पर उस घर के दो और व्यक्ति काम पर लग गये । इस तरह से एम्प्लॉयमेन्ट बढ़ा है। ऑपोर्चुनिटी काम में लगने की बढ़ी है तो उनकी जरूरत भी बढ़ी है। कन्ज़म्पशन बढ़ता है और चीजों की मांग बढ़ती है और मांग बढ़ती है तो प्राइसेज़ स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं। इसके साथ ही यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय आंकड़े देखें तो मालूम होगा कि विलायतों में भी ब्रिटेन, फ्रान्स आदि में सब जगह वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं, वस्तुओं में गिरावट आई है ब्रिटेन में, मैं उन आंकड़ों में नहीं जाऊँगा लेकिन इतना कहूँगा कि इन अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए और घरेलू परिस्थितियों को देखते हुए कुछ उतार-चढ़ाव प्राइसेज़ में होता है तो सब्र करनी पड़ती है । फिर भी इन्फ्लेशन से बचने के लिए काफी प्रयत्न किया गया है। मुद्रास्फीति से दूर रहें, ऐसी स्थिति नियोजित अर्थ व्यवस्था में जिसमें तीव्र गति से आगे बढ़ते रहे हैं खाली अटक नहीं सकते, जागरूक रह कर विषय-स्थिति ठीक करते रहने का प्रयास करना पड़ेगा। तो मैंने काफी सदन का समय लिया और जो खास खास बातें नजर में आईं, बजट के सम्बन्ध में वे कहीं। मैं समझता हूँ, हमने टैक्सेशन की ओर जो कदम उठाया है वह यहां की गिरी हुई आर्थिक दशा को देख कर उठाया है, तभी हम दूसरे सभी राज्यों के साथ इस बारे में ठीक ठहर सके हैं । और इन डेटाज़ के साथ, इन टैक्सेज़ के साथ सही रूप में अपनाकर आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ, हम टैक्सेज़ से जितना फायदा देना चाहते हैं वह वाकई दे सकेंगे और इसके अलावा यदि हम पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में बढ़ते हैं जिससे कि फाइनेन्सेज़ की स्थिति स्वतः ठीक हो सके तो वह इसी प्रकार का जरिया होगा जहां पब्लिक सेक्टर या प्रशासन सुधरेगा और कॉर्पोरेशन और कोऑपरेशन्स पद्धति का सुचारू फैलाव होगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री बृजसुन्दर शर्मा।

(श्री मुरलीधर व्यास के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री बृजसुन्दर शर्मा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, लगातार दो दिन से मुझे सदन में बजट पर हमारे माननीय सदस्यों की बहस सुनने का मौका मिला। खास तौर पर मैंने बड़े ध्यान से हमारे स्वतन्त्र पार्टी के नेता के भाषण को सुना और सुना हमारे माननीय सदस्य जो जनसंघ के मुखिया हैं उनके भाषण को। मुझे इस बात को जान कर और सुन कर बड़ी खुशी हुई दिल में, जब मैंने इस सदन में दोनों तरफ के नेताओं से कुछ समाजवाद की बातें सुनीं। हमारे स्वतन्त्र दल के नेता के मुंह से मुझे यह सुन कर कि इन्श्योरेन्स और बैंकिंग का नेशनलाइज़ेशन हो ही जाना चाहिये, मेरे दिल में बड़ी प्रसन्नता और खुशी हुई। मैं यह मानता हूँ कि कांग्रेस ने जिस नारे को बुलन्द किया, हमारे समाज को समाजवादी

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

समाज के ढांचे में ढालने को उसे कम से कम हमारे स्वतंत्र दल के नेता ने इस सदन में कबूल किया उससे ज्यादा हमारे लिए और कोई खुशी की बात नहीं हो सकती । मैं उम्मीद करता हूँ कि स्वतन्त्र दल के नेता की तरह और लोग भी इसे कबूल करके चलेंगे । जितने आय के साधन हैं, जिनसे अर्थ व्यवस्था में मदद मिलती है, जिनसे पूंजी का निर्माण होता है, जिनसे पूंजी की बढ़ोत्तरी होती है उन सारे साधनों का राष्ट्रीयकरण किया जायगा, जल्दी से जल्दी और मैं निवेदन करूंगा कि उनके भी दिमाग आपकी तरह से जल्दी से जल्दी पलटेंगे ।

इसी तरह से मुझे इस बात की भी खुशी हुई जब हमारे जन संघ के नेता ने सदन में लोकतंत्रीय अर्थ-व्यवस्था के बारे में अपने विचार प्रगट किये और यह जाहिर किया कि पूंजी का केन्द्रीयकरण न होकर विकेन्द्रीकरण होना चाहिए प्रजातांत्रिक तरीके से और इस अर्थ-व्यवस्था में भी उनको विश्वास है । मैं समझता हूं, सदन का प्रत्येक व्यक्ति उनके भाषण से प्रफुल्लित हुआ होगा । जहां मेरी तरफ के साथी इस बात से खुश हैं वहां उस तरफ बैठनेवाले साथियों को भी तसल्ली हुई होगी कि हम लोगों ने इस बजट से कम से कम हमारे नेताओं का दिमाग तो पलटा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनियोजित अर्थ व्यवस्था में हम विश्वास करते हैं और प्रजातांत्रिक तरीके से समाजवाद लाने में हमारा पूर्ण विश्वास है । हम पूंजीवादी प्रणाली को नहीं चाहते और उसे खत्म करना चाहते हैं । हम पूंजी का केन्द्रीयकरण नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि पूंजी पैदा करने के साधन हाथ में हों और साथ ही साथ हम यह भी चाहते हैं कि जहां हमारी अर्थ व्यवस्था में अभी इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है वहां कुछ ऐसी भी पूंजी उत्पादन के साधन हैं जो प्राइवेट लोगों के हाथ में रह सकते हैं । कुछ ऐसे साधन जिनसे कुछ केपिटल पैदा कर सकें उनको अपने हाथ में लेना होगा ।

मुझे इस बात की बड़ी सराहना करनी पड़ेगी अध्यक्ष महोदय, हमारे वित मंत्रीजी ने अब की बार पता नहीं क्यों अपनी साफ स्थिति को कबूल किया और उन्होंने साफ साफ बताया कि हमारी क्या हालत है । अच्छा है साफ बताना क्योंकि उससे लोगों को सुझाव देने का भी मौका मिलता है और इससे हम लोगों के पास साफ तरीके से पहुँच सकते हैं । लेकिन मैं इतना कहूँगा कि हमारे वित्त मंत्रीजी घबराये हुए थे । उन्होंने यहां तक कह दिया कि हमें पेट पर पट्टी बांधनी पड़ेगी और भाषण में यह भी कह दिया कि हमें जरूरत है सचेत रहने की । मैं, जहां तक सचेत रहने का संबंध है, सहमत हूं लेकिन जहां यह कहा कि पेट पर पट्टी बांधनी पड़ेगी, मैं उससे असहमति जाहिर करता हूँ; क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है कि पेट पर पट्टी बांधनी पड़े । प्लान्ड इकोनोमी और अनडेवलप्ड देशों में ऐसा मौका आता है जब खर्चा करना पड़ता है उधार लेकर खर्च करना पड़ेगा, मांग कर खर्च करना पड़ेगा और टैक्स लगा कर खर्च करना पड़ेगा । अपने विकास के लिए, मुल्क में आनेवाली बहतरी के लिए हम कुछ सोचें कि कुछ कर सकें । लेकिन आज के दिन जैसा कि उन्होंने डर बतलाया मुझे वैसी आशंका

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

नहीं लगती है इस वजह से जैसा कि उन्होंने कहा :

"There are also no immediate or near-future prospects of any marked improvement in our resources as may be evident from the following explanation. The major portion of our Third Plan Outlay has been on Power and Irrigation Schemes. The Rajasthan Canal Project will not have perennial irrigation till after 1970. It takes about 10 years for an irrigation project to yield full results and so the Chambal and Bhakra Projects will give substantial returns only in the second-half of the Fourth Plan."

मैं इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं समझता। चम्बल और भाखरा के प्लान्स का जहां तक ताल्लुक है, वे पूरी हुई हैं और उनसे हमें आमदनी होनी शुरू हो गयी है। साल, दो साल या तीन साल में हम उम्मीद कर सकते हैं, जहां तक चम्बल की बिजली का ताल्लुक है ज्यादा से ज्यादा हिस्सों में पहुंच जायगी। जहां तक पानी का ताल्लुक है मुझे कोई शक नहीं कि तीन साल में पानी पहुंच जायगा चम्बल का और भाखरा का भी पहुंच रहा है। इस प्रकार निर्माण करने की आशा रखते हैं। जहां तक उनका ताल्लुक है उनसे यह आशंका रखना कि १० साल बाद या अगले प्लान के अन्त में फायदा होगा; यह मैं नहीं मानता। हम यह कोशिश करें कि इसी थर्ड प्लान में हमें उसका फल मिलने लग जाय। मिलना तो शुरू हो गया। अब थोड़ा टाइटन करना चाहिए; बेल्ट्स को नहीं; बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन को टाइटन करना पड़ेगा। हमें कुछ थोड़ी चिन्ता रखनी पड़ेगी, हमें बेखबरी से नहीं सोना पड़ेगा, हमें यह नहीं सोचना पड़ेगा कि हमारे पास बहुत साधन हैं; लेकिन हमें इस बात की कोशिश करनी पड़ेगी कि हम इन मदों से ज्यादा आमदनी कर सकें। तो मैं समझता हूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में चम्बल और भाखरा दोनों से आमदनी हो जानी चाहिए।

मैं, माननीय अध्यक्ष, सदन का ध्यान गत वर्ष के हमारे वित मन्त्री के भाषण पर दिलाना चाहता हूँ। उसमें उन्होंने यह निवेदन किया था:—

"There is thus no reason to be perturbed over the figure of the public debt. These loans are not meant only for earning interest but they are meant to provide funds for Development Plans and Production Schemes and it is quite possible to repay them out of the surplus income which will accrue to the State as a result of the fulfilment of these Schemes."

जहां गत वर्ष हम एक बात करते थे कि हमें किसी तरह की चिन्ता करने की जरूरत नहीं है, हमारे डेवलपमेन्ट के प्लान्स और स्कीम्स पूरी होने पर। हमें आमदनी मिलनी शुरू हो जायगी और कर्ज को चुका सकेंगे, मैं आज भी उस स्थिति को मानता हूँ। ठीक है कि हमने कर्ज को चुकाने के लिए या ओवर ड्राफ्ट को चुकाने के लिए भारत सरकार से ऋण लिया, सिक्योरिटियां बेचीं और तरह तरह से रुपया इकट्ठा किया।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

आज यह चीज सोचते हैं जब कि गत वर्ष हमें यह मालूम होना चाहिए था कि हमें इतना खर्चा करना जरूरी हो जायगा तो स्थिति को साफ कर सकते थे। लेकिन इसी सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शायद यह हो सकता है कि इसका कारण यह हो सकता है कि फाइनेन्स पर चेकिंग ठीक तरह से नहीं रहा हो। हमारे फोर्टनाइट चेकिंग का सिस्टम है कि फोर्टनाइट में फिगर्स का चेकिंग होना चाहिए, उसमें शायद कुछ स्लेक नेस बरती हो, शायद हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर ने, चौदह दिन के अन्दर आमदनी और खर्च के आंकड़े उनकी मेज पर आने चाहिए उनकी ओर ध्यान नहीं दिया हो या वे उनके सामने नहीं आये हों। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यह पद्धति जरूर अपनानी पड़ेगी कि चौदह दिन के अन्दर जितने ट्रेज़री के स्टेटमेंन्ट हैं, जिनमें जितनी आमदनी होती है या जितना खर्चा होता है उनके आंकड़े होते हैं उसको फोर्टनाइट में वित्त मन्त्रीजी खुद देखा करें और उन पर अपना कंट्रोल रखें कि इतनी आमदनी हुई और इतना खर्च पड़ा और क्या कारण है कि गत वर्ष इतनी आमदनी इस मद में हुई थी और इस फोर्ट-नाइट में कम क्यों हुई ? यह किस कारण से हुई, क्या कारण हो सकते हैं ? इन सब का विवेचन करने का वे ध्यान रखेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आती है कि हमें मजबूर होना पड़ेगा कि पेट पर पट्टी बांधें। थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। वर्ना ऐसी परिस्थिति में नहीं हैं कि यह कहा जाय कि राजस्थान दिवालिया हो गया, राजस्थान के पास कुछ नहीं रहा। हमारे पास बहुत से रिसोर्सेज़ हैं, आमदनी के जरिये बहुत हैं। केवल जरूरत है कि आमदनी के जरियों से ठीक तरह से आमदनी आवे, इसकी व्यवस्था करें। इसके साथ ही साथ जो फिजूल खर्चियां हैं उनको भी बन्द करने की कोशिश करें।

आज हम बात करते हैं इकोनोमिक कट की। गत वर्ष भी बात की थी कि पचास लाख का इकोनोमिक कट अफेक्ट में लायेंगे लेकिन हम देखते हैं कि इकोनोमिक कट किसी भी तरह से सम्भव नहीं हुआ, उसको अमल में नहीं लाया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि इको-नोमिक कट की जरूरत होती है तो सदन के किसी सदस्य को विश्वास में लें या फिर किसी और कमेटी का निर्माण करें, या फिर कोई जरिया निकालें जो यह देखे कि कौनसे खर्च ऐसे हैं जिनमें रुपया वैस्ट होता है और जिसको बचाना चाहिए। तो इसके लिए हम एक कमेटी का निर्माण करके उन चीजों को अच्छी तरह से देख सकते हैं। साथ ही साथ हम उन चीजों को भी देखें जो सदन की कमेटी जो हर वक्त यहां मिलती है पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी उनके जो निर्णय होते हैं वे उनकी रिपोर्ट्स में दर्ज होते हैं उन पर अमल किया जाता है या नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर उन कमेटियों की रिपोर्ट्स पर अच्छी तरह से विचार करके उनको अमल में लाने की कोशिश करें तो वे भी इतना मसाला देती हैं। उनका हम अपनी अर्थ-व्यवस्था में योग लें तो उससे हमें बहुत फायदा मिल सकता है।

माननीय अध्यक्ष, जहां हम सुनियोजित अर्थ-व्यवस्था की बात करते हैं तो यह तो

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

हमारा क्रीड है। हम समाजवाद के लिए आगे आये हैं और उस क्रीड को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील हैं। वहां एक बहुत बड़ी बात अनुभव होती है कि यहां पर इस बारे में विचार रखे गये कि कोऑपरेटिव फार्मिंग के जरिये हम मुल्क की तरक्की नहीं कर सकते। हमारे ऐसे माननीय सदस्य हमारे यहां के काश्तकारों में एक डर सा बैठाना चाहते हैं, उसके जरिये वे कहना चाहते हैं कोऑपरेटिव अर्थ व्यवस्था तो कभी चल नहीं सकती है। उसके लिए वे बताना चाहते हैं कि काश्तकारों से जमीन छीन ली जायगी, उनके ऊपर उनकी, जायदादें नहीं रहेंगी और माननीय अध्यक्ष, इस चुनाव के दौरान में मैंने तो देखा, मेरे को बहुत बड़ा पोस्टर देखने में आया जिसमें एक गाय के सिर को एक हाथ में लिये हुए एक दैत्य सा बनाया हुआ बताया और नीचे खून बहता बताया गया। एक किसान को दैत्य के पांव के नीचे रख कर बताया गया कि इस सहकारी खेती से पशु धन राशि नष्ट होगी, सहकारी खेती से आदमी की आजादी खत्म हो जायगी, सहकारी खेती से जमीन की मालिक सरकार हो जायगी। इस प्रकार की धारणायें हमारे कई माननीय सदस्य रखते हैं। मैं समझता हूं, यह बिल्कुल गलत है। अगर हिन्दुस्तान की तरक्की करनी है तो हमारा हिन्दुस्तान एक कृषि प्रधान देश है और यहां छोटे छोटे टुकड़ों में किसानों के पास खेत की जमीन है। वे अगर सहकारी खेती को नहीं अपनायेंगे, या सर्विस कोऑपरेटिव की तरफ नहीं जायेंगे तो पैदावार को नहीं बढ़ा सकते, हैसियत को नहीं बढ़ा सकते। इसलिये जरूरी है कि अगर भारतवर्ष के किसानों की हालत को ठीक करना है, उनकी आर्थिक हालत को ठीक करना है, आगे बढ़ाना है तो हमें सर्विस कोऑपरेटिव को पहले अपनाना पड़ेगा और उसके साथ ही साथ सहकारी खेती की तरफ हमें जाना होगा, उसके बगैर किसानों का कल्याण नहीं हो सकता। इसके बारे में यह मानना कि काश्तकार के खेत की जमीन सरकारी जमीन हो जायगी, बिल्कुल निराधार है। मैं समझता हूं कि बगैर पढ़े-लिखे आदमियों को यह बताया जा सकता है लेकिन जो आदमी पढ़ा-लिखा है, जो आदमी खुद का दिमाग रखता है, जो अर्थ-व्यवस्था के बारे में जानता है वह जान सकता है कि किस प्रकार सहकारी खेती से उसका हक जाया होगा। मैं इसके विषय में और ज्यादा नहीं कहना चाहता।

दूसरी बात यहां कही गई है नेशनलाइज़ेशन ऑफ ट्रान्सपोर्ट के बारे में। मैं समझता हूं कि बड़ी अच्छी तरह से यहां पर उन लोगों की वकालत हुई है जो प्राइवेट बस ओनर्स हैं और नेशनलाइज़ेशन ऑफ ट्रान्सपोर्ट को इस वजह से खत्म करने के लिए कहा गया कि इससे फायदा नहीं होगा, गरीब जनता को फायदा नहीं है, बस ओनर्स को फायदा नहीं है। ठीक है, बस ओनर्स को फायदा हो या नहीं हो लेकिन आज के दिन आम आवाम चाहती है कि अच्छी तरह से सफर करने को मिले। लेकिन एक बात यह ध्यान में रखनी चाहिये कि उनका जो खर्च है वह कम हो, उन लोगों को चीप ट्रान्सपोर्ट मिले यानी सफर करने में खर्च कम हो। मैं मानता हूं कि राजस्थान में आज के दिन मोटरों का किराया और जगहों से ज्यादा है। जहां ६ पाई पर-मील पहले लिया करते थे वहां हमारे राजस्थान में दस पाई उस

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

वक्त किराया था। आज भी यू. पी., मध्य प्रदेश, पंजाब से इन आंकड़ों का मिलान करेंगे तो किराये की दरें राजस्थान में ज्यादा मिलेंगी। इसलिए इसकी तरफ हमें ध्यान लगाना पड़ेगा कि किराया किस तरह से कम हो और राजस्थान में सस्ता ट्रान्सपोर्ट किस तरह से अवेलेबल हो। इसके साथ ही मैं यह उपयुक्त समझता हूं मेरे विचार इस बारे में प्रगट करने के साथ कि सस्ता ट्रान्सपोर्ट राजस्थान में नहीं है; ज्यादा से ज्यादा मंहगा है दूसरे प्रदेशों से, उसे आप समान करें। लेकिन हम यात्री-कर को बढ़ा कर उसको और ज्यादा मंहगा कर देते हैं। पहले भी यात्री-कर हमारे यहां पर था और उसके साथ साथ पहले साल ५ परसेन्ट फिर बढ़ोत्तरी हुई। जो बढ़ोत्तरी हुई वह मैं समझता हूँ कि वाजिब नहीं है। वह बढ़ोत्तरी आम पेसेन्जर हैं, गरीब लोग हैं जो मोटरों में सफर करते हैं उन पर असर डालनेवाली है। इसलिये यह भार उन पर डालना हमारे लिये अच्छा नहीं है। हम तो जितनी सुविधाएं एक समाजवादी समाज में गरीबों को दे सकें उतनी हमें उनको देनी चाहिये और जो लोग बसों में सफर करते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जो सहूलियतें दे सकते हैं देनी चाहिये। इसके अलावा जिस समय हम रोडवेज़ को नेशनलाइज़ करें तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि एक मील पर जो किराया आस-पास के दूसरे प्रान्तों में लिया जाता है उसके मुकाबले में यहां पर जो किराया लिया जावे वह ज्यादा नहीं होना चाहिये। आज हम देखते हैं कि देहली और पंजाब में इतना ज्यादा बसों का किराया नहीं है जितना राजस्थान में है। इसलिये किराया भी देख कर तय करना चाहिये कि हमारी हालत वास्तव में कैसी है और किस तरह से हमें किराये की दरों को लगाना है।

अध्यक्ष महोदय, समाजवादी अर्थ व्यवस्था में यह तो निश्चित है ही कि हमें अपने रिसोर्सेज़ बढ़ाने होंगे और रिसोर्सेज़ के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा रुपया भारत सरकार से हम ले सकते हैं; लेकिन रिसोर्सेज़ बढ़ाने का जो तरीका है वह आज हम देखते हैं कि उचित नहीं है और उसकी तरफ हमने उचित ध्यान नहीं दिया है; या तो यों कहिये कि हमारी कुछ मजबूरियें है। हो सकता है कुछ मजबूरियें भी हों। हमारे वित्त मन्त्रीजी ने एक जगह जिक्र किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे सैकन्ड प्लान पर काफी खर्चा बढ़ा है :

"9. In the first place, the fulfilment of the targets of the Second Five Year Plan has proved a heavy burden on the resources of the State, so that, as a result of the budgetry deficits during the past years the Goverment had to overdraw a substantial amount from the Bank and were also unable to repay some imstalment...

उसके बाद उन्होंने जिक्र किया है : "there had been unavoidable shortfalls in receipts and inevitable increases expenditure under various Heads.

मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि केपिटल एक्सपेन्डिचर हमने किया उससे हमारा नोन टैक्स रेवेन्यू बढ़ना चाहिये वह नहीं बढ़ा। मैं समझता हूँ कि प्रथम पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना खत्म होने के बाद आज

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

के दिन हमको लेखा-जोखा करने की जरूरत है। हमने दो योजनाओं में रुपया खर्च किया है उसमें आमदनी क्यों नहीं बढ़ी और उस अनुपात में क्यों नहीं बढ़ी जिस अनुपात बढ़नी चाहिये ? इसका क्या कारण है कि नोन टैक्स में माइनर इर्रिगेशन और इर्रिगेशन में आमदनी क्यों नहीं बढ़ी, फोरेस्ट और मिनरल डिपार्टमेंटों में आमदनी क्यों नहीं बढ़ी ? इन सब बातों के लिये हमें इवोल्यूशन ऑरगेनाइज़ेशन करना पड़ेगा। हमें इस प्रकार की मशीनरी और इवोल्यूशन ऑर्गेनाइज़ेशन के जरिये प्रथम और दूसरी पंचवर्षीय योजना में नोन टैक्स रेवेन्यू बढ़नी चाहिये। इवोल्यूशन कोम्युनिटी प्रोजेक्ट का हो सकता है। छोटी-मोटी बातों को जोड़ कर ओन दी होल, इसका इवोल्यूशन करना जरूरी है। आगे किस तरह से बढ़ना है, इसको ध्यान में रखें ताकि हमें इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके।

इसके साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज के दिन हमारा खर्चा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि नये डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट हम क्रिएट करते जा रहे हैं। उन डिपार्टमेंट्स में इन्सपेक्टर होंगे, दूसरे अधिकारी होंगे, और दूसरे कर्मचारी भी होंगे। और मैंने खास तौर से दो-चार सालों में यह देखा है कि काम वास्तव में उनके पास नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज़ेशन में क्या काम होता है, यह तो हम जानते हैं। सेल टैक्स आदि में जो इन्सपेक्टर होते हैं उसमें सब इन्सपेक्टर अलग और इन्सपेक्टर अलग होते हैं। उनके पास सीमित काम होता है।

मैं यह निवेदन करूंगा कि अलग अलग प्रोविज़न और अलग अलग खर्चों का जो प्रोविज़न किया है मैंने थोड़ा सा एक्सपेन्डिचर को देख कर मालूम किया। वह अन-नेसेसरी है। बहुत से लोगों के पास कुछ काम नहीं होता है। एक इन्सपेक्टर मार्केटिंग इन्सपेक्टर का काम कर सकता है जो सेल्स टैक्स में फूड का काम करता है। उसको यह काम भी दिया जा सकता है। आप डेवलपमेंट में देखेंगे कि एग्रीकल्चर डाइरेक्टर ब्लॉक में भी एग्रीकल्चरल ऑफिसर अलग अलग पावेंगे। यह इतना मल्टीफेरियस एक्सपेन्डीचर है और मैं यह कहूंगा कि जितने ऑफिसेज की जरूरत है उससे ज्यादा ऑफिसेज़ लग रहे हैं।

एक और बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और वह है स्पेशल पे। स्पेशल पे का तरीका हमारे यहां पुराने जमाने से चला आ रहा है। मैं नहीं समझ पाया कि आज जब हम १० बजे से ५ बजे तक की ड्यूटी देते हैं और १० से पाँच बजे तक काम करते हैं फिर उनको स्पेशल पे किस बात की दी जाती है। यह समझ में नहीं आता। अगर पांच बजे से ज्यादा समय उनको बैठना पड़े और काम करना हो तो स्पेशल पे पे वाजिब हो सकती है। एक आई.ए.एस. है यदि उसको मोटर ट्रान्सपोर्ट में ट्रान्सफर कर दिया जाता है तो उसको १५०) रु० उसकी तनख्वाह से ज्यादा स्पेशल पे के रूप में एलाउन्स के दिये जाते हैं। समझ में नहीं आता कि यह क्यों दी जाती है ? वह जहां पर काम करता था वहीं पर भी काम तो उसको

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

उतना ही करना पड़ता था। उसने सेक्रेटेरियेट में काम नहीं करके यहां पर काम किया है। जब आप स्पेशल पे १५०) या २००) या २५०) रु० देते हैं तो उसके साथ साथ उनके स्टेनोग्राफर्स और दूसरी लवाजमा जो उसके साथ होता है उसको स्पेशल पे भी अलग से देनी पड़ती है। पता नहीं फाइनेन्स मिनिस्टर को इसका ध्यान है या नहीं। वे इस संबन्ध में कहां चले गये हैं? मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस संबन्ध में ध्यान दें और स्पेशल पे को समाप्त करके इकॉनोमी करेंगे तो मैं आशा करता हूं कि इसमें भी ३० या ४० लाख रुपयों के घाटे की पूर्ति हो सकती है।

एक चीज मैं और निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, कि स्टेट ट्रेडिंग स्कीम में हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाया है। लेकिन जरूरत इसमें इस बात की है कि स्टेट ट्रेडिंग के लिये सरकार ने जहां जहां नियंत्रण कर रखे हैं वहां सरकार को चाहिये कि सदन के सदस्यों को भी उसमें लिया जावे ताकि वे मेनजमेंट को देख सकें कि मुनाफा क्या आता है और मशीनरी काम करती है इस पर और अच्छी तरह से काम किया जा सकता है। आज के दिन हम देखते हैं कि नेशनलाइज़ेशन बढ़ता जा रहा है। आगे भी हमें बहुत सी चीजों पर नेशनलाइज़ेशन करना होगा। जिस तरह से कई कम्पनियों में अच्छे आदमी भाग लेते हैं ठीक उसी तरह से यदि यहां पर कार्य करेंगे तो ज्यादा फायदा मिल सकेगा और इस पर यदि ध्यान दिया गया तो मेनेजेमेंट ठीक तरह से चल सकेगा। मैं यह कहूंगा कि कॉमर्शियल कन्सर्न को इस तरह से खुला छोड़ देना मैं ठीक नहीं समझता। जितने भी कॉमर्शियल कन्सर्नस हैं उनमें सब में सदन के सदस्यों को विश्वास में लिया जावे।

मैं माननीय अध्यक्ष, इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि जो टैक्सेशन का दकियानूसी तरीका हमारे यहां पर चला आता है, जो पुरानी रियासतों के जमाने में भी था, राजस्थान बनने पर भी था, ५ वर्ष पहले भी था और आज भी तरीका टैक्सेशन का है; वही अपनाते हैं जो आज के दिन समाजवादी अर्थ-व्यवस्था और विकास की अर्थ-व्यवस्था में नहीं जंचता।। ठीक है इस सिद्धान्त को मैंने बड़े गौर से पढ़ा कि जो टैक्सेशन माननीय वित मन्त्री ने लगाये हैं वे सिद्धान्त के ऊपर घटते हैं कि नहीं कि टैक्सेज़ का भार उन्हीं लोगों पर पड़ना चाहिये जो कि टैक्सेज़ दे सकते हैं। अगर इस चीज को देखें कि इसका इन्सिडेन्स किस पर पड़ता है तो फौरन उसी तरीके पर पहुंच जाते हैं, जो पुराना तरीका है उसी को अपनाते हैं। ये टैक्सेज़ जो लगाये गये हैं ये ऐसे हैं कि जिनका आम जनता पर इफेक्ट पड़ता है।

यह इन्डाइरेक्ट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन है। इसका असर आम जनता पर पड़ता है। डाइरेक्ट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन को हमें अडॉप्ट करना चाहिये। इसको अडॉप्ट करने से ही हम वास्तव में जो लोग टैक्स दे सकते हैं उन पर टैक्स लगा सकेंगे। इनडाइरेक्ट टैक्सेशन से गरीबों पर इन्सिडेन्स लगता है जो कि इस प्रकार के टैक्स देने की स्थिति में नहीं हैं। एक गरीब किसान जिसकी आमदनी २५) रु० माहवार है वह मोटर में जाता है तो वह भी उतना ही पैसेन्जर टैक्स देता है जितना

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

कि आप और हम जैसी हैसियत के लोग देते हैं।

इन टैक्सेज़ को लगाते समय जरूरत इस बात के सोचने की थी कि इस तरीके को बदल कर ऐसा तरीका अपनाते कि जो टैक्सेज़ दे सकने की हैसियत में हैं उन्हीं पर इन टैक्सेज़ का असर पड़ता। ट्रैक्टर्स पर टैक्स लगाते, कारस पर टैक्स लगाते, पैट्रोल पर टैक्स लगाते, मोटर एक्सेसरीज पर टैक्स बढ़ा सकते थे, इतनी ही आमदनी इसके जरिये से आप खड़ी कर सकते थे। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, मेरे दिमाग में नहीं आता कि ऐसी बात क्यों नहीं की गई। १५ दिन का टाइम माननीय वितमंत्री ने बजट बनाने में लिया वहां शायद १५ मिनट का टाइम भी इन टैक्सेज़ को लगाने के बारे में नहीं लिया होगा।

इसी तरह दूसरे टैक्सेज़ को लगाने के बारे में भी निवेदन करना चाहूँगा। आज देखते हैं कि सोने-चांदी के जेवरों के ऊपर टैक्स बढ़ाया है। ठीक है, सोना-चांदी पहिनने वाले ज्यादा से ज्यादा टैक्स दें, पर आज के दिन चाहें कि चांदी की बुलियन के बजाय ऑर्नामेंट्स पर टैक्स लगायेंगे; यह उचित नहीं कहा जा सकता। चांदी की बुलियन पर टैक्स बढ़ा देते पर आपने ऐसा न करके मजदूरी करने वालों पर टैक्स लगाया है, इस टैक्स का असर मजदूरों पर पड़ता है। मजदूर अपनी मजदूरी के लिए ऑर्नामेंट्स बनाता है और मजदूरी करके बेचता है, उसकी मजदूरी कर मुक्त होनी चाहिए। आपने ऑर्नामेंट्स पर कर लगा कर मजदूर की मजदूरी पर टैक्स लगा दिया है। मान लीजिये चांदी का भाव १४५ है, उस पर ८ आना सैकड़ा टैक्स है तो मजदूर उस पर मजदूरी करता है वैसी हालत में उस पर २) रुपया सैकड़ा और टैक्स बढ़ जाता है। तो यह मजदूर की मजदूरी पर टैक्स लगाया गया है। तो इस तरह ऑर्नामेंट्स पर टैक्स लगाने की प्रणाली अपनाई है। मैं समझता हूं, यह ठीक नहीं है। ऑर्नामेंट्स पर टैक्स न होकर बुलियन पर टैक्स होता तो ठीक था। बने हुए ऑर्नामेंट्स कोई भी देहली से ले आयगा जहां कि आठ आना सैकड़ा ही टैक्स है; तो इस तरह आपका टैक्स भी जायगा और यहां के मजदूर की मजदूरी भी चली जायगी। १० हजार के ऑर्नामेंट्स बनाने वाला है उसको क्या फर्क पड़ता है कि जयपुर में ही ऑर्नामेंट्स बनाकर खरीदे, ८ आना सैकड़ा टैक्स देकर वह देहली से या इससे भी कम टैक्स देकर गुजरात से ऑर्नामेंट्स ले आयगा। तो टैक्स भी नहीं आयेगा और गरीब मजदूरों का रोजगार भी खत्म होगा। तो बुलियन पर टैक्स होना चाहिये; चांदी पर, सोने पर टैक्स लगाते वह ठीक था, पर ऑर्नामेंट्स पर टैक्स लगाया है वह ठीक नहीं है।

अब मैं बिजली के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। बिजली पर बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि ३ नये पैसे इलेक्ट्रिसिटी पर ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। हमें उम्मीद तो यह थी कि भाखरा और चम्बल की बिजली आ जाने पर लोगों को सस्ती बिजली मिलेगी। एक तरफ तो बड़े बड़े कारखानेदार हैं उनको सरकार सस्ती बिजली देती है और दूसरी ओर गरीब कन्ज़्यूमर्स हैं उनको कहती है कि ज्यादा पैसा बिजली का देना पड़ेगा। मैं समझता हूं, यदि आपको बिजली

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

पर टैक्स बढ़ाना ही था तो किसी हद तक छोड़ कर बढ़ाना चाहिये था, २० यूनिट तक एक ऑर्डिनरी फेमिली के आदमी कन्ज्यूम कर सकते हैं उस हद तक मुक्त रख कर उससे आगे जितने युनिट स कन्ज्यूम होते उन पर टैक्स बढ़ाते।

आज हमने इस बात को देखा है और सदन में भी कई बार इस बारे में सवाल आये हैं कि बड़ी बड़ी कम्पनियां जयपुर में कायम हुईं, उनको जो एग्ज़ेम्पशन्स शुरू में दिये गये वे आज भी कायम हैं। एक अमुक कन्सर्न को कम भाव पर बिजली क्यों देते हैं ? उनको जो बिजली के बारे में रियायतें दी हुई हैं उनके बारे में भी सोच सकते हैं कि वाजिब हैं कि नहीं। उस समय यदि यह देखा हो कि राजस्थान में कोई कारखाना नहीं खोलता है और इसलिए पानी-बिजली को सुविधा दी है तो उसके साथ ही साथ हमें यह देखना होगा कि आज के दिन उनसे करोड़ों रुपयों का माल बनता है लेकिन वे लोग एक पैसा भी मुनाफा नहीं बताते हैं। वहां यदि बिजली का खर्चा उस घाटे में और जोड़ देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है; क्योंकि मजदूरों को तो बोनस मिलता नहीं है,वे हमेशा घाटे में ही बताते हैं। मैंने खुद ने इस चीज को एग्ज़ामिन किया है, उस जानकारी के आधार पर मैं यह निवेदन करता हूं। ऐसी हालत में अगर बिजली का पैसा बढ़ जावे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है।

(१.० म.प.)

इसी तरह से ऑइल सीड पर, कपास पर हम देखते हैं, वित्त मंत्री महोदय ने सोच कर जिन मदों पर टैक्स बढ़ाया है, मैं समझता हूं उनको उन पर पुनः विचार करना चाहिए। इसके लिए कई और तरीके हो सकते हैं। १२८ लाख के उन्होंने टैक्सेज़ लगाये हैं। यदि १२८ लाख की और तरीकों से जब आमदनी बढ़ सकती है तो उनको उसकेलिए कोशिश करनी चाहिए। यदि नान टैक्स रेवेन्यू में बढ़ा सकते हैं तो उसके लिए उनको कोशिश करनी चाहिए। और भी कई चीजें बची हुई हैं। जब टैक्स लगाने का प्रश्न आता है तो हम सिद्धान्त तौर पर यह चीज मान लें कि हमको डाइरेक्ट टैक्स को अवोइड करना है, करना चाहिए भी। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि ऐसा हो सकता है कि टैक्सेशन प्रोपोज़ल माननीय वित्त मन्त्री महोदय के सेक्रेटरी ने ड्राफ्ट किए हों और उन पर जो असर होने वाली चीजें हैं उन पर टैक्स न लगाये हों। यह भी हो सकता है। लेकिन यह मेरी समझ में नहीं आता कि उनकी टैक्सेशन की पॉलिसी क्या है।

एक चीज़ मुझे भी खटकती है, माननीय अध्यक्ष, उसे मैं इस सदन के सामने जरूर रखना चाहूंगा और वह यह है कि कल हमारे जनसंघ के माननीय मुखियाजी ने भी उस चीज पर सदन का ध्यान आकर्षित किया था कि कॉलेज एजुकेशन और यूथ्स के बारे में जो रिमार्क्स हैं वे वास्तव में इस प्रकार की चीजे हैं वे खटकने वाली हैं। क्या हम कॉलेज एजुकेशन से गांव वालों को वंचित करना चाहते हैं, गांव वाले तो गांव में ही रहें और शहरों में न आवें ? वहां भी खोल दीजिए, लड़के पढ़ेंगे तो सही। जो भाषा का प्रयोग है वह यह है।

"While we strive to provide full

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

employment to all citizens, we must also strive to eradicate the Psychological malady prevailing among the educated young men who are running after comfortable jobs in Government or private service.........."

आपकी जिम्मेदारी है कि यदि यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो उसको किस तरह से कम किया जाय। एक पढ़ा-लिखा ग्रेजुएट कॉलेज में से निकलता है। कोई एवेन्यूज़ नहीं खोलते हैं तो वह आपके पास आता है कि उसको आप नौकरी दीजिए। गवर्नमेन्ट सर्विस में जाता है। अगर आप उसके लिए दूसरे एवेन्यूज़ सर्विस के खोल देते हैं, टैक्निकल एजुकेशन के साधन बढ़ा देते हैं तो गवर्नमेन्ट सर्विस में क्यों आवेंगे, कोई पसन्द नहीं करता है; प्राइवेट बिज़नेस में जाना अधिक पसन्द करेंगे और खुद अपने साधनों से कोई कारखाना लगावेंगे। मुझे जो अधिक खटकने वाली चीज़ है वह यह है कि आप चाहते हैं कि शहरों के ही रहने वाले लोगों को सरकारी नौकरियां मिलती रहें, जिनको आज तक नौकरियां मिलती रही हैं उन्हीं को मिलती रहें, उन अधिकारियों के लड़कों को ही मिलती रहें और ऑफिसर्स क्लास के जो लड़के हैं वे ही उन कॉलेजेज़ वगैरह में पढ़ते रहें और नौकरियां प्राप्त करते रहें और कोई नहीं पढ़े; ऐसी भावना रहती है। लेकिन हमारी यह नीति रही है कि हम राजस्थान में शिक्षा को प्रगति देना चाहते हैं।

(१.५ म.प.)

(श्री नारायणसिंह, सभापति, पदासीन)

माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने यह कहा है। इसी दृष्टि से राजस्थान में सैनिक स्कूल खुला, टैक्निकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज कायम किये। माननीय वित्त मन्त्री महोदय एक तरफ तो कहते हैं कि इसकी जरूरत है और दूसरी तरफ इस प्रकार के कॉलेजेज़ की आवश्यकता है जो टैक्निकल कॉलेजेज़ हों, मेडिकल कॉलेजेज़ हों, एग्रीकल्चरल कॉलेजेज़ हों। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि हमारे यहां राजस्थान कॉलेज जैसे कॉलेज की क्या आवश्यकता थी, कौनसी उस एजुकेशन में सुरख्वाब के पर लगे हैं कि उस पर इतना खर्चा किया जाय? लड़कों को ऐसी कौनसी शिक्षा वहां दी जाती है? मैं समझता हूं कि इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन करने की आवश्यकता नहीं थी। वहां की जो हकीकत है उसको मैं स्वयम् भी जानता हूँ। इसलिए ट्रेनिंग दी जाती है कि लड़कों को आइ० ए० एस० में जाने के लिए अच्छी तालीम मिलेगी। लेकिन जिस तरह से यह है वैसा सम्भव नहीं है। यदि दिमाग है बच्चे का तो दूसरे कॉलेज में भी पढ़ कर वह बन सकता है। कोई वजह नहीं है कि इस प्रकार का कॉलेज अलग से चले। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की केटेगरी कायम करना जरूरी नहीं था। हो गई; चलाना है तो उसकी ओर जरा ध्यान दिया जाय। यदि कोई लेक्चरार फर्स्ट क्लास फर्स्ट हुआ तो उसको राजस्थान कॉलेज में रखा जाता है और यदि सेकन्ड क्लास हुआ तो उसको महाराजा कॉलेज में। नये नये आते हैं और वहां कॉलेज में भेज दिये जाते हैं। यदि यह होता कि महाराजा कॉलेज से जिसको पांच साल का टीचिंग का एक्सपीरियेन्स हो गया उसको राजस्थान कॉलेज में भेजा जावेगा तो यह

Page No 34

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

बात मानने योग्य थी कि अमुक लेक्चरार को वहां पर तब ही रखा जावेगा कि उसको पांच साल का टीचिंग एक्सपीरियन्स कॉलेज का होगा। यदि वहां कॉलेज में जाकर आप देखेंगे तो मालूम होगा कि आपको ऐसे लड़के मिलेंगे जो नये नये एम० एस०सी० पास करके जाते हैं। इसलिए इस चीज पर गौर किया जाना चाहिये।

एक चीज और निवेदन करना चाहूँगा वह इस बजट स्टडी से मिली है। पेज ३ पर एक फीगर दी हुई है जिससे हमें अपना पता लगता है। टैक्स रेवेन्यू सन् १९५१-५२ में ७२.५ थी और अब टैक्स रेवेन्यू है ६२-६३ में ५५.८। नॉन टैक्स रेवेन्यू ५१-५२ में २७.२ और अब ६२-६३ में २४.६। उसके साथ जहां तक उनके परसेन्टेज का ताल्लुक है कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन जिन्दा किस पर हैं? ग्रान्ट-इन-एड पर जो सन् ५१-५२ में ०.३ थी तो ६१-६२ में १९.६ है। आखिर इतने टैक्स लगाये, नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश की। फिर भी १९.६ पर ग्रान्ट-इन-एड के सहारे पर चलते हैं। इनका सहारा न हो तो कोशिश किस तरह से करें, यह पता नहीं। संक्षेप में मैं निवेदन कर दूं अपनी बात और वह यह है कि हमको इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है कि हम कर्जदार हैं या हमने ओवर ड्राफ्ट ले लिया है या और किसी तरह से आगे के लिए आमदनी नहीं होने वाली है। यह तो एक आंकड़ों का खेल है। फाइनेन्स मिनिस्टर महोदय ने या तो बताना मुनासिब नहीं समझा हो और मुनासिब समझा हो, फिर भी नहीं बताया हो। इधर बोलने वाले माननीय सदस्य ने और सबों ने कहा कि हमारे पेट पर पट्टी बांधना चाहते हैं। हो सकता है माननीय सदस्यों का यह खयाल हो। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। आमदनी इस साल, अगले साल और उसके बाद के सालों में भी बढ़ने वाली है। हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है। एक खतरा जो कुछ है, मेरे दिमाग में है, कह नहीं सकता कि वह कहां तक ठीक है, एक चीज़ से हमें डरने की जरूरत है वह यह है कि अगले दस-पन्द्रह साल में या बीस साल में इस ओवर ड्राफ्ट को हमें पेश करना पड़े। इन सारी स्कीम्स के ओपरेशन के बाद, प्रोडक्शन बढ़ जाने के बाद मुमकिन है कि वर्ल्ड टेन्डेन्सी ऐसी हो जाय कि जो चीजें आज हम एक्सपोर्ट करते हैं उनको वे मुल्क लेना बन्द कर दें कि अथवा और जगह कम्पीटिशन चले। तो गुन्जाइश जरूर है कि स्लम आ जाय। यदि सस्ता हो जायगा तो फिर इतनी बड़ी तनख्वाह न करके छोटी तनख्वाह कर सकते हैं। यह चीज़ अवश्य है, लेकिन यह खास खतरे की चीज़ नहीं है।

यह निश्चित बात है कि हमको इकोनोमी करनी पड़ेगी। काफी सब्स्टेन्शियल इकॉनोमी हमको करनी चाहिये। एम्प्लॉयमेंट का कोटा कम हो जायगा; नौकरियां कहां से मिलें। लेकिन हमको आदत खराब नहीं डालनी चाहिये। यदि नौकरी देना चाहते हैं तो दे दीजिये, लेकिन यह कहना कि एल०-डी० सी० बनाया जाता है, १००) रू० मिलेगा, केवल इतना ही काम है एक लैटर आया रिसीट का और एक लैटर आया डिस्पेच का; इनको रिसीट डिस्पेच कर देना। इसके माने

श्री बृजसुन्दर शर्मा)

हैं कि उस व्यक्ति को आप सुस्त बना देते हैं। उसकी काम करने की आदत छूट जावेगी। उसके अलावा और जरिये हैं उनको काम पर लगाने के।

इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि आज तक जितने रुपये लोन में एडवान्स करते हैं, राजस्थान गवर्नमेन्ट की ओर से लोन लिये जाते हैं तो काफी एडवान्स भी किये जाते हैं। इसकी रकम जो बनती है वह है १,०३९ लाख रुपया। १,०३९ लाख रुपयों की रकम में से अगर हम आधी भी अपने फायदे में खर्च करके अपनी इन्डस्ट्रीज़ में लगाते, मिनरल डेवलपमेन्ट आदि में लगाते तो हमारे राजस्थान की पोटेन्शियल वेल्यू को और केपिटल वेल्यू को अधिक बढ़ा सकते हैं; बनिस्पत उसके कि एक जगह एक कारखाना चल कर फिर वह बन्द हो जाय। इनको ७५ लाख, १ करोड़ रुपया दिया है, लेकिन कारखाने लगाने का काम नहीं। कारखानों के लिये, मशीनरी खरीदने के लिये, हायर पर्चेज़ के लिए जो रुपया दिया है वह इस १,०३९ लाख में से ही दिया गया है, उधार के रूप में दिया वह वैसे का वैसा जेब में पड़ा हुआ है। उससे कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता। आप जब पहले मशीनरी के लिये लोन देते हैं उससे मशीनरी आती नहीं और वह पैसा वैसे ही पड़ा रह जाता है। जिस तरह से हम कुंए के लिये लोन देते हैं उस हालत में जब पांच हाथ गहरा गड्ढा खोद लिया जाता है उस वक्त हम १००) रुपया देते हैं उसी तरह से इन कारखानों के लिये भी हम यह कर दें, आप इतने हजार रुपया इन्वेस्ट कर दो, फिर हमसे इतना रुपया ले जा सकते हो। लेकिन होता क्या है कि पहले हमें रुपया दे दो हम उसको इन्वेस्ट बाद में करेंगे। इससे होता क्या है कि हमें व्याज का नुकसान होता है। इस प्रकार के ट्रान्ज़ेक्शन्स हैं वे केपिलिस्ट कन्ट्रीज़ में हो सकते हैं। इस तरह के ट्रान्ज़ेक्शन्स हमारे यहां नहीं होने चाहिये। इस ओर हमें ध्यान देना चाहिये।

अन्त में सभापति महोदय, मैं फिर माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हमारी जो वित्तीय स्थिति है उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। आज हम जो विकास करते जा रहे हैं उस विकास की ओर हम बढ़ते जायेंगे, हमारे चरण हमेशा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे और इस तरह से हमारा यह राजस्थान प्रदेश अन्य सुसमृद्ध प्रदेशों की गिनती में आगे आकर रहेगा।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने अपने घाटे की पूर्ति के लिए कुछ नये टैक्सेज़ का प्रस्ताव भी रखा है। सभापति महोदय, हमारे हिन्दुस्तान में अब एक ऐसी मनोवृत्ति पैदा हो गई है कि हमारे यहां के जो भी अफसर बाहर अमेरिका या इंग्लैण्ड जाकर आते हैं, वहां जिस प्रकार की पद्धति से काम होता है और जिस तरह की तड़क-भड़क रहती है उसी तरह की पद्धति और तड़क भड़क वे यहां भी लाने की कोशिश करते हैं; उस तड़क-भड़क की पद्धति को वे यहां भी चलाना चाहते हैं। हम देखते हैं, उसी का परिणाम है कि हमारे राजस्थान में आलीशान बिल्डिंग बन रही हैं, उनमें सजावट का सामान खरीदा जाता है। माननीय सभापति महोदय, जब हम हमारे देश और

Page No 36

(श्री भीमसेन)

प्रान्त का विकास करना चाहते हैं, जब हमें विकास के लिए धन की आवश्कता होती है तो वैसी हालत में जो हम फिजूल खर्ची इन सजावट या बिल्डिंग्ज़ पर कर रहे हैं उसके बारे में सोचना और समझना पड़ेगा। हमें यह सोचना पड़ेगा कि जो हम सजावट बिल्डिंग्ज़ आदि पर खर्चा करने जा रहे हैं क्या उसमें कमी नहीं की जा सकती। सभापति महोदय, मैं समझता हूँ, हमारे देश की स्थिति को देख कर इस प्रकार के कार्यों में जो भी बचत हो सकती है वे उपाय काम में लेने चाहिये।

दूसरा, सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह करना है कि जैसा कि विरोधी पक्ष के वक्ताओं ने इस बारे में संकेत किया कि हमारा राज्य दिवालिया राज्य है, हमारे पर कर्जा बढ़ता जा रहा है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं........

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : विरोधी पक्ष का तो आज कोई सदस्य बोला ही नहीं।

श्री भीमसेन : विरोधी दल के नेता ने कल कहा था।

मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम देश का विकास करना चाहते हैं और हमारे पास साधन नहीं हैं तो वे साधन हमें जुटाने होंगे, चाहे हम उसके लिए टैक्स लगायें, चाहे उसके लिए कर्जा लें। इस पर एक शिकायत हो सकती है; वह यह है कि जितना पैसा हम लगाते हैं उसका अच्छी तरह से उपयोग हो, उसमें फिजूल खर्ची न हो, अपव्यय न हो; यह कहने की गुंजाइश हो सकती है। यह कहना कि उधार ले करके विकास करना चाहते हैं ठीक नहीं है। और यह कहना भी उचित नहीं कि जितने साधन उपलब्ध हैं उतने से ही काम चलायें। अगर हमारे पास साधन नहीं हैं तो वैसी हालत में जहां से भी साधन उपलब्ध हो सकें हमें जुटाने होंगे। जहां आज दूसरे प्रान्त हमसे आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम केवल अपने साधनों पर आधारित रहें तो हमारी क्या स्थिति होने वाली है ? हम उनसे पिछड़ जायेंगे।

सभापति महोदय, जिस वक्त राजस्थान बना था उस समय हमारे राजस्थान की क्या हालत थी ? यहां कुछ नहीं था। हमने ज़ोरों से शुरूआत की। जिस समय हमारी इनकम १५ करोड़ रुपया थी उस इनकम को बढ़ा कर हम ८७ करोड़ तक उस बजट को ले आये। जिसमें केपिटल एक्सपेन्डिचर, रेवेन्यू एक्स-पेन्डिचर दोनों मिला कर ८७ करोड़ के ऊपर बजट आता है। हमने इन दस वर्षों में कितनी प्रगति की है, यह इन आंकड़ों से स्पष्ट प्रतीत हो जाता है, इससे किसी भी प्रकार से इन्कार नहीं किया जा सकता। यहां आलोचना की जाती है कि जिस प्रकार से खर्चा किया जा रहा है और जिस गति से खर्च किया जा रहा है उस गति के अनुपात से हमें उसके रिटर्न्स बहुत कम मिल रहे हैं। सभापति महोदय, यह तथ्य सही नहीं है। जिस तरह से हमने फूड प्रोडक्शन के मामले में आत्म निर्भरता प्राप्त की है उससे अन्दाज लगाया जा सकता है कि जो सिंचाई के मद में खर्चा किया है उसके रिटर्न्स हमें प्राप्त हुए हैं।

(श्री भीमसेन)

इसके अलावा सभापति महोदय, एक सब से बड़ा खतरा हमारे सामने अवश्य है। उस ओर मैं इंगित करना चाहता हूं कि जिस गति से हमारे राजस्थान की जन-संख्या बढ़ रही है वह सोचनीय अवस्था है। इसके लिए हम राजस्थान के सेन्सस डिपार्टमेन्ट द्वारा जो १९६१ का सेन्सस हुआ उसके जो स्टेटिसटिक्स निकले हैं उससे अन्दाजा लगता है कि हमारे यहां की जन-संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है वह हिन्दुस्तान में सबसे अधिक है। परसेन्टेज जन-संख्या का हमारे यहां सबसे ज्यादा है। यह सोचनीय है हमारे लिए। हम किस तरह से उस बढ़ती हुई जन-संख्या को रोक सकेंगे; अभी से हम इस पर गम्भीरता से विचार नहीं करेंगे तो जितना हम खर्च करना चाहते हैं, सभापति महोदय, वह सब बेमाने हो जायगा। इसी तरह से चाहे कुछ हो इस पर हमें बड़ी गम्भीरता से विचार करना है। कम से कम शुरुआत में हम यह तो कर सकते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे हैं जो भिक्षा-वृत्ति करते हैं उनके लिए ऐसे सदन खोल दें जहां पर ऐसी व्यवस्था हो कि वे अपनी सन्तति आगे न बढ़ा सकें। इस तरह से भिखारियों को स्टेरलाइज़्ड करने की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो गंभीर बीमारियों से कॉन्टेन्जियस डिज़ीज़ से ग्रसित हैं उनको सन्तति पैदा करने के लिए रोक सकते हैं, उनको स्टेरलाइज़्ड करके उन पर रोक लगा सकते हैं। इसके साथ साथ लोगों में हम ऐसी भावना पैदा करें ताकि इस बढ़ती हुई बीमारी की गंभीरता को महसूस करें। अगर इसी प्रकार जन-संख्या बढ़ती गई तो जो हम करोड़ों रुपया योजनाओं पर लगा रहे हैं वह सब बेकार हो जायगा। इस तरह से जहां सरकार यह चाहती है कि लोगों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाया जाय वहां ऐसी हालत रही तो जीवन स्तर नीचे गिरेगा।

दूसरा, सभापति महोदय, मुझे जो निवेदन करना था वह यह कि हमें एक मामले में स्पष्ट हो जाना चाहिये। आज एक तरफ हमारे इस प्रदेश में भूखे लोग हैं और एक तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास किसी प्रकार की कमी नहीं। जो लोग भूखे हैं उनको रोटी-कपड़ा देना है, जिनके पास अधिक से अधिक साधन हैं उन साधनों के बारे में भी स्पष्ट होना चाहिये। आज हमारे स्टेट की पॉलिसी यह है कि एक तरफ तो कार के लिए लोन देते हैं, मोटर साइकिल के लिए लोन देते हैं, मीडियम इन्कम ग्रुप के नाम से मकान बनाने के लिए लोन देते हैं; लेकिन दूसरी तरफ किसान को बैल खरीदने के लिये पैसा नहीं मिलता, जिसके बारे में हमें सोचने की आवश्कता है। इस बारे में स्पष्ट नीति को लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से विकास कर पायेंगे और लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठा पायेंगे। इस तरह से हमारी नीति स्पष्ट होनी चाहिये तभी हम आगे बढ़ सकेंगे।

सभापति महोदय, मुझे तो यह लगता है कि कर दाता कर देने में पीछे नहीं रहेगा, पर उसको यह विश्वास होना चाहिए कि उसके कर देने से जो पैसा इकट्ठा होता है उसका अच्छे से अच्छा उपयोग हो; फिजूल खर्च न हो, योजनाबद्ध खर्चा हो और उसके दुरुपयोग पर पूरा पूरा अंकुश हो।

(श्री भीमसेन)

मैं कुछ उदाहरण इस दुरुपयोग के दूं। जैसे राजस्थान कैनाल में कोलोनाइज़ेशन हो रहा है और लैंड अलॉट हो रही है, वह प्रति वर्ष होती है जब कि वे निश्चित रूप से यह जानते हैं कि ७० से पहले वहां पानी नहीं आने वाला है। तो फिर वे एक साल के बजाय चार साल या अधिक के लिए क्यों नहीं अलॉट करते? इससे वहां के स्टाफ का खर्चा भी बचेगा और किसानों को दरख्वास्तें देने में जो दिक्कतें और खर्चा होता है उससे वे काश्तकार भी बच जाते। सड़कें, बिल्डिंगें, बांध वगैरह बनते हैं, पर बराबर देख–भाल उनकी नहीं होती और वे बनने के थोड़े दिन बाद ही टूट-फूट जाते हैं या खराब हो जाते हैं। तो इस तरह मशीनरी जो यह काम देखती है उसे ठीक किया जाना चाहिए। अगर उनकी गलती हो तो उनको सख्त से सख्त सजा इसके लिए दी जानी चाहिए।

दूसरा, सभापति महोदय, वित्त मंत्रीजी ने यह संकेत किया है कि म्यूनिसिपेलिटियों के एड के मद में बढ़ोत्तरी करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस टैक्स का भार देहाती लोगों पर अधिक पड़ता है। राजस्थान में तो और राज्यों से भी अधिक लैंड रेवेन्यू का भार कृषक पर पड़ता है। इसको देखते हुए म्युनिसिपेलिटियों को जो आप एड देते हैं उसका प्रोपोर्शन ।।।) पर हैड आता है और पंचायतों को जो आप देते हैं उसका बीस नये पैसे। तो यह भेदभाव क्यों? यह समझ में नहीं आता। देहाती लोग अधिक टैक्स देते हैं तो उसका डिस्ट्रिब्यूशन भी उसी प्रोपोर्शन में होना चाहिए। म्युनिसिपेलिटियों के प्रति एक नजर देखते हैं और जहां पंचायतें हैं और जो नई नई अस्तित्व में आई हैं और जो डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन की बैकबोन हैं उनकी तरफ आप दूसरी नजर से देखते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : यह कांग्रेस के समाजवाद का नमूना है।

श्री भीमसेन : और भी हम बचत कर सकते हैं। डूंगरपुर जिला है, बीकानेर जिला है, बहुत छोटे छोटे हैं। तो इसी तरह तहसीलें हैं इनको आप रिऑर्गेनाइज़ करके इनके खर्चे में कमी कर सकते हैं। दूसरे गैर जरूरी खर्चे, जैसे मैंने बताये बिल्डिंग के हैं और हैं वे भी आप कम कर सकते हैं।

इसके साथ साथ एक समस्या हमारे इलाके में है पीने के पानी की। कुओं के लिए आप काफी रुपया देते हैं, पर वह बेकार जाता है, क्योंकि पैसा खर्च करके कुंआ खोदते भी हैं तो पानी खारा निकलता है। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप हर साल जो कुओं पर इस तरह से व्यर्थ पैसा खर्च कर रहे हैं उसको एक साथ ही आप लूणकरणसर और इसके आस–पास का एरिया नहरी इलाके के समीप पड़ती है; आप नहर से पानी ला सकते हैं और सारे गांवों को पहुंचा सकते हैं। इस तरह से स्थाई रूप से पानी की समस्या का हल खोजा जा सकता है। आप नहर से पानी लिफ्ट करके ही इस समस्या का हल कर सकते हैं। इसमें अधिक पैसा भी खर्च नहीं होगा, जितना आपका कुओं के अन्दर हर साल खर्च हो रहा है।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री

(श्री परसराम मदेरणा)

शिक्षा): एरिया नहर से दूर कितना रह जाता है ?

श्री भीमसेन : केवल तीस मील । यह दूरी अधिक नहीं है । बहुत दूर दूर से पानी लाकर कई अन्य शहरों में आपने दिया है और देने की आपकी स्कीमें हैं ।

इसके साथ ही आप अपने खर्चे को और तरीकों से कम कर सकते हैं । हमने संविधान में यह प्रोविज़न किया था कि दस साल के भीतर भीतर शासन का सारा काम-काज हिन्दी में कर देंगे । पर आज १४ साल के बाद भी आपका काम दुहरा चल रहा है । एक तरफ अंग्रेजी चलती है, दूसरी तरफ हिन्दी । तो हिन्दी को कर देने से आपका यह दुहरा खर्चा भी कम हो सकता है । तो सरकार को इस दिशा में अपनी दृढ़ नीति अपनानी चाहिये । सारा काम हिन्दी में होने पर आप दोहरे खर्चे से बच सकते हैं । नये टैक्सों के संबंध में जो प्रस्तावित किये गये हैं उनमें सबसे पहले मैं पशुओं के टैक्स के बारे में निवेदन करना चाहूँगा । किसान अपनी खेती के लिए पशुओं का आपस में लेन-देन करता है । अगर आप इस पर टैक्स लगाते हैं तो सवाल पैदा होगा कि इसे कलेक्ट करनेवाली आपकी कौनसी मशीनरी होगी ? क्या इससे किसान की परेशानी नहीं बढ़ जावेगी ? वह अनपढ़ है, हिसाब-किताब रख नहीं सकेगा और इस तरह क्या आपकी नौकरशाही मशीनरी उसको और अधिक हैरान नहीं करेगी ? तो किसान के लिये भी यह परेशानी का बायस होगा और सरकार के लिये भी कि इसे वसूल कैसे करेगी ।

मेलों लगते हैं । आपने इन मेलों का प्रबंध पंचायतों को ट्रान्सफर कर दिया है । अब पंचायतें और पंचायत समितियां भी अपने अपने टैक्स लगाती हैं और सरकार भी लगाती है । तो क्या यह किसान पर दोहरा टैक्स नहीं होगा । हां, अगर बाहर जाने वाले जानवरों पर यह टैक्स है तो सोचने की बात हो सकती है ।

इसके अलावा, सभापति महोदय, जो पैसेन्जर टैक्स लगाया हैं वह भी अनुचित है । इसका भार सीधा जनता पर बहुत अधिक पड़ेगा । हमारे यहां ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां रास्ते बड़े खराब हैं और जहां मोटर चलाना आज भी बड़ी तवालत का काम है, वीयर और टीयर का खर्चा आज भी उनका काफी है । आज टार रोड पर चलने वाली बसों पर भी वही रेट से टैक्स और बड़े बड़े टीलों में लम्बा-चौड़ा वीयर और टीयर बर्दाश्त करके चलने बसों पर भी वही रेट से टैक्स ! तो सरकार को इस पर भी सोचने की आवश्यकता होगी ।

दूसरा आपने ग्राम या कॉटन सीड पर जो टैक्स लगाया है उसका भार भी सारा देहात के आम लोगों पर पड़ेगा । अगर इसमें रियायत कर सकें तो अच्छा है, सरकार को इस पर सोचना चाहिए ।

इसी तरह बिल्डिंगें हुईं, लग्ज़री आइटम्स हुए इनके खर्चे में बचत करके चलें तो अच्छा होगा । इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री परसराम मदेरणा : लग्ज़री आइ-टम्स से आपका क्या मतलब ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभा-

(श्री मुरलीधर व्यास)

पति महोदय, वित्त मन्त्री महोदय ने जो बजट हमारे सामने रखा और उस पर जो महानुभाव बोले और खास कर आज के कांग्रेस पक्ष से जो बोले, खुशी है कि उन्होंने विरोधी पक्ष की कुछ ऐसी बातों पर जो उनकी नीति से मेल खाती हैं, खुशी प्रकट की।

मुझे इसकी खुशी है कि सभी महानुभावों ने जो नये टैक्स लगे हैं उनका बहुत ज्यादा विरोध किया है और कहा है कि समाजवादी समाज-रचना के और उसकी रीति-नीति के ये टैक्स अनुकूल नहीं हैं।

हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने बजट रखा तो बजट रखते समय जो उन्होंने अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से कही कि टैक्स वह गोली है जो हमें कड़वी जरूर लगती है पर इसलिए गले के नीचे उतार लेनी चाहिए क्योंकि इससे हमारा राज्य रूपी शरीर गरीबी के रोग से छूट कर चंगा होगा।

कड़वी के कारण कुछ ऐसी छूट दी और ऐसा कहा कि शुगर-कोटेड है, यह ठीक है, हर आदमी इसको ठीक तरह से ले सकता है।

अभी हमारे वित्त मंत्री तो उपस्थित नहीं हैं; लेकिन हमारे उप-मंत्री उपस्थित जरूर हैं क्योंकि वे भी हमेशा समाजवाद की बात करते थे और मुझे खुशी है कि उन्होंने हमेशा समाजवाद की बात को कह कर सरकार को बताने की कोशिश की है कि हमें समाजवाद के रास्ते पर चलना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस मौके पर क्योंकि अब चलने और चलाने का मौका आया है तो वे भी इसका ख्याल रखेंगे और हमारे बजट द्वारा सचमुच समाजवाद के रास्ते पर चलने की कृपा करेंगे। जहां तक बजट का सवाल है इसके सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री महोदय ने हमारे राजस्थान के आर्थिक ढांचे को बहुत अच्छी तरह से देखा और उस आर्थिक ढांचे को देख कर जिस प्रकार की परिस्थिति थी उसके अनुसार उसके अन्दर सारी बातों को बहुत सफाई के साथ रखा और कहा कि राजस्थान की जो आर्थिक स्थिति है वह ऐसी गिर चुकी थी कि जिसको सम्भालना बहुत कठिन था और उसको केन्द्रीय सरकार ने कुछ सहयोग देकर सम्भाला। इसके संबंध में जब मैंने गए बजट के सम्बन्ध में एक लफ्ज़ कहा था कि राजस्थान की जो आर्थिक स्थिति है वह एक दीवालिया की सी स्थिति है उस समय कुछ रंज भी प्रकट किया गया था लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि उस समय चाहे माना हो या नहीं माना हो, लेकिन अब की से आनेवाले मन्त्री महोदय ने उसको अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। यह परिस्थिति तो आज नहीं पहले भी खराब थी। और इस सम्बन्ध में जो जन-लेखा समिति को रिपोर्ट १९६१-६२ की दी गयी थी उसमें इसका उल्लेख था। मैं उसको थोड़ासा पढ़ कर जरूर सुनाना चाहता हूं। यह जन लेखा-समिति का छठा प्रतिवेदन है। इसमें समिति ने अपनी राय प्रकट की थी और उसके बारे में जो वित्त जांच समिति; उक्त प्रतिवेदन के अनुसार वित्त आयोग ने कहा है कि यदि राजस्थान के बजट को संतुलित रखना है तो ऐसा करना योजना की अवधि; के पिछले दिनों कदाचित असम्भव होगा जब तक प्रशासनिक व्यय में अधिकतम

(श्री मुरलीधर व्यास)

नियन्त्रण रखने के अतिरिक्त विकास सम्बन्धी व्यय पर भी नियन्त्रण न रखा जाये और उसे प्राप्त साधनों के अनुसार न रखा जाये। यदि ऐसा नहीं हुआ तो राजस्थान बजट पर अत्यधिक भार पड़ेगा और चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यह १९५९-६० में ही जो वित्त आयोग था उसने राजस्थान के सम्बन्ध में कहा था और उसी समय १९५९-६० में अगर राजस्थान अपनी आर्थिक स्थिति को संभालता और अपने प्रशासनिक ढांचे में कुछ खर्च की कटौती करता और उसको व्यवस्थित करता तो वह स्थिति पैदा नहीं होती। परन्तु राजस्थान सरकार ने जैसा कि अभी हमारे भूतपूर्व वित्त मन्त्री महोदय ने कहा कि जो भी इसके जिम्मेवार लोग थे उन्होंने इस सारी स्थिति को ठीक तरह से नहीं संभाला; यह उसी का परिणाम है कि आज हमें यह दिन देखना पड़ा।

मैं राजस्थान के आर्थिक ढांचे के सम्बन्ध में इतना कहना चाहता हूं कि हमने हमारे देश में लोकतन्त्र स्वीकार किया औरफिर लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ ही साथ एक योजना का युग प्रारम्भ किया। योजना के युग में हमारा दृष्टिकोण यह रहता है भी कि हम किस प्रकार से अपने राज्य के लोगों का विकास करें और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है तो वह वित्त मन्त्री महोदय के ऊपर होती है। हमारे राज्य की जो योजनायें हैं उन योजनाओं के अनुसार किस प्रकार से हम अपने खर्चे के ढांचे की व्यवस्था बैठायें जिससे राज्य के हर आदमी का विकास हो सके और योजना का जो मुख्य लक्ष्य समाजवाद है उसको प्राप्त करें? यह पब्लिक फाइनेन्स होता है, यह बनिये का फाइनेन्स नहीं होता। इसका दृष्टिकोण एक ढंग का होता है और उसमें ज्यादा से ज्यादा जिम्मेवारी हमारी यह होती है कि हम जिस जनता से पैसा लेकर खर्च कर रहे हैं उसमें एक एक पाई का भी यहां तक हिसाब रखना पड़ता है कि इसका दुरुपयोग न हो और इस पाई के खर्चे का ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए किस प्रकार से उपयोग होता है, यह हमारा पब्लिक फाइनेन्स लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था के अन्दर होना चाहिये और यदि इस व्यवस्था के आधार पर नहीं होता है तो ठीक है, हम यह कह सकते हैं कि हमने समाजवाद को स्वीकार किया है, हम यह भी कह सकते हैं कि हमें विकास के दृष्टिकोण से आप सहयोग दीजिए, हम यह भी कह सकते हैं कि आप पेट पर पट्टी बांध कर भी हमें सहयोग दीजिए। हां, जहां तक पेट पर पट्टी बांधने का सवाल है एक समाजवादी कभी यह सोच भी नहीं सकता कि अपने नागरिकों को कहे कि पेट पर पट्टी बांध कर भी टैक्स दो। इसका मतलब तो यह हुआ कि आप खाओ नहीं और टैक्स दो। अगर खायेगा नहीं तो टैक्स कहाँ से देगा? तो आप मारनातो नहीं चाहते? समाजवाद तो हर आदमी की उन्नति चाहता है और वह अगर यह कहें कि पेट पर पट्टी बांधो तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई इसे समाजवाद कहता है तो वह समाजवाद नहीं है। हो सकता है, आप कहें कि हमें त्याग करना पड़ेगा पर पेट के पट्टी बांधने की बात हमें नहीं करनी चाहिये। इसके अतिरिक्त आप यह कहते हैं कि हमें पेट पर पट्टी बांध कर भी थोड़ा बहुत टैक्स देना

(श्री मुरलीधर व्यास)

पड़ेगा। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आज एक बनिये और डॉक्टरों में फर्क होता है। बनिया तो अपने ग्राहकों से इस प्रकार की बात करेगा मीठी मीठी जिससे वह ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार शोषण कर सकता है और अपने घर में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा रख सकता है; परन्तु डॉक्टर का दृष्टिकोण पैसे लेने का जरूर होता है पर साथ ही साथ चंगा करने का दृष्टिकोण भी उसका होता है। वह कम से कम उसका शोषण तो नहीं करता। मैं चाहता हूं कि हमारे वित्त मन्त्रीजी ऐसे डॉक्टर बनें कि जिससे जो मुल्क में स्थिति है उसमें सब को चंगा करें। केवल टैक्स लगाकर ही जनता को चंगा कर सकते हैं तो मैं आपको डॉक्टर तो नहीं कह सकता। ठीक है, मैं यह कह सकता हूं कि व्यापारिक तरीके से अपनी बात कही जा सकती है, लेकिन आज सही माने में यह होना चाहिये कि हमारा दृष्टिकोण आम लोगों को चंगा करने का, अच्छा करने का होना चाहिये और उसके लिए हमारा जो टैक्स लगाने का तरीका है वह दूसरी तरह का होना चाहिए।

आज हमारे समाज की अवस्था बड़ी विचित्र है। समाज में एक ओर ऐसा अंग बैठा है जिसके पास खाने को नहीं है और एक ओर ऐसा अंग है जिसके पास बहुत ज्यादा है। अगर हम दोनों अंगों को ठीक तरह से नहीं समझते हैं तो मुल्क चंगा नहीं हो सकता— अभी एक किताब में मैंने पढ़ा उसमें डॉक्टर ने कहा कि सबको चंगा करने का इलाज और उसके लिए छोटी सी बात कह दी। डॉक्टर साहब, किसी मिल मालिक की पत्नि की तबीयत खराब थी उनको देखने गये तो वहां जाकर उन्होंने उनसे पूछा कि इन पर कितना खर्चते हैं, क्या खाती हैं तो उन्होंने कहा कि सबेरे, दोपहर को और शाम को यह खा लेती हैं और दूध, फ्रूट वगैरह ले लेती हैं। यह सुनने के बाद डॉक्टर ने कहा कि अच्छा मैं कल दवा दूंगा। वे डॉक्टर साहब जब बंगले से नीचे उतरे तो दरवाजे के ऊपर एक चौकीदार बैठा था। चौकीदार ने भी झट डॉक्टर साहब के पास आकर कहा कि मेरी पत्नि बीमार है उसको भी देख लें। डॉक्टर साहब ने उसको देखा और देखने के बाद वे चले गये। उन्होंने मन में सोचा कि एक ओर तो एक आदमी ऐसा है कि जिसको बहुत खाने को मिलता है इसलिए बीमार पड़ा और दूसरी ओर ऐसा है कि जिसे खाने को नहीं मिलता इसलिये बीमार है, अब इनको कैसे चंगा करूं। आने के बाद दूसरे दिन सेठ से मिला और कहा, सेठ साहब एक सुझाव मैं देता हू और वह यह है कि जो कुछ भी आप खाते हैं और पीते हैं वह धर्म के नाम पर, या और किसी तरीके से, जैसा कि आप मानते हों, वैसे का वैसा खाना अपने चपरासी की औरत को दे दें और चपरासी की औरत जो खाना खाती है वह आपकी पत्नि को दे दें। वह जानता था कि सेठ की पत्नि को तो ज्यादा खाने की वजह से संग्रहणी की बीमारी थी और चपरासी की औरत को पूरा खाना नहीं मिलता था इस कारण उसको टी० बी० हो रही थी। तो परिवर्त्तन कर दिया खाने का। परिवर्त्तन हुआ और महीने भर के बाद में दोनों चंगी हो गईं। आज आपको भी अगर इस राज्य को चंगा करना है तो चंगा करने में आज हमारी हालत यह हो गई। अगर

(श्री मुरलीधर व्यास)

आप इस तरीके से चंगा करना चाहें कि कड़वी गोलियां शक्कर चढ़ी हुई को गटक लें तो चंगा हो जायगा तो वह कड़वी भी मरीज को देते हैं जिनके पास दवा का पैसा देने की स्थिति नहीं हैं और जिनके पास नहीं है उनको गोलियां देते हैं तो उसका असर नहीं होगा जब तक कि उनको खाना नसीब नहीं होगा। तो आपको नीति यह बनानी चाहिए कि जिससे हमारे मुल्क का हर आदमी चंगा हो। आज हमारे यहां पर इसके बिल्कुल विपरीत काम हो रहा है। उससे देश के लोकतन्त्र को खतरा है।

१५ साल के बाद में आप जांच करने की बात कहते हैं कि देश की दौलत बढ़ रही है, पैसा बढ़ रहा है पर वह कुछ मुट्ठी भर लोगों की जेबों में चला जा रहा है और दूसरे लोगों को पूरा खाने को नसीब नहीं होता है। यह वस्तुस्थिति है। यह वस्तुस्थिति १५ साल से चली आ रही है; और भी हमने सुधार किये हैं फिर भी वही पुरानी बात है जो १५ साल से चली आ रही है कि टैक्स लगाओ तो हर आदमी पर टैक्स लगाओ और ऐसे लोगों पर भी लगाओ जिनके पास में पूरा खाने को भी नहीं है। उन पर लगाने से अगर देश चंगा हो जाय तो मैं नहीं समझता हूं कि चंगा हो जायगा। आपके सामने दो चीजें हैं। एक यह खड्डा है और एक टीला है और आप कहते हैं कि हम तो सपाट मैदान करना चाहते हैं तो सपाट मैदान करने में गड्ढे में से मिट्टी निकालते हैं और टीले के ऊपर से मिट्टी लेकर कहते हैं कि खड्डे को बूर देंगे और सपाट हो जायगा और समाजवाद आ जायगा, लेकिन उसका नतीजा यह होगा कि खड्डा और ज्यादा गहरा होता जायगा और हो सकता है कि मिट्टी का तीसरा बन जाय, पर सपाट नहीं हो सकता। समाजवाद नहीं आ सकता। तो एक बुनियादी नीति को स्वीकार करना पड़ेगा।

आज बहुत से लोग कहते हैं और हमारे जनसंघ से आने वाले दूसरे साथी कल कह रहे थे कि समाजवाद तो क्या है? समाजवाद में हम यह चाहते हैं कि जिनकी हालत अच्छी है वह हालत अच्छी रहे। मैं इस नीति को नहीं मानने वाला हूं। मैं तो कहता हूं कि जिनके पास में बहुत ज्यादा हो उनसे ज्यादा से ज्यादा लो। आपका दृष्टिकोण यह बनना चाहिए, आपके बजट का तरीका यह होना चाहिए कि जिसके पास बहुत ज्यादा हो उससे ज्यादा से ज्यादा ले सको और लेकर उस खड्डे को भरो। वह जो कमजोर हो उसको ज्यादा से ज्यादा दे सको। अगर यह नीति नहीं बनायेंगे तो मैं तो कहता हूं कि हो सकता है कि वर्षों तक यह बजट चलता रहे और ऐसी परम्परा चलती रहे और जैसा कि भूतपूर्व वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि परम्पराओं को बदलना चाहिए, मैं भी यही कहता हूं कि यदि आपने परम्पराओं को नहीं बदला तो आने वाले समय में समाजवाद की बात तो कर सकते हैं लेकिन समाजवाद जनता को दे नहीं सकते। समाजवाद देने के लिए आपको अपने रास्ते को परिवर्तित करना पड़ेगा। आपको भी दूसरे साधनों का उपयोग करना पड़ेगा जिससे कि सही मायने में समाजवाद आ सके।

आप किसी भी दूसरे मुल्क में चले जाइयेद

(श्री मुरलीधर व्यास)

जहां समाजवादी व्यवस्था है तो उन देशों में प्रोडक्शन बढ़ा है। प्रोडक्शन के साथ में आय भी बढ़ी है और साथ में विषमता भी दूर हुई है। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय आय तो बढ़ी है लेकिन पैसा कुछ लोगों के पास गया है। यूरोपियन राष्ट्रों में राष्ट्रीय आय हर साल १५०,२००) तक बढ़ रही है तो हमारे यहां हिन्दुस्तान में ८ रुपये बढ़ी है। वह बहुत कम बढ़ी है। इसको हम प्रोग्रेस तो नहीं कह सकते, वह भी १५ साल में।

दूसरी बात, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि विदेशों से जो माल आता है, निर्यात होता है उसकी कीमत बहुत घट गई है, इसलिए वहां फर्क आया है। मेरी समझ में नहीं आता कि विदेशों से निर्यात होने के बाद प्रति व्यक्ति की आय बढ़ जाती है और भाव कम होते हैं। अगर भाव कम होते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की आय नहीं बढती है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ रही है।

विकास वगैरह के दूसरे मामले बहुत से हैं। एक अमेरिकन ने जिसने सारे एशियाई कन्ट्रीज़ के विकास के बारे में लिखा है तो उसने २७ देशों का नक्शा पेश किया है और उन २७ देशों में हिन्दुस्तान का भी नक्शा पेश किया है। उसने बताया है कि कौन से नम्बर पर किस देश की योजनाएं आती हैं और कौन सा देश सबसे ज्यादा आगे बढ़ा है। उसने हिन्दुस्तान का नम्बर २७ देशों में से २४ वां नम्बर रखा है। अब हम कितने पीछे हैं ? एक मास्टर कहता है कि २७ लड़के पढ़ते हैं और बहुत पढ़ा पढ़ा कर होशियार कर दिया है और नम्बर पूछें तो २४ वें नम्बर पास होता है और कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा पढ़ा दिया है ! यही हमारे मुल्क की आज हालत है। इस हालत को देखते हुए हमारे यहां की वस्तुस्थिति को देखना पड़ेगा और नये परिवतन लाने पड़ेंगे।

आज जैसा कि पहले एक निर्णय लिया था कि हमारा जो बजट है उसके अन्दर प्रशासन के खर्चे को कम करेंगे और इन आँकड़ों के बारे में मैं कहता हूं कि जैसा कि एक सम्मानीय सदस्य ने कहा कि १२ साल में आंकड़े प्राप्त होने लगे हैं; पहले तो कुछ था ही नहीं। मैं मानता हूं कि यह अच्छी बात है। लेकिन मैं आंकड़ों का उदाहरण रखना चाहता हूं कि हमारे राज्य में यह कहां प्रशासन में खर्चा कम हुआ है पहले से। मैं तो कहता हूं कि प्रशासन का खर्चा जैसे बजट बढ़ता जाता है वह खर्चा भी बढ़ता जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि बजट बढ़ता है विकास के काम में ज्यादा से ज्यादा पैसा लिया इस कारण से। प्रशासन के काम में इस प्रकार से खर्चा बढ़ता चला जाता है, चाहे पुलिस का खर्चा हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा हो, चाहे जस्टिस का खर्चा हो। मुझे आश्चर्य हुआ जब पुलिस के खर्च को देखने लगा तो। पुलिस का खर्चा २१७ लाख ५१-५२ के बजट में था और हमारा आज का पुलिस का खर्चा करीब ५३८ लाख का है। इसके अन्तर्गत अब वह ढाई गुना हो गया है। खर्चा ज्यादा क्यों हुआ ? हम पूछें तो कहेंगे कि खर्चा तो बढ़ता चला जाता है लेकिन तारीफ यह कि ज्यों ज्यों खर्चा बढ़ता जाता है लोगों की दिक्कत बढ़ती जाती है और पुलिस से

(श्री मुरलीधर व्यास)

राहत नहीं मिल रही है। आप कहेंगे कि राहत मिलती है, पहले से बहुत राहत पहुंची है; तो ऐसा है कि आपकी बात मान लें तो भी उनकी राहत का प्रमाण क्या है ? यह प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट है, इसमें मैंने देखा है कि हमारी पुलिस का काम ठीक हुआ है, अपराध कुछ कम हुए हैं तो इसमें अपराध बताये गये हैं, अलग अलग जिलों में कब कब, किस किस साल में कितने २ अपराध हुए हैं उसका टोटल बताया गया है। २०,००० अपराध पहले होते थे और अब १०,००० अपराध होते हैं। यह इस रिपोर्ट के अन्दर जो कि ५८-५९ की है इसमें ५२ से लेकर ५८—५९ तक के आंकड़ेदिये हैं और यह बतलाने की कोशिश की गई है कि पहले अपराध ज्यादा होते थे और अब अपराध कम हो गये। मेरी समझ में नहीं आता कि जब अपराधों की संख्या कम हो रही है और अपराध कम हो रहे हैं तो पुलिस तो अपराध कम कराने के लिये रखी जाती है और जब अपराध कम हो गये हैं तो पुलिस पर आपका खर्चा क्यों बढ़ता रहना चाहिये ? अरे भाई, जब अपराध ही आधे हो गये लोग गड़बड़ नहीं करते हैं तो आपका खर्चा क्यों २ करोड़ से ५ करोड़ ३५ लाख हो गया और यदि आंकड़े अपराधों के देखें तो पहले २०,००० थे उसके बजाय अब १०,००० ही रह गये हैं तो जब अपराध कम होते हैं, आदमी अच्छे हो गये हैं, ठीक ढंग से काम करते हैं, अपराध करते नहीं हैं आपके राज्य में, तो बजट आपका क्यों बढ़ता है ? और जब बजट आपका बढ़ता है तो फिर साथ ही साथ यह देखना होगा कि अपराधियों को निकाल कर उनका क्या किया जाता है ? उनको कोर्ट में भेजा जाता है। जब अपराधी कम हो गये तो आपका न्याय का खर्चा भी कम होना चाहिये। इसके जो आंकड़े बजट में दिये हैं उनको देखें तो पता चलेगा कि ३८ लाख से ५६ लाख हो गये हैं। यह इसके अंदर दिया है। पुलिस का दिया है। पहले था २६१ लाख ५१-५२ में, इसमें ५१-५२ का दिया है, यह न जाने क्यों बढ़ गया ? लेकिन सरकार की रिपोर्ट में दिया है। प्राक्कलन समिति को २ करोड़ ४० लाख बताया है और इसमें २ करोड़ ६० लाख दिखाया है। समझ में नहीं आता कि यह २० लाख का फर्क कैसे आता है; लेकिन इसको मान लिया जाय तो भी दूसरी ओर ५ करोड़ ३३ लाख दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में ३५ लाख मिला था वहां बढ़ कर ५८ लाख हो गया। वहां भी खर्चा बढ़ गया, अपराध कम हो गये तो वहां भी खर्चा कम होना चाहिये, पर वहां भी कम नहीं हुआ। तोसोचा शायद जेल का भी खर्चा कम हुआ होगा। वहा देखते हैं तो वहां भी कम न होकर बढ़ गया। पहले था २३ लाख का अब हो गया ३७.७ लाख का। मैं यह सोचता हूँ कि आखिर आंकड़े किस आधार पर बनाते हैं ? जहां आपने अपनी सुरक्षा को बढ़ाया और अपराध कम हुए हैं तो ये दिन-दिन बढ़ते क्यों जा रहे हैं ? यदि आपके कहे अनुसार कमती हुए हैं तो खर्चा कम होना चाहिये, लेकिन खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। यह नीति की बात है।

आज कोई सरकार आंकड़े कम बताती हैं तो मैं कहता हूँ कि आंकड़ों का जाल सरकार आंखों में धूल झोंकने के लिये बिछाती है, सच्चे आंकड़े नहीं बताती। जब आपका काम ठीक हो रहा है तो खर्चा कैसे बढ़ रहा है, यह

Page No 46

(श्री मुरलीधर व्यास)

समझ में नहीं आता। लेकिन यह सरकार की हर मामले में नीति है। आप एडमिनिस्ट्रेशन को लीजिये, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को लीजिये और उसके खर्चे को देखिये। आपका पहले खर्चा ५१-५२ में देखिये, ५७ तक का देखिये, फिर आप विकेन्द्रीकरण करते हैं फिर घोषणा करते हैं कि कमिश्नरियें हटा दी जायेंगी,यह खर्चा कम करेंगे वह खर्चा कम करेंगे लेकिन बजट आता है, डयोढ़ा और दूना बढ़ता रहा है। यह वस्तु स्थिति है, आप मानें या न मानें। इस लोकतंत्र में १० साल से हम हमारे राज्य का बजट बनाते हैं और हम चाहते हैं कि लोकतंत्र का बजट बनावें लेकिन हमारे ऊपर नौकरशाही हावी हो गई है। वह जैसा चाहे वैसा बजट बन जाता है। वह जैसा चाहे वैसी तरक्कियें हो जाती हैं। मैं जनलेखा समिति में देखता हूं कि किसी ऑफिसर की तनख्वाह ८००) से १,२००) रु० कर दी। इस पर जनलेखा समिति पूछती है कि यह कैसे कर दिया तो वहां पर जवाब दिया जाता है कि साहब, ऐसा था कि उस समय वह पुराने राज्य के फलां पद से आया था और वहां पर इतनी तनख्वाह पाता था अब इसको कम करना मुश्किल है। यह जनलेखा समिति की रिपोर्ट में आता है। ८००)से १,२००)रु० कर दिये; दो साल तक ले लिये; अब कम कैसे करें ? आखिर जनलेखा समिति का फैसला होता है कि अच्छी बात है कर दिये सो कर दिये, ले लिया सो ले लिया; अब लेते रहें।

मैं तो कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में इन आंकड़ों के बारे में सोचना पड़ेगा, यदि समाजवादी ढांचा बनाना है। एक तरफ चपरासी को देखते हैं तो उसका ४५ से ७०)रु० तक का ग्रेड है और दूसरी तरफ बड़े बड़े अधिकारियों का ग्रेड २,५००रु० रखा गया है। इस अंतर को भी हम कम करना चाहते हैं। किस देश में ऐसा है कि एक आदमी को ४५ रु० मिले और दूसरे आदमी को १,८०० रु० मिलें। अभी वित्त मंत्रीजी ने कहा था २५० रु० अलग मिलते हैं, दूसरी और ग्रेड २,५०० रु० तक का भी है। यह ढांचा हो सकता है, बहुत पहले का हो। यदि समाजवादी राज्य को अपनाना चाहते हो तो इतना बड़ा अंतर रहने का नहीं है। किस देश में इतना अंतर है ? आप यूरोपीय देशों का उदाहरण सामने रखिये। स्वीडन में जाइये, डेनमार्क में जाइये, जर्मनी में जाइये और वहां देखिये कि कितना अंतर है, १ : ३ या १ : ५ का अनुपात मिलेगा। स्वीडन में १ : ३ का अनुपात है। वहां पर एक भंगिन ४०) रुपये रोज पाती है और हमारे हिन्दुस्तान में ४०) रुपये माहवार भी उसको नहीं मिलते। उसके लिये हड़तालें करनी पड़ती है, जेल में जाना पड़ता है, मारा जाता हैं, पीटा जाता है, उसके बाद भी कहते हैं कि फैसला क्यों नहीं होता; तो भी फैसला नहीं होता। आज यह हमारे राज्य की वस्तु स्थिति है; मैं चाहता हूं कि मंत्रीजी इस लाइट में सोचें। यदि समाजवादी समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो सीमा निर्धारित करनी होगी; अनुपात १ : १० से अधिक का नहीं होगा। इस कानून को बनाने में आपको क्या दिक्कत आती है ? क्योंकिआपने ज्यादा से ज्यादा बहुत बढ़ा दिया अब उसको कम करने में दिक्कत आती है, हमारा कॉन्स्टीट्यूशन कहता है कि ज्यादा कर दिया उसको कम नहीं कर सकते।

(श्री मुरलीधर व्यास)

मैं यह कहता हूँ कि यदि इसमें परिवर्तन करने का फैसला नहीं किया तो कम से कम छोटे आदमियों का वेतन बढ़ाने की गुंजायश कम से कम ५ साल तक तो नहीं रहेगी। उन पर आप टैक्स तो लगा सकते हैं लेकिन वेतन बढ़ाने की मांग को नहीं मान सकते ? मैं मांग करता हूं कि राज्य के वित्त मंत्रीजी को फैसला करना पड़ेगा घोषणा करनी पड़ेगी कि समाजवादी समाज लाने के लिये १ : १० का अनुपात होगा कम से कम किसी को ४५ रुपये मिलते हैं तो दूसरी ओर किसी अफसर को ज्यादा से ज्यादा ४५० रु० मिलेंगे और यदि कम से कम किसी को ७० रुपये मिलते हैं तो अधिक से अधिक एक अफसर को ७०० रुपये करने पड़ेंगे ताकि समाजवादी समाज का निर्माण कर सकें। तो मैं चाहता हूं कि इस नीति में परिवर्तन किया जाय। इससे सारे राजस्थान के जो कर्मचारी हैं उनमें विषमता दूर होगी।

दूसरा परिवर्तन जमीन के बारे में करना पड़ेगा। आज पिछले १५ साल में जमीन के बारे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जमीन पर काम करने वाले एक किसान को प्रति दिन क्या मिलता है इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री पर जो खर्चा होता है उसका अंदाज लगाने की मैंने कोशिश की। हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री के ट्रेवलिंग पर, नौकर-चाकरों पर और अन्य बातों पर कितना खर्चा होता है, पार्टियों पर जो खर्चा होता है उसको जाने दीजिये और जो खर्चा होता है उसको देखिये और दूसरी ओर किसान को देखिये। देश में ५० परसेन्ट किसान ऐसे हैं जिनको प्रति दिन १३ नये पैसे प्राप्त होते हैं। राजस्थान के ५० प्रतिशत किसान इतने से अपनी जिन्दगी बसर करते हैं और दूसरी ओर राजस्थान के एक मंत्री का खर्चा १३,००० रुपये प्रतिदिन आता है........

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : वे अपने लिये खर्च करते है या जनता के लिये ?

श्री मुरलीधर व्यास : यदि इसकी जांच करनी है तो गाँवों में चले जाइये। मैं मंत्रीजी से कहता हूं कि गरीबों की बस्ती में जाइये, उनके साथ १० दिन रहिये। इधर उधर न घूम कर उनके साथ बैठिये, उनके दिल और दिमाग को इससे राहत मिलेगी। गांवों में मेघवालों और हरिजनों के साथ बैठिये, किसानों के साथ बैठिये, उनसे पूछिये क्या करते हो, खेती होती है ? वे लोग आपको बतायेंगे कि खेती के समय लोगों से कर्जा लेकर जमीन जोत लेते हैं। वर्षा होती है तो कुछ मिल जाता है; नहीं होती है तो नहीं मिलता है और फिर कर्जदार वैसे ही हो जाते हैं और फिर कर्ज लेते हैं और जिन्दगी बिताते हैं।

(२.० म.प.)

हैं। गांव से इधर उधर जा नहीं सकते, गांव में बैठे हैं। ऐसे पचास प्रतिशत आदमी आपको राजस्थान में मिलेंगे जिनकी आमदनी तेरह पैसे हैं और राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी का खर्च तेरह हजार रुपये का होता है। वह किस प्रकार होता है, उसमें क्या है, क्या नहीं है, इस खर्च में आप सारे खर्चे को ले लीजिये। इतना एक व्यक्ति पर जब खर्च करते हैं और दूसरी ओर जो राजस्थान का किसान है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्दर मतदाता कहा जाता है उसकी हालत यह है ! इस भेद को देखना पड़ेगा, इस फर्क को देखना पड़ेगा।

(श्री मुरलीधर व्यास)

आप कहेंगे कि तेरह हजार में कितने खर्च आते हैं ? मैं आपको निवेदन करूं कि उस खर्च में सारे खर्च आये हैं, जो फोटो छपती है, पत्रों में फिर जो प्रचार के वास्ते लगता है, जो वे टूर करते हैं उसके बिल बनते हैं, और जो उनके आसपास के आदमियों पर खर्च होता है, ये सब खर्च उसमें आ जाते हैं। तो राजस्थान के मुख्य मंत्री पर इतना खर्च होता है ! तो आप एक ओर लोगों से कहते हैं कि त्याग करिये। हमारे वित्त मंत्रीजी छात्रों से कहते हैं, उसकी दो लाइन आपको पढ़ कर सुनाता हूं। उन्होंने कहा है। "ऊपरी टीमटाम की तरफ झुकाव – ये बुराइयां हमारे नौजवानों में घुसी हुई हैं।" नौजवानों में ऊपरी टीम टाम की तरफ झुकाव की बुराई घुसी हुई है ? मैं कहता हूं, ठीक बात है, नौजवानों में, छात्रों में, बुराई है, उसे मैं अच्छा नहीं मानता। मैं कहता हूं कि आज टीम टाम और दिखावा कैसे कम हो जाय ? आज हमारे एक एक मंत्री के ऊपर कितना खर्च होता है ? आप पेट्रोल को बचाने के लिए ऐसी मोटर कार रख सकते हैं जिसमें पेट्रोल कम से कम कन्ज्यूम हो। आप किसी के पास बड़ी गाड़ी देखते हैं तो सोचते हैं कि इनके पास बड़ी गाड़ी है तो मंत्री के पास भी बड़ी गाड़ी होनी चाहिये क्योंकि मंत्री की गाड़ी अच्छी दिखनी चाहिए। लेकिन अगर यह सोचें कि पेट्रोल कम कन्ज्यूम हो तो ऐसी गाड़ी मिल सकती है जो चालीस मील चल सके एक गैलन में और २० मील का जो पेट्रोल बचता है आप उसको दूसरे खर्चे के नाम पर इस प्रकार कटौती कर सकते हैं। आप ज्यादा-काम करके, जो कर्मचारियों को रख कर अपनी शान-शौकत पर खर्च लगाते हैं, दौरे पर खर्च करते हैं (समय समाप्ति सूचक घंटी) वह बहुत ज्यादा होता है, उसको आप कम कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपने खर्च में कटौती कर सकते हैं। मैंने ये जो बातें कही हैं वे इस दृष्टिकोण से कही हैं कि हमको अपना जीवन सादगीमय बनाना चाहिए, एक ऐसा ढांचा बनाना चाहिए कि हमारे मंत्री महोदय बहुत थोड़े थोड़े खर्च में काम कर सकें। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की केरल में सरकार बनी। उसने घोषणा की कि हमारा कोई मंत्री पांच सौ रुपये से ज्यादा तनख्वाह नहीं लेगा ठीक बात है. हिन्दुस्तान में मंत्री एक हजार, दो हजार तक लेते हैं। लेकिन सोशलिस्टपार्टी का मंत्रिमण्डल बना, ढाई साल तक केरलमें प्रजा का काम किया। उन्होंने इसको करके बताया कि पांच सौ से ज्यादा किसी मन्त्री ने वेतन नहीं लिया, बंगला नहीं लिया, मोटर इस्तेमाल नहीं की, साइकिल को आने जाने के काम में लिया। क्या इस प्रकार के आदर्श को पेश नहीं कर सकते ? परन्तु इसके लिए आपको एक फैसला लेना पड़ेगा, दृढ़ता के साथ आपको फैसला लेना पड़ेगा कि हम खर्च में कमी करें। अगर इस खर्च को कम नहीं कर सकते तो ठीक बात है, कि आज की हालत में परिवर्तन नहीं कर सकते। इसको करने के लिए आपको मुल्क के लिए दो नीतियें अपनानी पड़ेंगी एक तो कम से कम और अधिक से अधिक वेतन दूसरा यह करना पड़ेगा कि जमीन की सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी। जिस किसान के पास जमीन नहीं है उसको जमीन देकर खेत का मालिक बना दें। तीसरी उस किसान को खुशहाल करने के लिए नीति अख्तयार करनी पड़ेगी कि जिसके पास कम आमदनी की पैदावार होती है, जिसके पास कम जमीन है उसे

(श्री मुरलीधर व्यास)

लगान की बिल्कुल छूट देनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त हमारा राजस्थान एक रेगिस्तान इलाका है, वहां उन लोगों को जिनको वर्षा की कमी के कारण आमदनी कम होती है, गृह उद्योग देने पड़ेंगे। ये बुनियादी चीजें कर देते हैं तो राजस्थान में सत्तर, अस्सी प्रतिशत आदमी खुश हो सकते हैं, इधर कर्मचारी खुश हो सकते हैं। राजस्थान में परिवर्तन लम्बे चौड़े, पन्द्रह वर्ष केअर्से में नहीं,दो साल के अन्दर परिवर्तन हो सकते हैं अगर सरकार चाहे तो। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पन्द्रह साल में भी वह परिवर्तन नहीं किया है।

दूसरे; मैं अब टैक्स के बारे में थोड़ी बात कहना चाहता हूं। टैक्स के बारे में बहुत कुछ कहा गया है उस सबको मैं दोहराना नहीं चाहता पर मैं इस टैक्स नीति के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं कि आपकी टैक्स की नीति किस प्रकार की बने। खुद वित्त मन्त्रीजी ने कहा कि टैक्स की नीति ऐसी होनी चाहिए कि जो टैक्स देने लायक हैं उन सेक्स लेना चाहिए उन्होंने यह बात कह दी, यह बात कागज में जरूर है। लेकिन आज देख लीजिए कि ये किस तरह से बात अधूरी रह गई है। जैसा वितमंत्री ने ओर्नामेंट्स के बारे में कहा। इनके बारे में जो टैक्स लगा है मैं मानता हूं कि जो ऑर्नामेंट्स खरीदने वाले हैं वे कहीं से भी पैसा देकर ऑर्नामेंट्स खरीद सकते हैं, उन पर लगना चाहिए। मैं मानता हूं कि ओर्नामेंटस समाजवाद में ऐसी चीज नहीं है जो आवश्यक हों, इसे समाजवाद की दृष्टि से रखने की कोशिश की जाय। किसी लेखक ने कहा है कि लेट्रीन में भी सोने की ईंट रख दी जायं तो उसका मूल्य नहीं है। यानी लेट्रीन में भी रख लें तो उस सोने का मूल्य नहीं है। मायने समाजवाद में संडास में भी सोने की ईंट बनाकर रखी जा सकती है। लेकिन सोना चाहे कहीं गिरा हुआ हो, चाहे अन्दर पड़ा हुआ हो वह समाज के काम में आना चाहिए। सोना कोई शोभा की चीज नहीं है, सोना धन है, दौलत है। तो सोने पर टैक्स लगाया है वह ऐसा लगना चाहिए कि अर्नामेंट्स खरीदने वालों पर लगे। लेकिन जो ओर्नामेंट्स पर टैक्स लगा है, इस पर मैंने विचार किया तो मालूम होता है कि यह मजदूरों पर लगता है। आज किसी मजदूर ने एक गहना बनाया और गहना बनाकर दूकानदार के पास गया। उस गहने में कितने सोने को लगाया है उस पर टैक्स नहीं लगा है, लेकिन जिस मजदूर ने बना कर दिया है। उस मजदूर पर टैक्स लगेगा, जो रुपये की कटौती होगी वह मजदूर की होगी जिसने वह बना कर दिया है उसी को देना होगा क्योंकि क्योंकि सोना तो जिस भाव पर आया है उसी पर बिकेगा। ओर्नामेंट्स पर टैक्स होने से मजदूर पर टैक्स लगता है। इससे क्या होगा कि जो दूकानदार है वह सोने की चीज बाहर से मंगा लेगा या जो सोने की चीज का खरीददार है वह दिल्ली जाकर खरीद लायेगा, जिसको पांच-दस हजार रुपयों का गहना लेना है वह बाहर जाकर खरीद लायेगा। इससे सरकार को लाभ नहीं मिलेगा और उल्टे नुकसान होगा; वह मेहनतकश मजदूर का होगा। इसलिए ऐसा रास्ता निकाला जाय कि सोने पर टैक्स लग सकता है तो लगायें लेकिन जो मजदूरी करके पैसा प्राप्त करता है उस पर टैक्स

(श्री मुरलीधर व्यास)

न लगे तो अच्छा है ।

अनाज के ऊपर, मैं इस चीज का पक्षपाती हूँ, कोई टैक्स नहीं होना चाहिए । आपने टैक्स चने और चने की दाल पर लगाया है, वह बहुत छोटी चीज मालूम पड़ती है । चने के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान में कोई आदमी गुजरता है उसको कहा जाता है कि मुट्ठी भर चना चाब कर पानी पी लो । उस पर आप टैक्स लगा देते है । तो कौनसा स्थान आपने खुला रखा है ? राजस्थान में जो मुट्ठी भर चना चाबकर पानी पीता है; उस पर भी आपने टैक्स लगाया है । यह कोई बड़ी चीज नहीं है । इसका नतीजा यह होगा कि ब्लैक होगा, दूसरी बातें होंगी जिससे इसमें लाभ नहीं होगा । मैं वित्त मन्त्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की कहने की बात नहीं हो कि लो, चना खाकर पानी क्यों पीते हो; चने पर तो वित्त मन्त्रीजी ने टैक्स लगा दिया है । मैं प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार का मौका नहीं आने देंगे ।

इसके अलावा आपने पैसेन्जर टैक्स लगाया है । पैसेन्जर टैक्स के सम्बन्ध में निवेदन करूं कि जहां तक शहर के लोगों का सवाल हैं वे किसी गाड़ी में बैठ कर इधर से उधर चले जाते हैं । गाड़ी में बैठ कर गांव के लोग भी जाते होंगे लेकिन राजस्थान के अन्दर इतनी रेल-गाड़ियां नहीं हैं कि वे गांव गांव में पहुंच गई हों । आज भी गांव का आदमी एक गांव से दूसरे गांव में जाता है तो उसके लिए एक छोटा-मोटा साधन हुआ है वह बसेज़ का हुआ है । इसके साथ ही वहां पर अच्छी रोड्स नहीं हैं । उन बसेज़ में लोगों के सिर टकराते हैं । हमारे यहां तो बीकानेर से अगर रावतसर जायेंगे और वहां से जरा से और आगे किसी गांव में जायेंगे तो इस प्रकार का हाल रहेगा, ऐसे धचके लगेंगे कि सिर पर से खून बहाये बिना यात्रा नहीं कर सकते; क्योंकि सिर टकरायेगा । तो यह थोड़ा सा साधन है, इस पर टैक्स देना पड़ेगा । उनको जो यह सहारा मिला था उस पर साढ़े बारह परसेन्ट टैक्स था; पांच परसेन्ट की छूट थी, लेकिन अब आपने २५ परसेन्ट लगा दिया । तो इसकी नीति यह होनी चाहिए, बस टैक्स के लिए खास तौर से कहना चाहता हूँ कि जब हमारी सरकार ने इस योजना को इस नीति को अख्तियार किया कि राजस्थान में बसेज़ का नेशनलाइज़ेशन करना चाहते हैं । वहां पर आज राजस्थान की सरकार राष्ट्रीयकरण की बात के साथ पैसेन्जर टैक्स बढ़ाती जायगी तो मैं समझता हूं कि राष्ट्रीयकरण के प्रति आम लोगों में जो भावना बनाना चाहते हैं वह नहीं बनेगी यह भावना बनेगी कि आप इसलिए राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं कि आप टैक्स पर टैक्स लगायें । आप अपना खर्चा बढ़ाते जायं और टैक्स बढ़ाते जायं; तो नतीजा यह होगा कि आम लोगों का विश्वास राष्ट्रीयकरण से हट जायगा । हम चाहते हैं कि सारी माइन्स का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, बड़ी माइन्स का, क्योंकि आज राजस्थान में पैसे की कमी है ।

मैं आपको एक जिप्सम का उदाहरण देता हूं । जहां उसमें ८ या १० लाख रुपयों का मुनाफा होता है वहां पर आपके २ परसेन्ट बढ़ाने से १० लाख की आमदनी इससे होगी । इसके अलावा दूसरी जितनी भी माइन्स हैं उनका विकास किया जावे और इन माइन्स का राष्ट्रीयकरण किया जावे ।

(श्री मुरलीधर व्यास)

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं कहता हूँ कि वन राष्ट्र की संपदा है। आपने इसमें क्या किया है कि आपने लोगों को कॉन्ट्रेक्ट दे दिया। कॉन्ट्रेक्टर वन-संपदा की रक्षा नहीं कर सकते। उनको अपने फायदे की लगी रहती है। वन राष्ट्रीय संपदा है, मगर आपने सारा वन ठेकेदारों को सौंप रखा है। आप माइन्स के विकास के लिए भी ठेके देते हैं, मगर ठेकेदार मनमाने ढंग से गड्ढे खोदते हैं और थोड़े खर्चे में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और जो गड्ढे होते हैं उनको पूरी तरह से बूरते भी नहीं....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये जो मामले हैं इन पर गंभीरता से विचार करना चाहिये।

इसलिये मैं भिन्न भिन्न महकमों के मंत्री महोदयों से प्रार्थना जरूर करना चाहता हूँ कि आप इन ५-७ बातों को, चाहे वह वन-संपदा की बात हो, चाहे कृषि की बात हो, चाहे वित्त मंत्री की हो, इस पर ध्यान दें और मौजूदा जो तरीका है वह तो समाजवाद को लाने का नहीं; बल्कि समाजवाद को कम करने का है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे मैं आशा करता हूँ कि वे इस बात को अवश्य ध्यान में रखेंगे कि गरीब से गरीब को किस तरह से दवा दी जा सके और उसकी बीमारी दूर हो।

श्री सभापति : आप अपना भाषण अब समाप्त करें।

श्री मुरलीधर व्यास : शिक्षा मंत्री से मैं यह निवेदन करूंगा कि गरीब से गरीब व्यक्ति को शिक्षा को प्राप्त करने में ज्यादा से ज्यादा अच्छे साधन किस प्रकार दिये जा सकते हैं, इसका ध्यान रखें। उद्योग और लेबर मंत्रीजी से यह चाहूँगा कि आप मजदूरों के मंत्री नहीं; बल्कि मालिकों के मंत्री हैं। आपको लेबर मंत्री कहते हैं, मगर दरअसल में आप मालिक मंत्री हैं इसलिये आपका नाम बदल कर लेबर मंत्री के स्थान पर मालिक मंत्री कर दिया जाना चाहिये। आज हर आदमी मालिकों का मंत्री बन जाता है, मजदूरों का नहीं। इसलिये मैं आपसे यह कहूँगा कि आप जैसा आपका नाम है वैसा ही आप काम करें और मजदूरों के हितों में काम करें। जिस विभाग को आपने अपने जिम्मे लिया है उसमें समाजवाद लाने के लिये आपको सोचना होगा। आपको अगर एकान्त में बैठ कर सोचना पड़े तो भी आप इस पर सोचें या आपको १० दिन तक एकान्त में बैठ कर सोचना पड़े तो भी सोचना चाहिये। आप आपसी बातों में समय जरूर खर्च करें, लेकिन अगर आप थोड़ा समय खर्च करके अच्छे आदमियों से राय लेकर अच्छा समाजवाद लावें, अच्छा समाजवाद आ जावे तो कोई बुरी बात नहीं है।

इन सारी बातों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि इस पर आप ध्यान दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री दुर्गालाल बाददार (हवा महल, जयपुर) : सभापति महोदय, आज सदन के सामने हमारा बजट है, इस पर हम विचार कर रहे हैं। बजट को पढ़ने से हमें यह मालूम हुआ कि सरकार कुछ अपनी मांगें, अपनी जरूरतें हमारे सामने रखती है और साथ ही

Page No 52

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

साथ उनको किस प्रकार पूरा करना चाहती है, किस प्रकार पब्लिक पर टैक्सेज़ लगा कर आगे बढ़ना चाहती है, यह भी बजट में हमारे सामने रखा गया है। लेकिन इन दोनों बातों पर विचार करने से, अध्ययन करने से हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि हम लोगों पर यह कर थोपा जाता है। हो सकता है कि हमारे उधर बैठनेवाले सदस्य यह समझें कि विरोधी लोग हमारा विरोध करते रहते हैं लेकिन मैं यह कहूँगा कि आपने कल से देखा होगा कि जो टैक्सेज़ हमारे पर थोपे जाते हैं उनका विरोध हम ही नहीं करते लेकिन जो वास्तव में जनता के प्रतिनिधि हैं और अपने आपको जनता के प्रतिनिधि समझते हैं और जिनके हृदय में जनता के दुःखों को पहिचानने की भावना है वे लोग कम से कम आगे आकर कहने को तैयार हैं कि बहुत से टैक्सेज़ ऐसे हैं जो हमारे पर थोपे जा रहे हैं; पब्लिक का अहित करने वाले हैं। मैं मानता हूँ और यह बात सही है कि सरकार को चलाने के लिए उसको अर्थ की जरूरत है, धन की जरूरत है और पैसा लेगी वह भी जनता के पास से और उनकी जेब से, लेकिन इस पैसे को ठीक तरह से इस्तेमाल किया जाता है या नहीं, यह एक देखने की बात है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इस पर विचार करने के बाद हम कह सकते हैं कि........

श्री सभापति : माननीय मन्त्री सोयेंगे नहीं।

श्री बरकतुल्ला खां (स्वास्थ्य मंत्री) : मैं सो नहीं रहा हूँ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : हम पर टैक्स लगाया जा रहा है उसका सरकार दुरुपयोग नहीं करेगी। लेकिन मैं आप लोगों के सामने, सभापति महोदय, आपके द्वारा शासक वर्ग के सामने यह बात खास तौर से रखना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूँ कि अब तक जो अर्थ व्यवस्था रही है वह किस प्रकार की रही है। पीछे जो बजट बने और आगे भी बजट बनेंगे उन्हें देखेंगे। मैं हमारे वित्त मंत्री की जो स्पीच थी उसमें से थोड़ा सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं। पेरा नं० १० हमें यह बताता है : "The second factor was the revision of the Pay Scales of Government employees, details of which must already be known to the Honourable Members. The financial implications of this step are both immediate and far-reaching in character. In assessing the resources for the Third Plan, it was estimated that a sum of Rs. 4 crores would be required to improve the emoluments of Government servants. But this estimate has turned out to be an under-estimate in as much as the adhoc increase of Rs. 5 in the dearness allowance granted to low-paid employees from 1st July, 1960 will alone amount to an additional expenditure of Rs. 5 crores." ये जो ऑब्जर्वेशन्स हैं हमारे माननीय वित्त मन्त्री के भाषण में। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये आंकड़े हम अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ावेंगे उसमें इतना खर्चा होगा। हमने अन्दाजा लगाया कि इतने में हमारा खर्चा चल जावेगा। मगर जब आज दूसरे मंत्री यहां आते

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

हैं तो हमारे वित्त मंत्री ऐसी बात करते हैं जैसे उनके सामने कोई आंकड़े नहीं थे । सारा सदन और सदन के सभी सदस्य इस बात को जानते हैं कि हमारे वित्त मंत्री की सेवा में भी सेक्रेटेरियेट था । हमारे वित्त मंत्री थे वे भी रेस्पोन्सिबल थे और जैसी बात कही गई कि ज्ञान नहीं था कि कितने नौकर हैं और कितनों को देना होगा यह तो स्पष्ट है कि दो और दो तो चार ही होंगे, कभी भी पांच नहीं होंगे । अगर हमें इसका भी अनुमान नहीं तो हमारे सामने यह प्रश्न रखा जाता है और यह कहा जाता है कि हमारा एस्टीमेट अन्डर एस्टीमेट हो गया तो यह आश्चर्यजनक बात है । और यह मान कर चलना चाहिये कि आंकड़े जो हमको दिये जाते हैं वे गलत दिये जाते हैं, या यह मान कर चलना चाहिये कि रिपोर्ट गलत देते हैं; या यों कहिये कि कोई नीचे से ऊपर तक आदमी टोटलाइज करने-वाला नहीं है ।

मेरा यह निवेदन है कि टैक्सेज़ जनता के हित के लिये लगाते हैं । लेकिन पब्लिक यह सोचेगी कि जिन लोगों को हम रुपया देते हैं वह ठीक तरह से उपयोग में लाया जावेगा या नहीं; 'Maximum good out of minimum labour and sacrifice.' अगर ऐसी चीज़ नहीं होती तो इसका विरोध नहीं होता । मैं थोड़ा निवेदन करूंगा कि जब आलोचना हो रही हो तो यह मान कर चलते हैं कि यह तो विरोधी पक्ष के लोगों की भावना है कि विरोध किया जावे । मैं यह कहूंगा कि विरोधी पक्ष की यह भावना नहीं रही है कि व्यक्तिगत आलोचना करें । हम व्यक्तिगत आलोचना को लेकर नहीं चलते; किसी व्यक्ति, सम्प्रदाय या संस्था विशेष की आलोचना को लेकर नहीं चलते । कल चर्चा की जा रही थी कि कांग्रेस ने बड़ी तपस्या और त्याग किये, रामराज्य की स्थापना की जाने वाली थी पर इसमें बाधा डाली गई, इसमें बाधा डालने वाले राजा लोग और स्वतन्त्र पार्टी है । मैं निवेदन करूंगा कि जिस समय देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई हमारे मुल्क के हर आदमी ने कन्धे से कन्धा मिला कर अपने मुल्क को आजाद करने की कोशिश की । मैं यह मान कर चलता हूं कि वह एक इस प्रकार को फिजां बन रही थी देश में कि देश में बहिनों ने भाइयों को, माताओं ने पुत्रों को और महिलाओं ने अपने सिंदूर को मातृ-भूमि की बलि वेदी पर चढ़ा दिया । फिर क्या आप इस सब का श्रेय एक व्यक्ति विशेष को, एक पार्टी विशेष को देना चाहते हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : इसका श्रेय आप ले सकते हैं, इधर वाले नहीं ले सकते ।

श्री दुर्गालाल बाढदार : आप ले रहे हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : नहीं, यह तो आपकी बपौती है ।

श्री दुर्गालाल बाढदार : आप ले सकते हैं । इसे यदि कोई बपौती मान कर चलता है तो सही नहीं है । ऐसे आदमी थे जिन्होंने हंसते हंसते अपने आपको फांसी के तख्ते पर झुलाया । वे महान् व्यक्ति किसी संस्था विशेष के, किसी सम्प्रदाय विशेष के व्यक्ति नहीं थे राष्ट्र के व्यक्ति थे । उनको कोई बपौती मान

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

कर चलता है तो वह उचित नहीं । उन्होंने और आम जनता ने अपनी कुर्बानियों से राम-राज्य का बीजारोपण हमारे देश में किया, पर बड़े दुःख की बात है कि राम-राज्य का बीजारोपण होने के बाद ही रावण के कुछ वंशज कुर्सियों पर बैठ गये और इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे देश में राम-राज्य स्थापित नहीं हो सका। आज जो हमारा विरोध किया जा रहा है; मैं अपनी मान्यता रखता था कि राजस्थान में बहुत मुख्य मंत्री हुए, मौजूदा मुख्य मन्त्री भी अपनी अहमियत रखते हैं, मैं विश्वास रखता था कि मुख्य मन्त्री एक shrewed and intelligent statesman होना चाहिये जो अपने विरोधियों का भी सम्मान करें, आदर करें; पर कल-परसों-राजस्थान पत्रिका, पढ़ने के बाद, जहां मुख्य मंत्री यह स्टेटमेंट दे देने को तैयार हो जाते हैं कि कुछ राज्य परिवार ऐसे हैं कि जिनका मुकाबला करने के लिये उन्हें अपनी चीफ मिनिस्टरी भी छोड़नी पड़े तो इसके लिये भी तैयार हैं; बड़ा आश्चर्य है। इस प्रकार के व्यक्तिगत विद्वेष की किसी स्टेट्समैन से उम्मीद नहीं की जा सकती। एक प्रबल पार्टी अपना विरोधी दल बना देती है और सुझाव रखती है तो उससे इतनी व्यक्तिगत दुश्मनी रखें कि उसके मुकाबले के लिये वे चीफ मिनिस्टर छोड़ने को तैयार होंगे। इस प्रकार की आशा हमें मुख्य मन्त्री पद से नहीं होनी चाहिये। खैर; जाने दीजिये इन बातों को, ये दूसरी बातें हैं।

आप एक प्रश्न लेकर चलते हैं कि हम नेशनलाइज़ेशन कर रहे हैं बसेज़ का, सवारियों का। उसके पीछे आप दूसरा सपना रखते हैं, प्राइवेट बसेज़ चलाने वाले काफी मुनाफा कमाते हैं, एक पक्ष ऐसा होता जाता है, लाखों रुपया इकट्ठा करता जाता है और दूसरे पक्ष को कोई फायदा नहीं होता। पर तुलना कर लीजिये, आप अपने आंकड़ों को लेकर चलिये, दूसरों पर इत्मिनान मत कीजिये, अपने आंकड़ों को बताने को तैयार हों कि नेशनलाइज़ेशन की स्कीम पर कितना रुपया खर्च किया। प्राइवेट बस प्लायर्स जो किराया लेते हैं उससे कितना ज्यादा किराया आप लेना चाहते हैं, आप उन आंकड़ों को नाप लीजिये। प्राइवेट प्लायर्स से आप ज्यादा किराया लेते हैं। प्राइवेट प्लायर्स ने अपनी बसेज़ के रिपेयर में कितना खर्चा किया और आपकी सरकार ने अपनी बसेज़ को सुधारने के लिये कितना खर्चा किया ? तो यह है आपकी नेशनलाइज़ेशन की स्कीम। इस स्कीम के आधार पर आप कौनसे जमाने का राम-राज्य स्थापित करना चाहते हैं ? जनता प्रत्यक्ष फायदा देखना चाहती है। केवल कल्पना में स्वर्ग के दृश्य दिखा कर आप लोगों को लुभाना चाहें तो यह चीज इस युग में नहीं चल सकती, यह चीज बार बार नहीं आ सकती। आपको क्रियात्मक कार्य करने होंगे जिससे कि जनता सुख पा सके। जो मोटरों में ट्रेवल करते हैं उन्हें इस बात का अनुभव है, आपकी बसेज़ चलती हैं; आपने दो मील, ५ मील, ७ मील पर स्टेशन कायम कर रखे हैं पर सड़क के आसपास के लोग यात्रा करना चाहते हैं उनके लिये बस नहीं रोकी जाती, आप आगे बढ़ जाते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि वे लोग सुबह से शाम तक खड़े मुंह ताकते रहते हैं। दूसरे, आप यह

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

व्यवस्था करना चाहते हैं कि पैसेंजर्स के लिये शैड बनायेंगे। आप वायदे करते हैं पर ये सुविधाएं आप उपलब्ध नहीं करते, यह हम अपनी आंखों से देख रहे हैं । इतना अर्सा हो गया आपको यह स्कीम चलाये हुए, पर अभी तक आप कुछ भी नहीं कर पाये हैं । तो इन बातों के बावजूद भी यह माना जाय कि जो व्यवस्था आप इस राज्य में करना चाहते हैं वह सुचारू रूप से चल रही है और जो मांग टैक्स के रूप में कर रहे हैं कि हम व्यवस्था सुचारू रूप से चला रहे हैं, यह कहां तक न्यायसंगत है ? यह प्रश्न ऐसा है जो हम आपके सामने आपके विचारने के लिये ही छोड़ देते हैं।

इस तरह से बहुत से क्वेश्चन्स आपके सामने आते हैं। आप कहते हैं कि हमने न्याय सस्ता कर दिया, घर घर तक लोगों को न्याय प्राप्त करने के साधन पहुंचा दिये गये हैं; इस न्याय को हम इतना सस्ता बना देंगे कि गरीब से गरीब आदमी भी अदालत में जाकर न्याय प्राप्त कर सकेगा। पर आज की स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत है। मेरा निजी अनुभव यह है कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने कोर्ट फीस का कानून बनाया है, उसके अनुसार जो न्याय शुल्क पहले देते थे उससे कहीं ज्यादा न्याय शुल्क देना पड़ता है । मैं छोटी सी मिसाल से निवेदन करना चाहता हूं, कि जिस कोर्ट फीस का भार जनता पर लादा आप उसके कारनामों को भी देखें। कोई इन्जंक्शन, हुक्म इम्तिनाई का दावा, नाले-परनाले के नुकसान का दावा करे तो उसको साढ़े बाईस रुपया फीस के देने पड़ेंगे। पहले यह था कि यदि किसी ने किसी के २०) रुपये का नाला तोड़ दिया है तो बीस रुपये के आधार पर जो सीमा होती थी वह दे दिया करता था। पर आपने न्याय को सस्ता करने की गर्ज से जो कम से कम मूल्यांकन रखा इन्जंक्शन के लिये वह साढ़े सात पर्सेंट की जगह २२.५० कर दिया है। २०) रुपये का यदि किसी ने किसी का नुकसान किया है तो उस पर डेढ रुपया रस्म देनी पड़ती थी। अब यदि कोई चाहे २) रुपये के मूल्यांकन पर भी दावा करना चाहे, अदालत से इन्साफ कराना चाहे तो उसको साढ़े बाईस रुपये देने पड़ेंगे । डेढ़ रुपये से साढ़े बाईस रुपया रस्म कर दी, इससे ज्यादा सस्ताई आप क्या कर सकते थे, न्याय की सस्ताई की परिभाषा आप इससे ज्यादा हमें क्या दे सकते हैं ? यह रही है आपकी न्याय की व्यवस्था ।

जयपुर का नागरिक होने के नाते मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यहां एक बैंच हाईकोर्ट की प्रारम्भ से थी और उस हाई कोर्ट की बैंच को हटाने का प्रश्न पैदा हुआ तो एजिटेशन हुआ। जनता ने अपील की, याचनाएं कीं, मांग की कि जिस स्कीम को करना चाहते हैं, हाई कोर्ट को दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं उसमें जनता का हित नहीं है । इस पर सरकार द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। उस आन्दोलन का दमन कर दिया, इसके लिये आप जो भी उचित समझें वे शब्द प्रयोग में ला सकते हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि बहुत से आदमी जिनका सम्बन्ध न्यायालयों से रहा है वे जानते हैं कि कुर्की की इजराय हुई, फौजदारी में हाजिर होने की जरूरत रहती है, हाजिर नहीं होता है तो उसका मुचलका कैंसिल कर दिया जाता है।

Page No 56

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

एक फरीक जो राजस्थान के किसी एक कोने में रहता है, फौजदारी मुकदमा उस पर दायर किया हुआ है उसे हर तारीख पेशी पर जो उसके स्थान से पास का स्थान हो सकता था उस स्थान को छोड़ कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। उसके आने जाने का खर्चा और दूसरी व्यवस्था, उन पर आप स्वयम् ही विचार कर लीजिये। राजस्थान प्रान्त की कितनी बड़ी जनता के साथ न्याय व्यवस्था में सहायता की और कितनी की; यह जनता अच्छी तरह से जानती है। मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि जनता जानती ही नहीं है वह उसका उत्तर देना भी जानती है। जो जो स्थान आपकी इन हरकतों से प्रभावित हुए हैं उन्होंने आपको प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर भी करा दिया है कि जनता किसी बात पर तुल जाती है, कोई बात करना चाहती है, चाहे वे हुकूमत करने वाले हों, चाहे किसी पक्ष के हों उनको दिखा सकती है-उनको बता सकती है कि जनता की आवाज बुलन्द होती है। उसका प्रभाव यह हुआ है कि जो स्थान प्रभावित हुए हैं उनमें से कितने स्थान हुकूमत करने वालों ने-कांग्रेस पार्टी ने प्राप्त किये हैं ? यह आपके कारनामों का जवाब जनता ने दिया है। फिर जनता चेतावनी देना चाहती है, आगाह करना चाहती है कि ये मौके बार बार आ सकते हैं और पांच साल में कई बार भी आ सकते हैं। यह आप लोगों के सोचने की बात है।

जहां तक....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : माननीय सभापति महोदय, (खांसी चलने के कारण रुकने पर)

श्री सभापति : आपका भाषण समाप्त हो जाय।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : सभापति महोदय,....

श्री सभापति : माननीय श्री ज्वाला-प्रसाद।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभा-पतिजी,....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अ‍ब तो निगाह मैंने पकड़ ली है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : I may just wind up my speech, Sir.

श्री सभापति : Now the other member has started.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदय, बजट के सिलसिले में बहस चल रही है। उसके बारे में कुछ सुझाव मैं सरकार को देना चाहता हूँ। मैं यह समझता हूँ कि बड़ी ही सिन्सीयरिटी के साथ वित्त मंत्री महोदय जब अपना भाषण पढ़ रहे थे तो उनको यह ओहदानशीनी हुए बहुत कम वक्त हुआ था उसका उनको बड़ा दर्द था और उसकी वजह से उन्होंने सदन को यह भी खबर की कि वे जो करना चाहते थे वे नहीं कर सके थे। मेरा सिर्फ सुझाव है संक्षेप में कि वोट ऑन अकाउन्टस् पास करके थोड़े दिनों के लिए बजट ले लेते तो उनकी यह तकलीफ मिट जाती। बजट सेशन को तीन महीने बाद बुला लेते और खर्चे के लिए वोट ऑन अकाउन्ट पास करा लेते। वोट ऑन अका-उन्ट के नाम में करा लेते तो सरकार के

Page No 57

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

लिए सरल तरीका था, इतनी दिक्कत जो कई दफा रिपीट हुई है उस दिक्कत से सरकार बच सकती थी। उसके साथ मैं यह भी सुझाव सरकार को देना चाहता हूँ कि जनतन्त्र में बजट पास होना बहुत बड़ा कदम-कान्ड है और इस कदम-कान्ड को बहुत बड़ा महत्व दें, यह सरकार से अपील है। पीछे बैठने वाले, बैंक बैन्चर्स जो मेम्बर्स हैं सरकार को अपने २ इलाके की, अपने २ क्षेत्र की बातें कहें तो सरकार को पुनीत कर्त्तव्य समझना चाहिये, सरकार को चाहिये कि उनकी छोटी २ बातों का जवाब दे, जो उनकी जानकारी है अपने इलाके की, अपने क्षेत्र की उनके बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है; वे जान सकें। मैं यह भी कहूँगा कि बजट के मौके पर हर तरह की बात करने की छूट देते हैं; वह इसलिए देते हैं कि छोटी-बड़ी जितनी बातें हैं उनकी ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो छोटी २ बातें अपने क्षेत्र के बारे में उठाते हैं उनका कुछ न कुछ उत्तर सरकार की ओर से अवश्य ही दिया जाता रहेगा।

इसके बाद अब मैं बजट के सिलसिले में अपने विचार रखना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस बजट में और जो हमारे सामने भाषण हुए हैं उनसे मुझे ऐसा लगता है कि एक मुईम से दूसरी मुईम की तरफ राजस्थान को बढ़ा ले जा रहे हैं और अभी मेरे पूर्व वक्ता, स्वतन्त्र पार्टी के सम्मानित सदस्य बोल रहे थे तो वे यह कह रहे थे कि जनता के लोगों ने कुर्बानियां कीं और उस लड़ाई को कांग्रेस को अपनी कहने का हक नहीं है। मैं बड़े अदब से उन्हें कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस कई तंग रास्तों से निकल चुकी है। अंग्रेजों ने भी कई दफा यह सांस ली कि हमने कांग्रेस को खत्म कर दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस खत्म नहीं हो सकी। उसकी सच्चाई और उसके झंडे के नीचे कुर्बानियां हुई हैं। उसका कांग्रेस पार्टी को ही श्रेय है। इतिहास में उसको इसका श्रेय है और आनेवाली संतति यह कहेगी कि दो हजार वर्ष की गुलामी से यदि किसी ने निकाला तो कांग्रेस पार्टी ने ही निकाला। इसी के झंडे के नीचे आजादी की लड़ाई लड़ी गई और इसी झन्डे के नीचे गरीबी की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। उसके अन्दर बैठे हम अपने आपको गौरवान्वित फील करते हैं, महसूस करते हैं कि जो यह जिम्मेदारी आकर पड़ी है उसको हर मुमकिन तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल कह देने से ही काम नहीं चलता है, गिरहबान में मुंह डाल कर देखें, अंग्रेजों के वक्त वह तबका कौनसा था कि जिसको सहारा अंग्रेजों का था या राष्ट्रीयता का था। आपके दिल से सच्ची आवाज निकलेगी कि कांग्रेस और उसके झंडे के नीचे जितनी आजादी की लड़ाइयां लड़ी गईं उनका श्रेय यदि किसी को है तो वह कांग्रेस को है।

कुछ बातें कही हैं माननीय मुख्य मन्त्री के बारे में। मैं संक्षेप में यह कहना चाहता हूँ कि उन्होंने किसी के लिए कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं कहा है। उनकी किसी तकरीर के लिए कहा गया तो उन्होंने किसी व्यक्ति के लिए नहीं कहा है, न ही राजाओं के बारे में उन्होंने

Page No 58

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कुछ कहा है। मैंने भी अखबार को पढ़ा है और मैं जो समझ सका हूँ उससे यह है कि यदि हमको प्रतिक्रियावादी ताकतों के खिलाफ कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम देंगे। हमें विश्वास है, सच्चाई के साथ एक आदर्श की ओर राजस्थान को ले जाना चाहते हैं और देश को ले जाना चाहते हैं; वे यह बात कह सकते हैं और इसको व्यक्तिगत बात भी नहीं समझना चाहिये। मैं यह भी कर देना चाहता हूँ कि बजट की स्पीच को महज सामने इस तरीके से रखा गया है, इस तरह से रखा गया है जैसे कोई मेडीटेशन कर रहा हो, कोई आत्म-चिन्तन कर रहा हो। वित्त मन्त्री महोदय ने इस सदन में अपनी उस तकरीर को उस तरीके से रखा। इस सिलसिले में मैं कहूं, उन्होंने एक बात को साफ कहा है दूसरी बात मैं नहीं समझता। हमारी योजनायें इसी प्रकार चलती रहेंगी, हम इन योजनाओं के जरिये बराबर इस बात की कोशिश करते रहेंगे, राजस्थान के विकास की ओर जो कदम बढ़ रहे हैं उनके अन्दर राजस्थान पीछे न रह जाय। राजस्थान जो पिछले देशी रजवाड़ों का राज्य था, उससे निकाल कर जिस तरह से राजस्थान को इस कांग्रेसी सरकार ने आगे बढ़ाने क प्रयत्न किया वह प्रयत्न भी आपके सामने है। इसके साथ-साथ हम इस चीज को भी देखते हुए चल रहे हैं वह है अन्य प्रान्तों का विकास। उसके अनुसार हम भी अपनी आर्थिक हालत को मद्देनजर रखते हुए अपने कदम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। यह सब कांग्रेसी सरकार का अथक प्रयत्न है। इसके लिये हमें जरूरत हो तो लोन लेना पड़ेगा और लेते भी हैं। इस प्रकार के प्रयत्न में हमें कभी झुक कर भी प्रयत्न करना पड़ता है; जैसे वजनदार चीज को उठाने के लिये जरा झुक कर उसको ताकत लगानी पड़ती है उसी प्रकार की स्थिति हमारे यहां है। एक बात साफ है और इस बजट को देखने से वह बात और स्पष्ट हो गई कि जो तखमीना सरकारी अफसर लगाते हैं, जो तखमीना वे बना कर पेश करते हैं वह तखमीना आखिरकार सही नहीं निकलता है। जिन अधिकारी वर्ग को खास इसीलिये रखा जाता है, जिनको सरकार की तरफ से सब प्रकार की फेसीलिटीज़ हैं, अच्छा वेतन देते हैं इतना होने के बावजूद भी फाइनेन्स डिपार्टमेंट सही तखमीना बनाने में फैल रहा है। वह इसमें असमर्थ रहा है कि जो तखमीना वे देते हैं वह तखमीना गलत निकलता है। हर जगह यह सही निकली है इस बजट में उस बात को सही रूप में लाने का प्रयत्न किया गया है जिससे हम यह कह सकते हैं कि हमारा फाइनेन्स डिपार्टमेंट आज इस स्थिति के अन्दर है कि उनके द्वारा जो तखमीना लगाया जाता है हम महसूस करते हैं कि वे सही तखमीना नहीं लगा पाते। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम सब मिल कर इस बात को सोचें, इस बजट के बनाने के अन्दर हमारे सामने यह साफ तौर से बात आये कि जो सरकार द्वारा तखमीना बनाने का तरीका है वह वैज्ञानिक ढंग का हो जिससे सही तखमीना सदन के सामने आ सके। हम यह देखते हैं कि अधिकारी वर्ग को यदि यह कह दिया जाय कि सरप्लस बजट बना कर लाना है तो वे आंकड़ों को इस तरह से इधर उधर करके ला देंगे जिससे बजट सरप्लस मालूम हो। अगर आप उनसे यह कह दें कि

Page No 59

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

बजट डेफिसिट होना चाहिये तो वे आंकड़ों को इस तरह से फेरफार करके ला देंगे जिससे बजट डेफीसिट मालूम होगा। लेकिन हमें देखना यह है कि जब व्यवहारिक ढंग से साल भर काम करने के बाद जो अन्दाज लगाया था वह अन्दाज क्या निकला। इस प्रकार का स्टेटमेंट हमारे यहां टेबल ऑफ दी हाउस पर जरूर रखा जाना चाहिये ताकि हम यह जान सकें कि हमारे तखमीने में कितना अंतर रहता है, कितनी कमी-बेसी हुई है; इसका कारण पूरी तरह से सोच सकें।

कहा यह जाता है कि सर्विसेज़ को राहत देने में हमारा ४ करोड़ का अन्दाज था वह बढ़ कर ७॥ करोड़ हो गया। यह जो चीज आई है इसके लिए हमारी कांग्रेसी सरकार को आगाह होना है यह अचानक किस प्रकार से वृद्धि हो गई, इस तरः से हमारे अन्दाज में फर्क कैसे हो गया? इसके अलावा हमें यह भी देखना होगा कि जो लाभ हम देना चाहते थे वे किस कारण से नहीं दे सके, इसको भी ध्यान में रखना होगा। जरूरत इस बात की है कि बजट जो हमारे सामने आये वह सही अंदाजे के साथ आये। हम टैक्सेज़ से नहीं घबराते, जनता भी नहीं घबराती आखिर मुईम को पूरा करने के लिए कुछ करना ही पड़ता है ऐसे कार्यों के लिए कांग्रेसी सरकार न घबड़ाई है और न आगे भी घबरानेवाली है। हम अपने पेट पर पट्टी नहीं बांधे, पट्टी बांधना है तो tighten the belt of the administration, tighten those people जो इस तरह से हमको राजस्थान के तखमीने के बारे में जिनको सरकार पूरा पैसा देती है, उनके द्वारा तैयार किये हुए आंकड़े हम देखते हैं, सही नहीं निकलते हैं। इसलिए तखमीना सही करने के लिये उपाय सोचने पड़ेंगे। सही स्थिति और तखमीना सदन के सामने लाया जाय। सदन के सदस्यों के पास इतने साधन नहीं कि वे सब चीजों को ला सकें और इस प्रकार तखमीनों के बारे में सोच सकें। हम तो जो कुछ लिख देते हैं उस पर विश्वास करके चलते हैं। तो हम यह चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की यह जिम्मेदारी होनी चाहिये कि जो बजट बनाता है उसके अन्दर हमको यह भी सोचना चाहिये कि जो भी स्थिति है उस सब स्थिति का हमें सामना करना है।

अब मैं सभापति महोदय, विरोधियों की बात को लेकर चलता हूं। मेरा ख्याल है कि हमने स्वतन्त्र पार्टी के नेता की बात सुनी और भी लोगों की बात सुनी जो उनसे मिलती जुलती थी। एक नई बात उन्होंने रखी उसको मद्देनजर रखते हुएही हम आगे बढ़ सकते हैं। उनका कहना था कि धरती, धर्म और धन्धा इन सब में आजादी होनी चाहिये। इसके साथ साथ सोचने लायक जो बात उन्होंने कही वह यह कि हमें फेमिली प्लानिंग की ओर ध्यान देना चाहिये। जहां तक हम इस महत्व के काम को नहीं करते इस देश में धर्म की रक्षा, धन्धे की रक्षा नहीं हो सकती। उन्होंने इसको कहते हुए यहां तक कह दिया कि अगर इसको कानूनी ढंग से भी लागू करना पड़े तो भी हमें नहीं हिचकना चाहिये। कानून बनाने की इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता। हमने गरीबी को मिटाने की लड़ाई शुरू करदी है, अब हम यह नहीं चाहते कि 'अन्धा पीसे कुता खाये' वाली कहावत यहां पर चरितार्थ हो। इसको हमें रोकना होगा। जहां तक इस समस्या का सवाल है हमें इसे राष्ट्रीय महत्त्व देना है, इसमें किसी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

पार्टी का सवाल नहीं । जहां तक इस परिवार नियोजन का सवाल है इसको नेशनल इम्पोर्टेंस सवाल समझ कर कोई पार्टी इसके खिलाफ नहीं, ऐसी स्थिति समझते हुए सभी का कर्तव्य हो जाता है, जब हम इस चीज़ को एक राय से मानते हैं। पोपुलेशन की प्रोब्लेम, आबादी की प्रोब्लम किस तरह से जो यह रफ्तार बढ़ रही है इससे हमारे जो अन्दाज हैं उन अन्दाजों के अन्दर फर्क पड़ता है, इससे दिक्कतें आने वाली हैं; इसके लिए कांग्रेस सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है, इसके लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में बहुत व्यवस्था भी की है।

इसके बाद सभापति महोदय, दूसरा, जनसंघ दल के नेता महोदय ने बहुत धुंआ उठाया। वे अपने ढंग से सोचते हैं। उनके सोचने के तरीके से उनको समाजवाद का पता नहीं चल सकता। जहां तक उनके समाजवाद की व्याख्या है वह समाजवाद हम यहां लाना नहीं चाहते, वह तो उनकी संस्कृति तक सीमित है । हम उनके समाजवाद का विरोध करते हैं; वैसी हालत में उनके दिमाग में हमारे समाजवाद की परिभाषा समझ में आ जाय यह कोई विवेक नहीं। दूसरे समाजवादी भाई समाजवाद की बातें करते हैं। हम ऐसे उनको नजदीक पाते हैं। पर तुमको तो दूर पाते हैं और इतना दूर पाते हैं कि जिसकी वजह से हम और आप तो कभी मिल नहीं सकेंगे। अगर कोई चीज है, आज देश में जो संस्कृति और दूसरे नामों से देश की जनता में विवेक और विचार पैदा कर रहा है तो वह जनसंघ पार्टी है और वह उन चीजों की तरफ जाना चाहती है जो प्रतिक्रियावादियों से भी और भी अधिक प्रतिक्रियावादी है और इसलिये आप यह कोशिश ही न करें तो अच्छा है कि आप समाजवाद को समझें।

फिर भी मैं समझता हूं, उन्होंने बहुत सी आर्थिक पहलू और दूसरे पहलू की बातें उठाई। मुमकिन है, सरकार की निगाहों में उनके सुझाव ठीक हों, जैसे मैं उदाहरण दूं। नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये; अच्छी बात है। उनके साधनों की ओर सरकार ध्यान दे। यही बात बहुत जोरदार ढंग से कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने भी कही है। हमारा मुंह उधर की तरफ होना चाहिये। उधर वाले भी समझते हैं कि हमारा मुंह इधर होना चाहिये ताकि सही तौर से बढ़ती हुई इकोनोमी को हम और आगे ले जा सकें।

एक बात काफी जोर से कही गई। आज हमको पता चलना चाहिये कि हमारी इतनी इन्डस्ट्री और व्यवसाय, काम-धन्धे दो योजनाओं के काल में हमने बढ़ाने की कोशिश की है और उससे जो हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ी है आखिर देश का कोई तबका तो है जो उस सबका फायदा उठा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिये कि आखिर वह तबका कौनसा है जिसको यह सब फायदा मिल रहा है? जो इन डेवलपमेंट के कामों का फायदा उठता है उसे ही हमारे टैक्स का इन्सीडेन्स बनाया जाना चाहिये। बजट स्टडी को मैंने देखा। यह हमारे लिये गौरव की बात है कि जो डेवलपमेंट हमने किया है और उसका जो चार्ट इसमें दिया गया है उससे पता लगता है कि हम

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

हिन्दुस्तान में अपनी जगह ऐसी रखते हैं कई मानों में तो हम यू. पी. से भी आगे बढ़े हैं।

वित्त मन्त्री ने सारी चीजें हमारे सामने रखी हैं। टैक्स अवश्य लगावें आप, पर उसका इन्सीडेन्स उस तबके पर पड़ना चाहिये जो तबका आगे जा रहा है, जिसने इस योजनाबद्ध विकास का फायदा सबसे ज्यादा उठाया है। उस तबके को हमें ध्यान में रखना चाहिये, उसे छांट कर अलग निकाल देना चाहिये। मैं बड़े अदब से कहता हूं, वह तबका बच जाता है। मैं मिसाल के तौर पर बताऊं। यहां बड़ी बड़ी मिलें हैं, और भी लगने वाली हैं; हमें उनको यहां लाना है, लगाना है। पर इसके साथ यह नहीं भूल जाना चाहिये कि इस तरह के उद्योग या उद्योगपति आ रहे हैं या आ गये हैं और जो वे मुनाफा कमाते हैं और इस राजस्थान की गरीबी को दूर करने के लिए वे यहां आ रहे हैं और इन्डस्ट्री लगा रहे हैं तो अगर वे जम गये हैं और मुनाफा कमा रहे हैं तो सरकार को उनसे बराबर अपना हक लेना चाहिये, टैक्स उन पर भी लगने चाहिये, बोनस भी मजदूरों को उनसे मिलना चाहिये। मैं मिसाल के तौर पर कहूँ। बॉल बियरिंग की इन्डस्ट्री है यहां पर। यह इन्डस्ट्री काफी पनप चुकी है और दूसरी कम्पनियां हैं जो काफी पनप चुकी हैं। इनको बिजली देते समय यह नहीं होना चाहिये कि टैक्स नहीं लगेगा। आज इन इन्डस्ट्रियों को टैक्स से बरी करना मेरी नाकिस राय में गलत होगा। हमें इस तरफ जरूर गौर करना चाहिये। हम टैप करें उनको जिनको काफी अर्सा हो गया है, फायदा हुआ है। तो मजदूरों का जो हक है वह उनको दिलाना चाहिये, सरकार को देखना चाहिये कि इस फायदे में से मजदूरों को बोनस मिले। सीमेंट की कम्पनियां हैं। तो हमें उनकी तरफ निगाहें करनी हैं और अपने घाटे की पूर्ति उनसे भी पूरी करनी है।

तो मैं अर्ज कर रहा था इस बारे में। अब जो टैक्स इस बजट में लगाये गये हैं संक्षेप में मैं उनके बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं।

कांग्रेस प्रोहिबिशन के सिद्धान्त से किसी न किसी रूप में बंधी है और यह भी सही है कि इस तीसरी योजना में सरकारी व्यवस्था कुछ ऐसी की गई है कि इसके प्रोहिबिशन से राज्य सरकारों को नुकसान होगा उसकी पूर्ति केन्द्रीय सरकार करेगी। उस सिलसिले में मैं अगर गलत नहीं कहता तो ऐसी प्लानिंग भी हुई है कि पांच पांच डिस्ट्रिक्ट इस प्रोहिबिशन में लेते जावेंगे। आज सरकार एक्साइज़ ड्यूटी से १५ लाख वसूल करने की कोशिश में है। आप १५ के ३० और ४५ कर लें। यह वह तबका है जिससे किसी को कोई सहानुभूति नहीं है। शराब पीने वाले के कोई पास भी खड़ा नहीं होता। पर उसकी जो मानसिक स्थिति है, मनोवैज्ञानिक स्थिति है उस पर कोई गौर नहीं करता। उसकी शिकायत गलत मानी जाती है। जब सरकार खुद इसमें एक्साइज़ टैक्स लेती है तो उसका यह भी कर्त्तव्य हो जाता है कि उस तबके के साथ जो समाज से बहिष्कृत तबका है, जिसकी समाज में बात नहीं सुनी जाती, मैं चाहता हूं पैसे के मामले में उसकी बात सुनी जानी चाहिये।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

आज शराब पीने वाले से पूछिये तो सही; उसे पूरा बोतल में पाव भर नशा भी नहीं दिया जाता। कारण इसका है, हमारी कुव्यवस्था। इसके अन्दर आप नीलाम करते हैं दूकानों को।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपके कहने से विश्वास करें या एक्सपीरियन्स से ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप कहने की हिम्मत नहीं कर सकते। आपको इसका काफी पहले से एक्सपीरियेन्स है।

श्री भैरोंसिंह : वह तो आपको और मुझको दोनों का साथ ही एक्सपीरियेन्स हुआ है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप अपनी संस्कृति की वजह से दूर हैं। तो मैं उनकी दिक्कतों के बारे में कह रहा था।

श्री भैरोंसिंह : उनके वोट तो आपके पक्के हो गये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वोट की बात नहीं है। आप गौर करें। एक ठेका है। मैं मिसाल के तौर पर बतलाता हूँ। आंख में उंगली डालकर नहीं बतलाना पड़ेगा। यह साफ मसला है एक बहुत बड़े करप्शन का। बहुत करप्शन की बात कहते हैं, पर कहता हूँ इससे बड़ा क्या करप्शन होगा ? यह ठेका दस साल से एक जगह है। हर साल आप बोली लगाते हैं और एक लाख रुपया बोल कर देते हैं। और एक्साइज़ जो सरकार सप्लाई करती है उससे उसको क्या आमदनी होती है, यह भी कभी आपने जानने की कोशिश की ? ईमानदारी से उसकी चोपड़ियां, बही खाते, हिसाब, प्राइवेट हिसाब उठा कर देख लें बीस हजार से ज्यादा का फायदा नहीं होता। फायदा बीस हजार से ज्यादा नहीं होता, पर आपको वह बोली में एक लाख दे देता है। मुनाफा उसको बीस हजार होता है। पर ठेके में आपको एक लाख देता है और फिर भी दस साल से वह वहां बैठा है।

(३. म. प.)

और आप एक लाख लेते हैं और बड़े शौक से आपके ऑफिसर लोग बोलियां बुलवाते हैं और उसके बाद एक लाख रुपया वे लोग दे देते हैं। फिर भी इतना पैसा देने के बावजूद वह बहुत मजे में है। क्यों है ? उसका कारण यह है कि उस शराब के साथ किसी की सहानुभूति नहीं है। आज दूध के अन्दर कोई एडल्ट्रेशन करता है तो उसके ऊपर ५००)रु० का जुर्माना हो जाता है और अगर शराब के अन्दर किसी तरह की एडल्ट्रेशन होती है तो उसके लिए कोई नहीं कहता। जब वहां पर लोग पीने के लिए जाते हैं और वह कुछ कहते हैं तो उसका जवाब यह दिया जाता है कि पानी नहीं तो क्या तुमको शराब पिलायेंगे, हमने एक लाख रुपया दिया है। वह गरीब आदमी जो ३) रुपया कमा कर वहां पर जाता है उसके लिए आप कह सकते हैं कि उसको नहीं जाना चाहिये; मैं भी मानता हूँ लेकिन जब आपने शराबखाने खोल रखे हैं तो उसके अन्दर उसको भी जाने की आदत है तो वह वहां जाता है और वह यह सोच कर चलता है कि मैं आज एक रुपये की तो शराब पीऊंगा और दो रुपये बीबी को

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

दूंगा, लेकिन जब वह पीता है तो उसको एक रुपये की शराब में नशा नहीं होता और वह दो रुपये की शराब और पी जाता है....

श्री हरिराम धारू (सिवाना-सु.) : उनकी यूनियन बनवा लीजिये और उसको रजिस्टर करवा लीजिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इस तरह से वह तीनों रुपये फूंक कर चला आता है और उसके बाद कहीं जाकर उसको नशा होता है या नहीं; इसका पता नहीं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इसमें दो राय नहीं है कि अगर आप शराब की दूकानों का नेशनलाइज़ेशन कर दें तो अच्छा हो। मैं कहता हूं कि आज कितनी इल्लिसिट शराब बनती है और वह ठेका १ लाख का लेते हैं और फिर भी फायदे में रहते हैं। मैंने देखा है कि आज एक ही आदमी के पास दस साल से ठेका चला आ रहा है। वह कैसे करते हैं ? शराब को अपने यहां खिंचवाते हैं और एक्साइज़ की चोरी करते हैं और इसकी वजह से उनको फायदा होता है। आप ठेके के पैसे नहीं लेते हैं; बल्कि लाइसेन्स के लेते हैं और इस तरह से करके आप उनको कह देते हैं कि चाहे जिसको पिलाओ, किसी को भी दो हमें तो एक लाख रुपया दे दो। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि इससे बड़ा करप्शन और कोई नहीं हो सकता। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि कम से कम एक साल के लिए आप दूकानों को नेशनलाइज़ करके देखें। हमें सोचना ही होगा इस बात के लिए कि कोई ऐसा कदम उठायें। मैं बड़े अदब से कहता हूँ, क्योंकि इस विभाग में ईमानदार ऑफिसर्स भी हैं उनका कहना है कि हम एक लाख रुपया एक्साइज़ से भी ले सकते हैं। आप यह काम करिये उसके बाद १५ लाख रुपये उनके ऊपर लगायें। मैं कहता हूँ कि वह आदमी बिना पीये नहीं रह सकता है; यह डॉक्टर पूरी तरह मानते हैं। तो मैं इस एक ही टैक्स के बारे में नहीं कह रहा हूँ; बल्कि मैं और भी आपको बताऊं कि हमारे पंजाब के अन्दर विलायती शराब के ऊपर १५ पर्सेन्ट टैक्स है, मैं गलत नहीं कहता। अगर मैं गलत हूँ तो आप फोन करके अभी पूछ लें कि वहां पर २५ लाख रुपये की सालाना इन्कम विलायती शराब पर टैक्स लगाने के कारण होती है। लेकिन यह सरकार जो राजस्थान के बजट के तखमीने बनाने वाली है, जो विलायती शराब है उसके ऊपर टैक्स नहीं बढ़ाती। क्यों नहीं बढ़ाती ? इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है और वह राज यह है कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं और ज्यादा तनख्वाह पाने वाले लोग हैं वे विलायती शराब को पीते हैं और इसकी जितनी शराब की दूकाने हैं; उनको राजस्थान सरकार देखती तक नहीं है कि इस विलायती शराब को मंहगी की जाय। अगर यह मंहगी कर दी जाती है और इसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है तो इससे रुपया भी आयेगा और जनता भूखों भी नहीं मरेगी और न वह लोग भूखों मरेंगे जो कि इसे पीते हैं। आप जो यह १५ लाख रुपया इस देशी शराब पर टैक्स लगा कर अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं इसको आप एक्साइज़ से छोड़िये; आप इस देशी ठर्रे को छोड़िये। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि १५ लाख रुपये का टैक्स विलायती शराब पर

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

लगाइये। इसके ऊपर आपको जितना टैक्स लगाना है उतना लगा दो। आप देशी ठर्रे पर से हटा दीजिए और १५ परसेंट विलायती शराब पर लगा दीजिये। जितना आप चाहें उतना लगा दें। तो मैं यह सुझाव पेश करना चाहता हूं कि आप खास तौर पर इस विलायती शराब की तरफ ध्यान दीजिये और आपको जो निलामी के तरीके से पैसा आने वाला है उतना ही एक साल के अन्दर आपके द्वारा खोली गई दूकानें बेचें और सही तरीके से एक्साइज़ को वसूल करें तो उसको आप देखें कि आप कितने घाटे में रहते हैं बनिस्बत इसके कि आप इस प्रकार से देशी शराब पर टैक्स लगायें और छोटे लोगों की चर्चा का विषय बनें। मैं टैक्स का विरोध नहीं करता, पर मैं कहता हूँ कि जो टैक्स का इन्सीडेन्स है उसको आप शिफ्ट कीजिये और जो लोग पे कर सकते हैं यह इन्सीडेन्स एक्चुअली उनके ऊपर शिफ्ट कीजिये। उसकी मिसाल

(समय-समाप्ति सूचक-घंटी)

मैंने आपको दी कि आप विलायती शराब पर टैक्स लगा दो। हर दफा हम देखते हैं कि जब भी बजट का मौका आता है तब ही बड़े लोग अपने कन्टर के कन्टर छिपा कर चोरी करने की कोशिश करते हैं। विलायती शराब के ऊपर ऐसी छूट है कि कभी किसी की निगाह में यह आती नहीं इसलिये मैंने आपकी निगाह इस ओर खींची है। इसकी तरफ आप देखें।

अब मैं नेशनलाइज़ेशन ऑफ ट्रान्सपोर्ट और कोऑपरेटिव की बात कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा। नेशनलाइज़ेशन की बात में स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि एक बात का फर्क हमें समझ लेना चाहिए। नेशनलाइज़ेशन के अन्दर मैं आपको बताऊं कि आज आप उसको भी शिकायत करते हैं, उसको भी बुरा बताते हैं, उसकी भी आलोचना करते हैं। मैं कहता हूँ कि सरकार कुछ भी करे, किराये में उसके कमी करे उसके लिए अगर वह कर सकती है तो करे, नहीं कर सकती है तो नहीं करे; लेकिन मैं एक फर्क समझाना चाहता हूँ और जो मौलिक फर्क है इस नेशनलाइज़ेशन में और प्राइवेट ओनरशिप में। जो नेशनलाइज्ड चीजें हैं उनका पैसा और मुनाफा आता है वह जनता के लिए आता है और सरकार में आता है और सरकार के जरिये वह मुनाफा फिर गरीबी से जो लड़ाई चल रही है उस तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ प्राइवेट ओनरशिप में वह सारा का सारा पैसा और सारी की सारी कमाई व्यक्तिगत होती है, न कि जनता की। इसी फ्लोर के ऊपर मैं बताऊं कि नेशनलाइज़ेशन को तरह तरह से क्रिटिसाइज़ करते हैं।

मैंने जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ था और उस पर बहस हुई थी उस समय भी सुनाया है और उस समय भी आपने कहा था कि यह सबसे ज्यादा करप्ट है। उस समय भी आप तरह तरह की बातें करके जोश के साथ ट्रान्सपोर्ट आथोरिटीज़ की चर्चा करते थे और किस तरह से थूक फाड़ फाड़ कर कहते थे कि इसके अन्दर जो करप्शन है उसको खत्म किया जाये और जब सरकार ने ट्रान्सपोर्ट में जो करप्शन था उसको खत्म करने के लिए

Page No 65

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

नेशनलाइज़ेशन की स्कीम बनाई तो उसके लिये भी आवाज आई कि नेशनलाइज़ेशन खराब है। मैं कहता हूँ कि कभी इनके मुंह से राम निकलने वाला ही नहीं है, यह आपको विश्वास रखना चाहिये। आप बार-बार कहते हैं कि को-ऑपरेशन करें। इससे जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसके अन्दर मैंने कोई फर्क नहीं देखा। यहां तो आज स्थिति यह है कि जो भी अच्छी बात करो उसके खिलाफ कोई न कोई दलील दे देना शुरू कर देते हैं। यहां तो कुछ पार्टियों ने यह रवैया अख्तियार कर लिया है कि गाल बजाओ टैक्सों की आलोचना करो, जो भी चीज आये उसकी खिलाफत करो, जनता को अपनी ओर आकर्षित करो और जनता में चाहे जो प्रचार करो। मैं कहता हूँ कि आज आजादी को प्राप्त किये हमें १४ साल हो गये और इस जनतंत्र के अन्दर वे नौजवान हैं जो कुछ करके दिखायेंगे····

(३.८ म. प)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

श्री भैरोंसिंह : ये वही नौजवान हैं जिनको बजट स्पीच में क्रिटिसाइज़ किया है और कन्डेम किया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वह भी आ रहा है, अभी।

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि वह बात आखिर की है। मैं यह कह रहा था कि यहां पर हम यह सोचते हैं कि अभी नेशनलाइज़ेशन के ऊपर बात चल रही थी कि वे लोग इसकी चर्चा करते थे और सारे राजस्थान के अन्दर इस बात की चर्चा करते थे और ल्युक्रेटिव प्रोविज़न समझा जाता था और यही कहते थे कि दो दो लाख रुपये की ट्रान्सपोर्ट में रिश्वत चल रही है इसको रोका जाय और जब सरकार ने इस करप्शन को रोकने के लिए नेशनलाइज़ेशन के जरिये कदम उठाया तो वही कहते हैं कि हम नेशनलाइज़ेशन के खिलाफ हैं। हम यह महसूस कर रहे हैं कि इस नेशनलाइज़ेशन के अन्दर हम लोगों को अधिक सुविधायें दे सकेंगे और इससे जो पैसा आयेगा उसका उपयोग जनता की भलाई के लिये करेंगे। जैसा आपने अभी कहा और मिसाल दी कि १६ लाख रुपया यू० पी० को मिला तो हम बाहर से उस रास्ते पर चले हैं। मैं समझता हूं कि हम इस रास्ते पर शुरू से चलते और मैं यह गुजारिश करूंगा सरकार से कि इस नेशनलाइजेशन को जल्दी से जल्दी किया जाय। यह राजस्थान का एक ऐसा टेप है, ऐसा रिसोर्स है कि कई दिक्कतों से गरीब जनता को बचा सकते हैं और बचाने के लिए तुरन्त इसके ऊपर कितने भी कहीं से साधन इकट्ठे करने पड़ें, पर आपको इसको नेशनलाइज़ करना पड़े और इसको आप जब नेशनलाइज़ कर देंगे तो आप प्राइवेट बस वालों से-उनसे बात करना शुरू कर देंगे और नेशनलाइज़ेशन नहीं करें तो करप्शन की बात करेंगे। इस तरफ बगैर ध्यान दिये कांग्रेस की पॉलिसी के अनुसार सरकार को निर्बाध रूप से बढ़ते हुए चले जाना चाहिए।

अब कोऑपरेटिव की बात है........

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : माननीय

(श्री हरदत्तसिंह)

सदस्य नौजवान वाली बात बीच में ही भूल गये ।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे समय का ख्याल रखें ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जी हां, आपकी तरफ देखता हूं तभी ख्याल आ जाता है ।

तो मैं कोऑपरेटिव की बात कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी के साथ यह एक तरह से विश्वास की बात है और इसलिए उसके मूल-भूत सिद्धान्त की बात है । वे उसके भाग को खा जाना चाहते हैं । जब एक मनुष्य के पास पूंजी नहीं रहती है तो दिक्कत में फंस जाता है । पूंजी नहीं होने की वजह से उसको गुलामी करनी पड़ती है उस आदमी की जिसके पास में पैसा है उसकी और वह शोषण करता है । उसको उस शोषण से बचाने के लिए सरकार ने इस तरह की जिम्मेदारी ली है कि अगर किसी आदमी में कमा कर खाने की क्षमता है, रोजी कमा कर खाने की क्षमता है तो उस क्षमता को आज उपयोग में लाना है । तो मैं समझता हूं की सारी दुनिया में सहयोग और कोऑपरेटिव मूवमेंट के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं है । या तो पूंजी-वाद को पनपायें और मनुष्य द्वारा मनुष्य को खाने की जो नीति है या वह तरीका अख्तियार किया जाय जो कम्युनिस्ट और दूसरे लोग अख्तियार करते हैं । जनतन्त्र के अन्दर अगर उस आदमी को बचाना चाहते हैं जिसमें will to work है, जो काम करना चाहता है लेकिन पूंजी नहीं होने से काम नहीं कर सकता है तो इस देश के अन्दर, इस जनतन्त्र के अन्दर उसका इलाज कोऑपरेटिव मूवमेंट है । उस कोऑ-परेटिव मूवमेंट के अन्दर दो तरह की कन्ट्रोवर्सीज़ हो सकती हैं । एक कन्ट्रोवर्सी यह हो सकती है कि जनता पढ़-लिख जाय, हमारी जनता होशि-यार हो जाय उसके बाद शुरू करना चाहिये । यह बात सही हो सकती है । यह एक विचार हो सकता है । लेकिन दूसरा विचार यह है कि उसके लिए हम कोई पीरियड मुकर्रर नहीं कर सकते । हमको चलना चाहिये । इसमें हम से गल्तियां होंगी, अगर इसके अन्दर उतरेंगे तो । कोई हमारा सिद्धान्त हो । वे चाहते हैं कि हमारा देश इस तरह से टुकड़ों में बंटा रहे । आज जो एक फेमिली के के साथ में बैठना चाहते हैं, फेमिली के बाद में जाति और रिश्तेदारों के साथ में जाना चाहते हैं इसके बाद वे हिन्दुओं में जाना चाहते है, लेकिन हम उनको हिन्दुओं से निकाल कर हिन्दु-मुस्लिम सबको मिला कर जाना चाहते हैं; हम कोऑपरेशन के जरिये जाना चाहते हैं, इस देश के जन-जीवन के अन्दर क्रान्ति लाना चाहते हैं । हम सिद्धान्त रूप से इस बात को कहना चाहते हैं कि हम सब भाई की तरह कंधे से कंधा लगा कर सहयोग की भावना से गरीबी को दूर कर सकते हैं । उसके सिलसिले में आपको हम अच्छी तरह से समझते हैं कि आपकी यह राजनीति है कि इनको लड़ा लड़ा कर चलाया जाय । तुम लोगों का विश्वास है कि देश के अन्दर इन चीजों के बढ़ावे को रोका जाय तो भाषा, प्रान्तीयता, जातीयता की ये जो गलत चीजें हैं उनको पनपाते हैं । जब अंधेरे में पांव नहीं टिकता है तो बार बार कोऑपरेटिव पर आते हैं और कोऑपरेटिव

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

मूवमेंट को गलत समझाने की जनता को कोशिश करते हैं। मैं आपको अपील करना चाहता हूं कि इसके पहलुओं को सोचें और इसके अन्दर राजनीति को नहीं लायें। यदि आप यह चाहते हैं कि इस देश के अन्दर सहयोग बढ़े और भाई भाई बन कर सब लोग एक तरह से रहें और यदि संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की कसम खा कर उस श्रद्धा और निष्ठा से असेम्बली को चलाना चाहते हैं तो कोई रास्ता नहीं है कि आप इस कोऑपरेटिव मूवमेंट के साथ न हों। कोऑपरेटिव मूवमेंट में गल्तियां हो सकती हैं। हम समझते हैं कि राइट अर्नेस्ट में हमने इसको शुरू किया है। गल्तियां जनता से होंगी। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। हम वह स्पिरिट लाना चाहते हैं कि देश के टुकड़े २ हों; इस तरह का जो सोचना है उसको निकाल सकें और तुम्हारे जैसे लोगों का मुकाबला कर सकें और तुमसे इस देश को बचा सकें।

मैं और यह भी कहना चाहता हूं कि यहां पर कोऑपरेटिव फार्मिंग के सिलसिले में बड़बड़ाहट हुई है। वह बड़बड़ाहट उस बात का संकेत है जिसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है। इस देश के अन्दर चाहे जिस तरह की राज्य व्यवस्था रही, जो भी राज्य व्यवस्था; चाहे अंग्रेजों की रही हो, उसके अन्दर कोई भी नीति रही हो, जनतन्त्र के अन्दर आपको याद होना चाहिये कि हमारी पॉलिसी बदल चुकी है। हम सब मिल कर रह सकते हैं। जनतन्त्र के अन्दर तो हम सब एक हैं। उस एकता की भावना को लाने में कोऑपरेटिव मूवमेंट हमारे साथ एक क्रीड होना चाहिये। जो जबरदस्ती नहीं करते हैं लेकिन हमारा क्रीड है कोऑपरेशन। उस कोऑपरेशन के अन्दर कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए बहुत-कुछ बातें कहते हैं। किसान जो कि भोला है उसको भड़काना चाहते हैं कि तेरे बाप का बरगद का पेड़ नहीं रहेगा, तेरे बाप की जमीन नहीं रहेगी, पब्लिक की रहेगी। जमीन जैसे कोई ऐसी चीज हो और जिसको कोई उठा कर ले जा सकता हो! जमीन पब्लिक की रहने वाली है। वह जमीन उसी गांव में रहने वाली है। वह जमीन उसके बाप-दादा की रहने वाली है, उसकी रहने वाली है। कोऑपरेशन दो तरह का होता है। एक कोऑपरेशन इस तरह का होता है जिसमें जमीन भी उन्हीं की रहती है, कोई निकलना चाहे तो जमीन भी ले सकता है। लेकिन यदि किसान सहयोग से मिल कर काम करना चाहते हैं तो हम ऐलान करना चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार उनकी पहले मदद करेगी। उसका कारण है पहले मदद करने का। आप जैसा हम नहीं सोचते हैं। वह जनता उसके लिए रेस्पोन्सिबल होती है। जो एक दूसरे को सहयोग करने की वजह से एक दूसरे के जमानतदार होते हैं उसको वजह से पूंजी भी ठीक तरह से मिलती है और ठीक तरह से काम होता है। आज हम सब को सहायता देते हैं। सरकार व्यक्तिगत रूप से भी सहायता देती है तो ११ आदमी मिल गये और कोऑपरेशन करके काम करने लगे तो जो एक आदमी को तकाबी देते हैं तो ११ आदमियों की तकाबी देते हैं और कोऑपरेशन को आगे बढ़ाते हैं और सिद्धांत रूप से इस देश में करने की कोशिश करना चाहते हैं तो आपकी ये चीं चीं हमारी समझ में नहीं आती हैं। हम आपकी इस चीं चीं को सुनने वाले नहीं हैं।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

मैं जो दूसरी बात कहना चाहूँगा वह नौजवान की बात कहूंगा। उस बात को जिस तरह से आपने तोड़ा-मरोड़ा है वह वास्तविक बात नहीं है। बात इतनी है और वह बात है कि शायद मिनिस्टर साहब ने तय कर लिया हो कि अपने बेटे को मैट्रिक के बाद किसी कारखाने में भेजेंगे। यह बात भी हो सकती है कि आपको उन्होंने कुछ कह दिया हो। लेकिन एक बात हमको माननी पड़ेगी कि राजस्थान में शिक्षा के अन्दर जो पहल किया है, उसके ऊपर चाहे उसको आज रिटर्न नहीं मिलता हो, इसका खतरा लेते हुए भी राजस्थान के बालकों को शिक्षित करने के लिए इस कांग्रेस सरकार ने अधिक प्रयत्न किया है। १४ साल से जो प्रयत्न किए गये हैं उनको आज इस तरह से नहीं निकाल सकते हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : शिक्षित करके क्या खतरा ले लिया ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : खतरा मोल ले लिया क्योंकि पैसा खर्च कर दिया हिम्मत करके।

(अनेक माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री सभापति : Order ! Order !!

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : खतरा यह लिया है कि हमने मनुष्य का विकास करने में हमारी जो जनता है उसका शिक्षा के जरिये विकास किया है; उसका कोई रिटर्न आगे भी नहीं होने वाला है। आदमी का विकास, जनता का विकास करने के लिये शिक्षा को आगे बढ़ाया है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह खतरा कैसे है ? यह तो अच्छी बात है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : पैसा आपके बाप का था जो खर्च किया ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : खतरे की पूंछ पकड़ लें तो आपका ही बिगड़ेगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला है।

श्री मुरलीधर व्यास : पकड़ कर रखें तो अच्छी बात नहीं, परन्तु निकाल दें तो अच्छा रहेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: आपको मन्शा यह है कि २० मिनट और बोलूं।

मैं अर्ज कर रहा हूं कि शिक्षित किया है, पर्सेन्टेज के आंकड़े उठा कर देखें कि सारी स्टेट के अन्दर, सारे राजस्थान के अन्दर क्या पर्सेन्टेज लिट्रेसी की उस वक्त थी। जो अजमेर उस समय सैकन्ड था मद्रास के बाद में- वह राजस्थान का हिस्सा जो अंग्रेजों के पास था, सैकन्ड था........

१२ पर्सेन्ट तो वहां पर उस वक्त भी थी और आज राजस्थान में जहां पहले ४ और ५ पर्सेन्ट से अधिक नहीं थी उसको इतना ऊपर उठाकर लाकर रखा है तो शिक्षा के मामले में मैं यह कहना चाहता हूं, उस नौजवान को कहा गया है उस तरह से कहना मैं तो किसी हद तक गलत मानता हूँ, सही बात इस तरह से कहना चाहता हूं। उसकी पूंछ नहीं मिलती, मुंह नहीं मिलता, बीच में आया इसलिए कह दिया है।

Page No 69

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

सही स्थिति यहां बताना चाहता हूं कि आज भी राजस्थान विश्वविद्यालय बराबर चलेगा और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और दूसरे जितने भी लोगों की जरूरत की चीज़ें हैं उनके लिए इस पैराग्राफ से यह कभी भी मत सोचना कि हमें इस नोजवान को छोड़ना है। हम बराबर राजस्थान में एजुकेशन के साथ चलेंगे। इसके बारे में कुछ भी कहा जाय, कुछ भी कहा होगा लेकिन कोई कॉलेज बन्द नहीं होगा। इंजीनियरिंग कॉलेज बन्द नहीं होगा मेडिकल कॉलेज बन्द नहीं होगा। सबको भर्ती होने का पूर्ण अधिकार है। जो अच्छे से अच्छे नम्बर लायेंगे उनको हक है। यह कहें कि आप फायदा उठाते हैं नौजवान उसका फायदा न उठावें, इसमें संकेत है। हमारे उन बच्चों को, जो शिक्षा ले रहे हैं आप उनको जिस तरह से बुला बुला कर जिस तरह से आर. एस. एस. और दूसरी चीजों में कठ-मुल्ला बनाना चाहते हैं उससे खतरा मालूम होता है। दिमाग की खिड़कियां बन्द कर रहे हैं जिससे कि वे ज्ञान या नॉलेज का अर्जन न कर सकें। उनको अपने तरीके से कठमुल्ला बनाना चाहते हो, उसको हम ज़रूर रोकना चाहते हैं। उसके लिए हम कहते हैं कि दिमाग की आजादी हो। अच्छे-बुरे का ज्ञान कर सकें, उसके बाद राजनैतिक और सामाजिक जीवन में आवें। राजनीति में आने से पहले जो किंवाड़ बन्द करना चाहते हैं वह नहीं करने देंगे। थोड़े से बच्चों को बचाने के लिए कहा होगा।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री सभापति (श्री भीमसेन) : श्री विजयसिंह।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवा महल, जयपुर) : मैं अपने अपूर्ण भाषण को पूरा कर दूं।

श्री सभापति : आप बोल चुके हैं। श्री विजयसिंह।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : माननीय सभापति महोदय, अभी एक माननीय सदस्य ने अपना जोशीला भाषण दिया। कुछ जोश उन्होंने जनसंघ को गालियां निकाल कर ठण्डा किया और कुछ जोश और दूसरी........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of order, sir ये लफ्ज़ एक्सपन्ज किए जावें।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : सीट पर से होना चाहिए दूसरी जगह से नहीं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं कहता हूं कि मैंने कोई गाली नहीं दी....

श्री सभापति : Shri Vijay singh to continue.

श्री विजयसिंह झाला : सभापति महोदय, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि दरअसल में आप बहुत कुछ कहना चाहते थे लेकिन आप दब गये, डर गये। दब गये इससे सबक लेंगे और आयन्दा जनसंघ के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे। पूरा बोलते तो अच्छा रहता।

(श्री विजयसिंह झाला)

आज जितने भी हमारे शासक पार्टी के सदस्य बोले हैं उन सब के भाषणों से यह स्पष्ट होता है कि दरअसल में जो बजट हमारे सामने हैं उससे उनको भी संतोष नहीं है। खास कर के राजसमंद से जो माननीय सदस्य आये हैं और उन्होंने कल जो सुझाव रखे हैं उन सब सुझावों का मैं स्वागत करता हूं। ऐसे सुझाव रखने वाले व्यक्ति यदि उस दल को छोड़ कर इधर आते तो उनका ज्यादा मान होता और इसी प्रकार आज जो माननीय सदस्य बृजसुन्दरजी शर्मा बोले हैं उनके सुझावों का भी मैं स्वागत करता हूँ और उन सब सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि दरअसल में उनका सम्मान इधर आने से ज्यादा होगा। जो सुझाव रखे हैं उन पर यदि आपकी पार्टी कोई कार्यवाही नहीं करती है या एक्शन नहीं लेती है तो उसके बाद में आप का क्या आगे का कार्यक्रम होगा, इस सुझाव के साथ इस सदन के समक्ष विचार रखते तो बहुत अच्छा होता।

जहां तक माननीय वित्त मंत्रीजी का सवाल है, उन्होंने खुद ने ही स्वीकार किया है कि बजट रखते समय बहुत कम समय था इसलिए जो असली तत्व बजट के थे उन पर पूरा विचार नहीं कर सके इसलिए यह बजट इस रूप में हमारे सामने आया। मुझे ऐसा मालूम होता है कि माननीय वित्त मंत्रीजी को, जो आज तक आर्थिक नीति हमारी सरकार की रही उससे असंतोष जरूर है। यह असंतोष उनका उनके इस प्रवचन में कई जगह झलका है। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि यह बात उन्होंने दबी जुबान में कही है। वे बहुत कुछ कहना चाहते थे, इसमें सुधार भी करना चाहते थे लेकिन अपने अन्य साथियों के दबाव के कारण सही स्थिति बजट में नहीं रख सके, ऐसा मालूम होता है।

मैं अब वित्त मंत्रीजी के भाषण के पैरा नं० ६ वर्ग ३ पर आता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार पर बहुत भार पड़ा है। उसको भारत सरकार से १५ करोड़ रुपयों का लोन लेना पड़ा है इसलिए उलझन थी उसको सोल्व किया। मैं नहीं समझता कि ये १५ करोड़ रुपये लेकर हमारी जो उलझन थी उसको कैसे सोल्व किया गया। क्योंकि हमारे पर कर्जा था उसकी अदायगी कर्जा लेकर की। यह तो ठीक उसी तरह की बात हुई कि किसी बीमार के पेन है उसको मोर्फिया का इन्जेक्शन लगा कर कम करने की कोशिश की जाय तो मोर्फिया के इंजेक्शन से पेन दूर नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से वित्त मंत्रीजी ने १५ करोड़ रुपयों के लोन का आधार बताया वह यह बताया कि महान् आपत्ति थी उसको टालने के लिए यह लोन लिया गया। लेकिन मेरी समझ में यह आपत्ति टली नहीं है। कुछ देर के लिए कर्ज को लेकर कर्ज के रूप में चुकाया गया है।

उसके बाद इम्पोर्टेन्ट बात यह है कि जो अनुमान लगाया गया था उससे ज्यादा खर्चा हुआ। इस बात पर कई सदस्य महानुभाव बोल चुके हैं और अभी जो माननीय सदस्य बोले उन्होंने फाइनेन्स डिपार्टमेंट को जिम्मेदार बताया। जिस वक्त अनुमान बताया वह अनुमान सही नहीं था। मैं इस बात पर अपनी ओर से भी जोर देता हूं और वित्त मंत्रीजी

(श्री विजयसिंह झाला)

से निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार आंकड़े आवें उस पर स्वयं विचार करें। यह हो सकता है कि आंकड़े सही आवें लेकिन आगे चल कर दूसरे मदों के अन्दर आंकड़ों से अधिक खर्च किया जाता है वह सही रूप से नहीं है। जैसे जागीर बोन्ड्स के बारे में ८० लाख से ज्यादा के बोन्ड्स देने के लिए वित्त मंत्रीजी ने कहा है तो मैं जागीर कलेक्टर्स की एफिशियेन्सी की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि ऐसे बोन्ड्स जो जागीरदारों को मिलने चाहिये थे वे उनको इसलिए नहीं मिले कि उनके मामलों में मामूली उलझनें थी और जब तक वे उलझनें पूरी नहीं होंगी तब तक बने बनाये बोन्ड्स ट्रेज़री ऑफिसर्स के पास पड़े हैं, उन पर ब्याज सरकार को देना पड़ेगा। सक्सेशन सर्टीफिकेट के लिए जागीरदारों की दस-बारह महीने तक पेशियां करनी पड़ती हैं। इस प्रकार लाखों रुपये के जागीरी बोन्ड्स बने हुए हैं जो एक महीने में वितरित हो सकते हैं। वह एक मामूली कानूनी उलझन की वजह से ट्रेज़री ऑफिस में पड़े हुए हैं, उन पर सरकार को ब्याज देना पड़ रहा है। यह सारी व्यवस्था जागीर कमिश्नर साहब की है जिसकी वजह से सरकार को ब्याज जागीरी बोन्ड्स पर देना पड़ता है।

जहां तक चंबल डेम में २० लाख रुपया ज्यादा खर्च करने की बात है इसके लिए मैं कह सकता हूं कि यह तो जिस वक्त अमल में लाया गया, जिस तरह से लाया गया वह गलत था कि इसमें कई प्रकार के घोटाले हो सकते थे। हमारी व्यवस्था इसमें ठीक नहीं है। जो इर्रिगेशन के लिए १९५९-६० में अनुमानित आंकड़े थे उनके अनुपात से ११ करोड़ की आमदनी कम हुई है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि किसानों को दरअसल में जो इर्रिगेशन का साधन मिलता है उसके प्रति उनमें निश्चिन्तता नहीं है। मैं आपको नमन बांध का उदाहरण देता है। इस वर्ष जब फसल बोई गई और सिंचाई हुई तो नहर टूट गई और दस-बारह दिन तक पानी नहीं मिला। इस प्रकार इर्रिगेशन के द्वारा पिलाई होती है और जब किसानों को समय पर पानी नहीं मिलता है तो इससे किसानों में असंतोष बढ़ता जाता है। इसलिए जहां नहर होती है वहां पर नहर से सिंचाई न करके किसान अपने खुद के साधनों से काम चलाते हैं। इसके बाद जहां पर नहर बनी हुई है उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है। जहां तक नहर से पिलाई होने के बाद प्रोडक्शन का सवाल है तो जहां नहर से पिलाई होती है वहां प्रोडक्शन कम हो गया है। ये बातें हैं जिनकी वजह से किसानों को असंतोष है। इस वजह से हमारे इर्रिगेशन के अन्दर हमारी कम आमदनी होती जा रही है। मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार इस ओर भी ध्यान देगी।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था और इस सिद्धांत का विरोध किया था, 'Cut your coat according to your cloth.' मैं समझता हूं कि जहां तक हमारे पास पूरे साधन नहीं हैं तो इतनी बड़ी योजना लेकर क्यों चलें जिसकी पूर्ति नहीं कर सकते। सैकंड फाइव इयर प्लान में जो योजनायें थीं और जो माइनर इर्रिगेशन की योजनायें थी, यदि आप किसी एक क्षेत्र को लेकर चलें तो पता चलेगा कि ६० प्रतिशत योजनाएं अधूरी

(श्री विजयसिंह झाला)

पड़ी हुई हैं । मैं आपको बड़गांव का उदाहरण देता हूँ जहां पर दस इर्रिगेशन की योजनायें बनाई गई थीं, वे अधूरी रह गई हैं । इसी तरह खमनोर पंचायत समिति के विकास का सवाल है । वहां पर जो इर्रिगेशन की योजनायें बनी, वे अधूरी पड़ी हुई हैं । इस स्थिति में जो पहले योजनायें चलाई गई हैं और जो अधूरी पड़ी हुई हैं उसके बाद भी नई माइनर इर्रिगेशन की योजनायें बना रहे हैं । तो पहले जो खर्च किया है, जो पैसा खर्च किया है, उसका क्या हाल होगा ? उसका क्या होना है ? मैं उदयपुर जिले के उदाहरण दूं कि २४.०० लाख रुपया सार्वजनिक मकान के लिए रखा है, ३६.४१ लाख रुपया सिंचाई के लिए रखा है, ११.३ लाख रुपया सड़क पर रखा है । मैं समझता हूं कि मकान के लिए खर्च न करके उसे माइनर इर्रिगेशन के लिए खर्च किया जाय तो माइनर इर्रिगेशन के अन्दर जो अधूरे काम पड़े हुए हैं वे पूरे हो सकते हैं और इससे प्रोडक्शन बढ़ सकता है और उसका रिटर्न ज्यादा आ सकता है । इस प्रकार एक जिले में सार्वजनिक निर्माण के लिए २४ लाख और ३६ लाख रुपया खर्च करके वास्तविक इम्पोर्टेन्स की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है, इससे आगे जा कर मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा ।

जहां तक टैक्स लगाने का सवाल है मैं नहीं जानता कि चने पर क्यों टैक्स लगा दिया गया है जब कि विदेशी शराब आती है उस पर नहीं लगाया गया है । दरअसल में एक ऐसी चीज पर टैक्स नहीं लगना चाहिए जो प्रान्त की जनता के काम में आती है और गरीबों के काम में आती है । चना एक ऐसी चीज है, जो गरीब आदमियों के काम में आता है उस पर टैक्स लगाया है तो फिर विदेशी शराब के ऊपर क्यों नहीं लगाया गया है ? मैं नहीं समझता हूँ कि ट्रेजरी बैंचेज के कोई मंत्री महोदय विदेशी शराब को काम में लेते हों लेकिन यह एक शंका पैदा करता है कि इस पर क्यों नहीं लगाया गया जब कि चना, जो गरीब आदमियों के द्वारा काम में लिया जाता है, उस पर लगाया गया है ।

जहां तक अखबारी कागज को टैक्स से मुक्त किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं । लेकिन इसके साथ ही उन विद्यार्थियों के प्रति ध्यान नहीं दिया जाता है जो पुस्तकें खरीदते हैं, कॉपियां खरीदते हैं । यह उचित नहीं है । मैं समझता हूँ इनको भी टैक्स से मुक्त किया जाय तो बहुत अच्छा होगा । इससे, गरीब जनता के लड़के जो दरअसल में आज पढ़ने के लिए खर्च नहीं कर सकते उनको फायदा होगा ।

इसी प्रकार बिजली के अन्दर कल-कारखानों को टैक्स से मुक्त किया गया है लेकिन जो विद्यार्थियों को पढ़ाने वाली इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनको कर से मुक्त क्यों नहीं किया गया है ? यह उनके हित का सवाल है ।

इन सारी नीतियों से स्पष्ट होता है कि हमारे वित्त मन्त्रीजी के सामने एक बजट आया, किन्हीं ऑफिसर्स ने बना कर दिया उसी पर उन्होंने दस्तखत कर दिये हैं और ध्यान नहीं दिया है । इसलिए वे यह कह कर सदन को संतोष दिलाना चाहते हैं कि उन्हें समय कम मिला । अगर दरअसल में उनको समय

(श्री विजयसिंह झाला)

कम मिला तो वह बढ़ाया जा सकता था लेकिन जो वास्तविक तथ्य हैं उन पर विचार न करें, यह कभी नहीं हो सकता । मैं मानता हूँ कि उनको समय कम मिला तो विरोधी पार्टियों को भी तो समय कम मिला है, इसलिए हम इसका अध्ययन नहीं कर पाये । तो इसलिए कम समय की बात कह कर तथ्यों पर विचार नहीं हो, तो यह अच्छी परिपाटी नहीं है ।

जो पत्थर पर छूट दी गई है, इसके साथ ही मिट्टी, रेत, बजरी पर छूट नहीं दिया गया है........

('दिया गया है', 'दिया गया है' की आवाज)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : पहले से ही छूट थी ।

श्री विजयसिंह झाला : नगरपालिकाओं को दी जाने वाली राशि पन्द्रह लाख से पच्चीस लाख तक बढ़ा दी गई है, लेकिन पचास प्रतिशत श्रमदान उसके लिए रखा है । यह बिल्कुल गलत है । यदि नगरपालिका के लिए इस प्रकार पचास प्रतिशत श्रमदान की बात रखी गई तो मेरी समझ में कोई नगरपालिका अपने कर्मचारियों की तनख्वाह का भुगतान भी नहीं कर सकती । इसलिए पचास प्रतिशत श्रमदान करके वह सरकार से रुपया लेगी; यह सम्भव नहीं हो सकता ।

कपास और तिलहन पर जो टैक्स लगाया गया है वे ऐसी चीजें हैं जो सार्वजनिक रूप से गरीब जनता के लिए काम में लाई जाती हैं । कहने का तात्पर्य है कि जितने भी टैक्स लगाये गये हैं वे उन चीजों पर लगाये गये हैं जो गरीब जनता के काम में आती हैं ।

जहां तक पैसेन्जर टैक्स का सवाल है उसके सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि पैसेन्जर टैक्स जो पहले लगाया गया था वह गरीब जनता से वसूल हो गया था लेकिन चौधरी बस कम्पनी, नाथद्वारा ऐसी है, उसके द्वारा, जिस दिन से टैक्स लगा उस दिन से गरीब जनता से वसूल हो गया लेकिन वह टैक्स सरकार के डिपार्टमेन्ट में जमा नहीं हुआ और उस पैसे का मुनाफा लिया जाता है-उस पैसे से मोटर मालिक अपना धन्धा चलाते हैं और उस पैसे को ब्याज पर चलाते हैं । तो यह टैक्स ऐसा है जो गरीब मजदूर जनता पर पड़ता है और मोटर मालिक बीच में इस पैसे का फायदा उठाते हैं । इसके बजाय यह अच्छा होता कि जो मोटर मालिकों में टैक्स बकाया हैं उसको लेने की कोशिश की जाती । मेरी समझ में तो मुख्य मन्त्रीजी या कोई मंत्री किसी मोटर मालिक की मोटर में सफर करें तो उल्टे मोटर मालिक को उन पर खर्च करना पड़ेगा ; उनको किराया नहीं देना पड़ेगा । इसलिए जो पेसेन्जर टैक्स का भार है वह उन्हें मालूम नहीं हो सकता । आज ऐसी स्थिति है कि एक दो-आने बचाने के लिए एक गरीब आदमी दस मील पैदल आगे जाकर बस में बैठता है । इसलिए उस गरीब आदमी पर पांच पर्सेंट और टैक्स लगाना कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं माना जा सकता । इस तरह ८० लाख रुपये जो मोटर बसेज़ खरीदने के लिये खर्च किये गये हैं, उनका भी सही उपयोग नहीं हो पाया है । बहुत सी बसें

(श्री विजयसिंह झाला)

ऐसी पड़ी हुई हैं जो काम में नहीं आ रही हैं। इस प्रकार से खर्चा करके राजस्थान के बजट को घाटे में डाला जावे और फिर उसकी पूर्ति के लिये टैक्स लगाना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि ६० लाख का इन्डस्ट्रियल लोन दिया जिसका उल्लेख सैकन्ड फाइव इयर प्लान में नहीं था। यह क्यों दिया गया ? मेरे ख्याल से यह सब इलेक्शन स्टन्ट था और उन लोगों को इन्डस्ट्री के नाम पर रुपया दिया गया जिन्होंने कोई इन्डस्ट्री नहीं चलाई और इन रूपयों की वापसी भी होगी या नहीं; इसमें भी मुझे शंका है।

मिनिस्टर साहब की तनख्वाह में ८ लाख ८२ हजार रूपये रखे हैं; ८ लाख ४६ हजार की जगह किये गये हैं। यों तो हम एक तरफ त्याग की भावना को बात कहते हैं और दूसरी ओर मिनिस्टरों की तनख्वाह बढ़ाई जाती है ! यह राजस्थान के लिये कोई सराहनीय बात नहीं है। मैं आप से यह कहूँगा कि अभी मिनिस्टर बनने के लिये यह होड़ चल रही है। पार्टी में वही काम हो जाते हैं जिनको देख कर पब्लिक अब तक हैरान है कि दर असल मौजूदा सरकार है वह चल भी सकेगी या नहीं। आज यह एक बहुत बड़ी प्रोब्लम है। आप किस प्रकार से घाटे को पूरा कर सकेंगे ? मैं यह कहूंगा कि अगर आप मिनिस्टरों की तनख्वाह कम कर देते या बन्द कर देते तो यह आपकी समस्या हल हो जाती और घाटे की भी कुछ पूर्ति हो जाती।

अन्त में मैं मुख्य मंत्री का ध्यान उन कार्यों की तरफ दिलाना चाहता हूं जिनका उन्होंने उदयपुर और नाथद्वारा में जगह जगह उद्घाटन किया। जब मैंने बजट देखा तो मुझे दुःख हुआ कि उसके लिये कोई खास तौर से ध्यान दिया गया हो, यह बात नहीं मुख्य मंत्री ने कहा कि मैंने कोई चुनाव स्टंट के लिये काम नहीं किया। लेकिन बजट देखने से मालूम होता है कि उन कार्यों के लिये कोई प्रावधान नहीं। उन कार्यों के लिये कोई न कोई प्रावधान होता जिनको उन्होंने चुनाव के दौरान में सहर्ष किया था। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं यह निवेदन करूंगा कि आयन्दा जो चुनावों में स्टन्ट होगा वह फैल होगा। मेरे ख्याल में १३ में से ८ और आयन्दा ऐसा न हो कि अगले चुनावों में कहीं जनता गायब न कर दे और एक भी सदस्य आपकी तरफ का न मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।

अंत में मैं यह अर्ज करूं कि खास महत्वपूर्ण तथ्यों को छोड़ दिया गया है। उनको हमारे वित्त मंत्री महोदय ने नहीं टटोला। इसलिये जो सुझाव माननीय ज्वालाप्रसादजी, या कांकरोली से आनेवाले सदस्य और उधर से भी जो जो सुझाव दिये गये हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जावे।

श्री फूलचन्द (सुजानगढ़) : सभापति महोदय, बजट पर हम यहां बहस कर रहे हैं और माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं और मैं भी इस पर अपने विचार रख रहा हूँ। विकास के बारे में मैं खास तौर से बोलना चाहूंगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष इस समय चल रहा है और विकास के लिये इस बजट में जो हमारे वित्त मंत्री ने अपने भाषण में जिक्र

(श्री फूलचन्द)

किया है कि विकास के लिये टैक्स लगाने की आवश्यकता महसूस हुई है। वैसे देखा जावे तो यह बात सही है कि विकास के लिये खर्चे की आवश्यकता रहती है और उसकी पूर्ति किसी न किसी रूप में करनी होती है। इसलिये टैक्सेज़ लगाया जाना जरूरी होता है और सरकार को लगाना आवश्यक होता है। लेकिन मैंने देखा है, माननीय सदस्यों में से चाहे किसी भी पक्ष के हों सब ने किसी न किसी रूप में इसका विरोध किया है और उन्होंने यह बताया है कि आज राजस्थान की जनता इन टैक्सों को वहन करने की स्थिति में नहीं है। मैं भी बहुत कुछ इसी पक्ष में हूँ कि जिन परिस्थितियों में और जिन कारणों से टैक्स लगाने की बात कही है वह समझ में नहीं आती। इसका कारण बहुत साफ है कि आज विकास के लिये जो खर्च हो रहा है मैं समझता हूँ, हम सब जानते हैं कि इसके प्रति जनता में और हम सब में काफी असन्तोष है। विकास के लिये जो पैसा खर्च किया जाता है वह पूरी तरह से उसके उपयोग में नहीं आता है और उसका काफी अंश बेकार चला जाता है। इसी तरह से और भी जो खर्चे के मद हैं उनमें भी जिस तरह से मितव्ययता बर्ती जानी चाहिये नहीं बर्ती जाती है और इससे आज आम जनता में यह भावना बनती जा रही है कि जो कर लगाये जा रहे हैं वे कर और उससे वसूल होने वाले रुपयों का सही रूप में उपयोग नहीं होता है और इसी कारण से इसका विरोध होता है और हम लोग कुछ अंश में इस बात का विरोध करते हैं कि टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिये। इसके साथ साथ मैं यह भी मानता हूँ कि जब सभी लोग चाहते हैं कि विकास होना चाहिये और योजना के द्वारा विकास होना चाहिये और इस सूरत में भी आप करों की मांग करते हैं और हम विरोध करते हैं तो इसकी गहराई में जाने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि अगर हम इसकी गहराई में जावें तो काफी सदस्य ऐसे हो सकते हैं जो करों के लगाने का विरोध न करें।

प्रश्न यह है कि जो फिजूल खर्चा हो रहा है वह बन्द किया जावे और इसके साथ साथ में मितव्ययता काम में ली जावे और जनता में यह विश्वास दिलाया जावे कि जो रुपया टैक्स के रूप में सरकार द्वारा वसूल किया जाता है वह ठीक तरह से खर्च होता है। मैं विश्वास करता हूँ कि दूसरे आम चुनाव के बाद तीसरे आम चुनावों में पांच वर्षों के लिए हम यहां पर उपस्थित हुए हैं और मैं यह समझता हूँ कि पब्लिक भी हमसे आशा रखती है कि दो चुनावों के बाद में तीसरे चुनाव में हमने जिन लोगों को मत दिया है वे लोग वहां जाकर आगे के पांच वर्षों के लिए कोई नई दिशा बतावेंगे। यह पहला वर्ष है जब हम सदन में बजट पर अपने विचार रख रहे हैं। सही बात तो यह होती कि जैसी नई आशाएं पब्लिक ने हम से पांच वर्षों में की है वैसी नई आशा की किरण हम पेश करते। मैं समझता हूं कि इस बजट भाषण में कोई ऐसी नई आशा की किरण नहीं है जिसके कारण करों को लगाने की आवश्यकता हुई।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि योजना में बांध बनाने के लिये करोड़ों की राशि खर्च की जा रही है।

Page No 76

(श्री फूलचन्द)

दूसरी योजना द्वारा बिजली और पानी की सहूलियतें दिलाना चाहते हैं। इतना अर्सा गुजरा इसके बावजूद भी आज हम देखते हैं कि बिजली पर टैक्स बढ़ता है। जब बिजली पर टैक्स बढ़ता है तो फिर बिजली पर टैक्स कम करने की बात कब आवेगी ? जितना पैसा पर-युनिट अभी है वही आप रहने दें तो बाद में उसके कम होने की स्थिति हो सकती है। लेकिन आप बढ़ाते हैं तो कम होने की स्थिति अभी नहीं आई है। मैं अपनी राय के अनुसार इसका विरोध करता हूँ कि बिजली पर टैक्स नहीं बढ़ाया जाय इस संबंध में इस सदन के माननीय सदस्य अपने विचार रख चुके हैं इसलिये इस समय मैं सदन का समय इस सम्बन्ध में अधिक नहीं लेना चाहता कि टैक्स क्यों नहीं लगाया जाय; पर मैं विरोध कर देना चाहता हूं कि यात्री-कर नहीं लगाना चाहिये। साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि पशुओं पर जो कर लगाया है वह भी नहीं लगाना चाहिये।

आबकारी कर की तरफ मैं देखता हूं और मैं सोचता हूं कि देशी शराब पर टैक्स लगाने की बात बजट में कही गई है पर विदेशी शराब पर टैक्स लगाने की बात इस बजट में नहीं कही गई है। मैं सोचता हूँ, बजट बनाने-वाले वे अफसर हो सकते हैं जो देशी शराब उपयोग में नहीं लाते, विदेशी शराब का उप-योग करते हों। इसलिए शायद उन्होंने सोचा है कि देशी शराब पर टैक्स बढ़ा दिया जाय और विदेशी शराब पर टैक्स नहीं लगाया जाय। मैं इसका विरोध करता हूँ और यह राय व्यक्त करना चाहता हूँ कि यदि टैक्स लगाने की आवश्यकता है तो इसका अधिक अंश विदेशी शराब पर होना चाहिये।

चने और दाल पर टैक्स लगाया गया है, इसका मैं विरोध करता हूँ और यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये नये नये टैक्स लगा कर जनता को परेशानी में, जंजाल में डालते हैं, इससे लोग परेशान होते हैं। दूसरे अनाजों को छोड़ दिया गया है और चने और दाल पर टैक्स लगाया है। मैं इस टैक्स का विरोध करता हूँ।

अब प्रश्न यह आता है कि १ करोड़ २८ लाख की कमी है उस कमी को यदि टैक्स नहीं लगायें तो किस तरह से पूरा किया जा सकता है ? और कई साधन हैं जिनसे इस कमी को पूरा किया जा सकता है। मैं लम्बी चौड़ी बहस में नहीं जाकर यही कहना उचित समझता हूँ कि जैसे सेल्स टैक्स है इसमें कर वसूली से ६६ लाख का लाभ दिखाया है। इन करों की वसूली के लिये अलग२ मशीनरी लगाई जाती है, सेल्स टैक्स सेल्स टैक्स डिपा-र्टमेंट वसूल करेगा, अमूक कर अमुक डिपार्टमेंट वसूल करेगा और इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में इतना खर्चा बढ़ा दिया है कि जो कुछ इस तरह से वसूल किया जाता है वह सब प्रशासन में ही खर्च हो जाता है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता। एडमिनिस्ट्रेशन पर इतना अधिक खर्चा बढ़ा दिया है कि वहां बाबू लोगों से पूछते हैं कि क्या काम है तो वे हाथ पर हाथ धरे रहते हैं। तो इस तरह उधर विकास के नाम पर, विकास के लिये जनता पर टैक्स लगायें और उधर उन टैक्सेज़ की वसूली के लिये मशीनरी बनाई जाती है उस मशीनरी पर इतना अधिक खर्च कर

(श्री फूलचन्द)

दिया जाता है कि इस तरह टैक्स से वसूल किया हुआ पैसा प्रशासन पर ही खर्च हो जाता है। विकास के लिये जो पैसा वसूल किया गया और जो विकास पर खर्च किया जाना चाहिये वह पैसा मशीनरी पर खर्च हो जाता है। तो आज के इस क्रिटिकल टाइम में जिसमें से कि हम गुजर रहे हैं क्यों नहीं सरकार की जो मशिनरी है उसी को सरकार कहे कि और अधिक काम करे ? जिस प्रकार जनता पर करों का भार डाला जा रहा है उसी तरह प्रशासनिक ढांचे में इस तरह के परिवर्तन किये जायें कि खर्चा कम हो जाय, सरकार की जो मौजूदा मशीनरी है उस ही को कहा जाय कि ज्यादा से ज्यादा काम करे। नई मशीनरी पर खर्चा नहीं किया जाय। यह लम्बी-चौड़ी मशीनरी बना कर जो लोगों को उलझन में डाला जा रहा है वह उलझन भी मिट जायेगी और सरकारी कर्मचारियों की कार्य-क्षमता भी बढ़ जायेगी; जनता पर करों का भार भी नहीं बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से इस बजट में नये टैक्स लगा कर लोगों पर बोझा डालने का रखा गया है वह काम किया जा सकता है।

दूसरे मैं यह महसूस करता हूं कि टैक्सेज़ जिस हद तक वसूल होने चाहिये उस हद तक जो पहले से लगे हुए टैक्स हैं उनकी वसूली नहीं होती है। अगर हम अपने प्रशासनिक ढांचे को इतना मजबूत करें कि मौजूदा टैक्सेज़ से जितनी आमदनी हमें हो सकती है उसकी पूरी तरह से वसूली कर सकें तो हमें और टैक्सेज़ वसूल करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टैक्सेज़ की चोरियां सरकारी अफसरों की गलती के कारण होती हैं। इस पर भी यदि सरकार ध्यान दे तो दूसरे नये टैक्स लगाने की नौबत नहीं आयेगी।

इसी तरह जब खास तौर से विकास के लिये टैक्स लगाने की आवश्यकता महसूस की जाती है तो यह देखना चाहिये कि हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि डेवलपमेंट के लिये हमें काफी कुर्बानी और त्याग करने की आवश्यकता है। तो इसके लिये मेरा सुझाव है कि मन्त्री-गण और सरकारी अधिकारियों को जो टी. ए. डी.ए. मिलता है उसमें से वास्तवमें जो उनका खर्चा हुआ है उसको छोड़ कर जो उनकी जेब में रहता है उस पैसे को उन्हें गवर्नमेंट को सरेन्डर कर देना चाहिये। अगर ऐसा किया जाय तो इससे काफी लाभ हो सकता है। आम लोगों के दिलों में भी अच्छी भावना इससे पैदा होती है और हमको भी राहत मिलती है।

और भी कई ऐसे सुझाव हो सकते हैं। १ करोड़ २८ लाख का सवाल है। कोई बड़ी रकम नहीं, कुछ टैक्सेज़ को हटायें, कुछ प्रशासनिक खर्चे को कम करें, विदेशी शराब पर टैक्स लगायें, मैं यह नहीं कहता कि देशी शराब पर टैक्स नहीं लगायें, देशी शराब को भी नहीं छोड़ें और नये तरीकों से जनता पर बोझा डाल रहे हैं वह नहीं डालें और किसी तरह मितव्ययता से इसकी पूर्ति कर सकते हैं। अगर इस तरह करें तो इससे जनता में संतोष पैदा होगा और जनता में संतोष पैदा करके एक करोड़ ही नहीं, ५ करोड़ के भी टैक्स लगायें तो जनता को इसमें दिक्कत नजर नहीं आयेगी।

उस पक्ष के माननीय सदस्य सोच सकते

(श्री फूलचन्द)

हैं और कभी कभी अपने भाषणों में कहते हैं कि सत्तारूढ़ पक्ष की तरफ से करों का विरोध किया जाता है और सरकार का विरोध कई प्रकार से किया जाता है। मैं मानता हूं कि सदन के अन्दर सत्तारूढ़ पक्ष हो, चाहे विरोधी पक्ष हो वास्तविकता सदन में रखनी चाहिये और जो बहस धन्यवाद के प्रस्ताव के दौरान में और बजट में चल रही है उससे इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारे विरोधी पक्ष के सदस्यों को भी काफी सोचना चाहिये कि किस प्रकार से करों का विरोध करते हैं और यह साबित करना चाहते हैं कि जनता को राहत दिलाने के लिये करों का विरोध करते हैं और दिखाना चाहते हैं कि अमुक गड़बड़ियां हो रही हैं, उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं महसूस करता हूं कि सिर्फ भाषणों से सुधार नहीं हो सकता।

कई अजीब स्थितियां हमारे सामने आती हैं जिनसे हम अन्दाज लगा सकते हैं। धन्यवाद के प्रस्ताव पर बहस हुई, ज्यादा बहस चुनावों पर जो कि अभी अभी हम लड़ कर आये हैं उन पर हुई। सत्तारूढ़ दल की तरफ से चुनाव की बात कही जाती है तो कहते हैं कि यह प्रासंगिक नहीं है। खुद बोलने खड़े हुए तो शुरू से अन्त तक चुनावों की बात कह डालते हैं। इसको महसूस नहीं करते कि अभी दो मिनट पहले अपने माननीय साथी को मना किया वही वे कर रहे हैं।

(४ म. प.)

इस तरह से मैं आपसे निवेदन करूं कि स्वतन्त्र पार्टी के हमारे जो सम्माननीय साथी हैं उनको इस बात का कभी कभी अफसोस हुआ करता है कि हमको आज भी राजे-महाराजे और जागीरदारों के नाम से पुकारा जाता है या सम्बोधित किया जाता है। जब हम जनतन्त्रीय पद्धति के आधार पर उसी प्रकार से चुन कर आते हैं जिस प्रकार से दूसरे सम्माननीय सदस्य चुन कर आते हैं तो फिर हमें विशेष प्रकार से क्यों सम्बोधित किया जाता है ? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सम्बोधन अपने आप नहीं किया जाता है। यह बात अपने दिल और दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि उनको इन्टेन्शनली सम्बोधित किया जाता है, किन्तु उनके स्वयं के ही ऐसे एक्शन्स होते हैं जिससे उनको सम्बोधित इस प्रकार से किया जाता है। आज भी महारावल साहब डूंगरपुर अपने आपको महारावल डूंगरपुर लिखते हैं, लक्ष्मणसिंहजी नहीं लिखते हैं, इसी तरह से महाराजा मानसिंहजी अपने आपको महाराजा मानसिंह लिखते हैं, मानसिंह नहीं लिखते हैं। राजा-महाराजा अपने नाम के आगे लगाये रहें और दूसरे सदस्य जिस प्रकार से चुन कर आये हैं उसी प्रकार से वे आये हैं तो फिर यह बात आप स्वयं ही महसूस कराइये ताकि लोग इसप्रकार न सोच सकें। आपके एक्शन्स इस प्रकार के होने चाहिये जिससे यह समझा जा सके कि जमाना अब बदल चुका है। इसी सिलसिले में मैं अर्ज करूं कि चुनाव के दौरान में जो बातें घटी हैं, जनसंघ के भाइयों ने सरकार को सम्बोधित करके कहा। कहीं समाजवाद की बात कही जाती है, कहीं सिद्धान्त की बात कही जाती है; लेकिन होना यह चाहिए कि नीति और सिद्धान्त के साथ उस बात को करना भी चाहिये। मुझे यह बताइये कि चुनाव में यह बात किस प्रकार कही गई कि कांग्रेसी को वोट

(श्री फूलचन्द)

देना गाय को काटना है; मतलब यह हुआ कि कांग्रेसी को एक वोट देना और एक गाय को काटना है, एक कांग्रेसी को वोट दिया तो एक गाय को काट दिया। जिस राजस्थान में गाय काटने का सवाल नहीं है, जहां गाय काटना पहले से ही बन्द है लेकिन जब विधान सभा के सदस्यों के चुनाव का सवाल आता है तो जनसंघ के भाई यह प्रचार करते हैं कि एक कांग्रेसी को वोट देना एक गाय को काटना है। फिर यह कहा जाता है कि यह प्रश्न लोक सभा से सम्बन्धित है। फिर यह प्रश्न ही क्यों यहां उठाया जाता है ? क्योंकि जब भी और जहां भी राजस्थान का सवाल आता है वहां पर गो-हत्या का प्रश्न ही नहीं उठता है। यह स्थिति जब आवेगी कि जब हम स्वयं कहते हैं तो वे स्वयं करते हैं या नहीं। आलोचना कितनी भी इस तरह से करें उससे प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। विरोधी पक्ष से मैं निवेदन करूंगा कि उन पर एक विशेष जिम्मेदारी है। वे जो आलोचना करते हैं तो वे किस प्रकार की आलोचना करते हैं उससे अन्दाज लगाया जा सकता है कि उनकी बातों में कितना वजन है।

सहकारी खेती के बारे में विरोध किया गया और जब उनसे डिटेल में पूछा गया तो यह कहा गया कि हम उसके विरोध में नहीं हैं यदि सेवा सहकारी समिति को प्रोत्साहन देकर स्वेच्छा से सहकारीखेती लागू होती है। सहकारी खेती लागू करने वालों ने स्वयं ही यह बात कही है कि हम इस सम्बन्ध में शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहते। सहकारी खेती के पक्ष में जो लोग हैं वे यह बात कहते हैं, कानून भी बना है वह यही है तो फिर विरोध किस बात का ? राष्ट्रीयकरण की बात आती है तो उसका विरोध करते हैं। बसों का नेशनलाइज़ेशन हुआ तो उसका विरोध करते हैं और कई बारे में कई मिसालें देकर लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का भी विरोध करते हैं। सदन में चल रही बहस में जो बातें आई हैं मैं उस नतीजे पर पहुंचा हूं कि लोगों के अन्दर जो भावना है उसको छूने के लिए विरोध किया जाता है। जो काम शासन की ओर से हुए हैं उनमें गल्तियां हो सकती हैं; अच्छाइयां भी हो सकती हैं। कानून के द्वारा हम सदन में उसको मंजूर कर लेते हैं। हमें तो जो गल्तियां हैं उनको सुधार करके जो अच्छाइयां हैं उनको समझ कर अपनाना चाहिये और उन अच्छाइयों का भी यदि विरोध करते हैं तो यह अजीब सी बात है जो कि समझ में आने वाली नहीं है। मैं खास तौर पर विरोधी पक्ष से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी बातों को वे सदन के सामने रखें जिससे हमारी समझ में आये कि उनका यह बुनियादी पहलू है; उनको गलतफहमी है।

इसके बाद मैं एक बात और निवेदन करना चाहूँगा जो मुझे वित्त मंत्री महोदय के भाषण में अखर रही है और वह यह है कि उन्होंने पेज १६ पर नीचे जाकर नौजवानों के बारे में लिखा है कि नौजवानों में काफी बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। जो शब्द उन्होंने काम लिये हैं वे ये हैं :-"ये लोग सरकारी या निजी सेवाओं में आरामदेह नौकरियों की तलाश में दौड़ रहे हैं"। इसका मतलब यह लगाया जाय कि सरकारी सेवायें हैं वे आरामदेह हैं जो मेहनत नहीं कर सकते हैं; यह इसमें

(श्री फूलचन्द)

लिखा हुआ है। मैं इस भाषण के इन शब्दों पर सख्त नाराजगी प्रगट करता हूँ क्योंकि यदि नौजवानों पर कोई जिम्मेदारी भी डालते हैं तो वह बुजुर्गों के अधीन ही डालनी चाहिये क्योंकि सरकारी ऑफिसेज़ में जहां नौजवान काम करते हैं तो वे बुजुर्ग आदमियों के नीचे ही रह कर काम करते हैं। यदि बुजुर्ग एक्टिव होकर काम कर सकते हैं तो नौजवान भी एक्टिव होकर काम कर सकते हैं। एजुकेशन के द्वारा बुराइयां आई हैं तो जो प्रोफेसर्स या लेक्चरार्स हैं वे या तो ठीक नहीं हैं या यदि अच्छे हैं और नौजवानों को ठीक तरह से एजुकेशन मिल रही है जैसा डिग्रियों के बारे में कहा गया तो वह गलत है और इस प्रकार के सम्बोधन से नौजवानों में हम कोई उत्साह का संचार नहीं करने जा रहे हैं। मैं निवेदन करूं कि काफी अर्से से राजस्थान के अन्दर इस बात का प्रयत्न किया जा रहा था कि राजस्थान के फ्युचर के लिए यदि हम कल्पना करते हैं तो नौजवानों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास सही तरीके से हो उस ओर गम्भीरता से ध्यान देना चाहिये; यूथ वैलफेयर प्रोग्राम्स हमारी स्टेट की ओर से निकलने चाहिये। उस सम्बन्ध में अब तक कोई ठोस कदम सरकार की ओर से नहीं उठाया गया है। जब जब इस प्रकार का प्रश्न आया तो यह कहा गया कि स्पोर्टस कौंसिल नौजवानों में काम करती है। मैं निवेदन करूं कि जिन नौजवानों के बारे में इस भाषण में सम्बोधन किया गया है और यदि उसमें कुछ सही हो सकता है तो वह आपकी इन एक्टिविटीज़ के कारण ही। स्पोर्ट्स कौंसिल में आप हजारों रुपया खर्च करते हैं और वहां होता क्या है यह आप और हम सब जानते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम कौनसा पसन्द करते हैं, उनका असर किस प्रकार से पड़ेगा और जहां कहीं अवसर आता है तो भाषणों में कहते हैं कि इस तरीके के सांस्कृतिक प्रोग्रामों से हमारे नौजवानों में बदचलनी फैल रही है। ऐसी अजीब स्थितियां हैं जिनके दोहराने की आवश्यकता नहीं है। कहां पर वाजिब खर्चा हो रहा है, कहां पर नहीं; यह देखने की बात है। बुजुर्गों की यह फेशन हो गई है कि किसी कॉलेज में जाकर नौजवानों को खरी-खोटी सुना आये; किसी इन्स्टीट्यूशन में भाषण देने का मौका आया वहां भी दो-चार खरी खोटी सुना दी। बजट का सवाल आया इसमें दो-चार बातें नौजवानों के लिये लिख डालीं। लेकिन यदि नौजवानों के हित की कोई बात आती है तो बुजुर्ग भी कहने लग जाते हैं कि हम भी नौजवान हैं। मैं इस बात को निश्चित समझता हूँ कि हम फ्यूचर जेनरेशन के बारे में कोई भी बात कहें इतनी बात जरूर सोचें, इसका रिफ्लेक्शन उन पर कैसा पड़ेगा। जो कुछ वाजिब हो कहना चाहिये। वह किसी हद तक सही भी है। इस हिसाब से सोचना-समझना चाहिये और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में इस बात पर पूरा ध्यान दिया जावेगा।

अन्त में सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि टैक्सेज़ के बारे में माननीय सदस्यों ने जो भी सुझाव दिये हैं उनमें कमी की जा सकती है तो कमी अवश्य की जानी चाहिये। उस कमी की पूर्ति के लिये प्रशासनिक मितव्ययता हमें अपनानी चाहिये। उसमें किसी प्रकार से कमी करने की गुंजाइश हो तो सबसे पहले प्रशासनिक

(श्री फूलचन्द)

व्यय में कमी की जानी चाहिये। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो असन्तोष जनता में फैला हुआ है वह है हमारे प्रशासनिक ढांचे के कारण। हमारा प्रशासनिक ढांचा बहुत बिगड़ा हुआ है। इसके कारण हमारे विकास के नहीं कामहो रहे हैं वे सही नहीं हो रहे हैं। जो कुछ भी हमारी सरकार राजस्थान के विकास के लिये कर रही है वह बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। उसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जनता को सोचने-समझने की शक्ति मिली है, विकास के करने की गुंजाइश दी है। जिस जिस तरह से हमारे सोचने-समझने के तरीके में डेवलपमेन्ट होगा उसी तरह से अगर हमारे डेवलपमेन्ट में किसी प्रकार की कमी नजर आयेगी तो जनता उसके लिये असन्तोष व्यक्त करेगी। इस तरह से जो भी चीजें हमारे सामने आयें उनको सोच समझ कर दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये। जो लोगों के अन्दर प्रशासनिक ढांचे के प्रति बुराई और असन्तोष फैला हुआ है उसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, यह सोचते हुए हम जनता को किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं विकास के लिये वह स्वेच्छा से राशि देने की सहमति प्रदान करें।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सभापति महोदय, सदन के समक्ष जितने भी भाषण बजट पर हुए हैं उनमें एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि 'हां' पक्ष के लोगों ने भी नये टैक्सेशन के प्रोपोज़ल्स का विरोध किया है और 'ना' पक्ष के लोगों ने तो इन प्रस्तावों का एक स्वर से विरोध किया है। चूंकि हमारे देश में जनतन्त्र है, हम लोग जनतन्त्र द्वारा चुन कर आये हैं मेरा विश्वास है कि अगर 'हां' पक्ष वाले लोग पार्टी व्हिप का इस्तेमाल न करें तो नये टैक्स के जो प्रपोज़ल्स हैं वे सारे के सारे गिरने वाले हैं। मैं माननीय वित्त मन्त्रीजी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस पार्टी की तरफ से उन्होंने टैक्स के प्रोपोज़ल्स रखे हैं उस पार्टी के काफी माननीय सदस्यों ने उन टैक्सेज़ का विरोध किया है; इसलिये उनको खुद को इस पर पुनर्विचार करना चाहिये। जनतन्त्र का यदि कुछ मतलब है तो। कांग्रेस पार्टी जिस जनतन्त्र का दावा करती है अगर वह देखे तो ८७ आदमी इस राय के हैं ही कि इस प्रकार के टैक्सेज़ नहीं लगने चाहिये। इसके अलावा उनकी खुद की पार्टी के लोग भी इन टैक्स प्रोपोज़ल्स के खिलाफ हैं। इस लिये हमारी सरकार से मांग है कि टैक्स प्रोपोज़ल्स को रद्द कर दिया जाना चाहिये।

आज हमारे वित्त मन्त्री पूछ सकते हैं कि आखिर १.२७ लाख का जो घाटा है उसके लिये क्या किया जाय? मैं उनसे निवेदनकरना चाहता हूँ, बम्बई स्टेट में भी हमारे वित्त मंत्री की तरह एक नये वित्त मन्त्री महोदय ने आसन ग्रहण किया है उनको भी आप जितना ही थोड़ा समय बजट प्रस्तुत करने को मिला है। उन्होंने किसी प्रकार के टैक्स प्रोपोज़ल्स फ्रेम न कर १.६७ लाख का डेफिसिट बजट बम्बई विधान सभा के समक्ष रखा है और उसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जब समय मिलेगा तब हम नये टैक्स के प्रोपोज़ल्स पर विचार करके सदन के समक्ष रखेंगे। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप भी इस समय १.२७ लाख का डेफिसिट बजट रख देते तो विरोधीदल को किसी प्रकार का दुख नहीं होता;

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

विरोधी दल द्वारा आलोचना नहीं होती। मैं विरोधी दल की तरफ से एक सुझाव देना चाहता हूं। पिछले वर्ष के लिये सप्लीमन्ट्री ग्रान्ट्स हमारे से ली गई थीं तीन, चार रोज पहले उसमें यह कहा गया था कि ८३ लाख की कमी हम प्रशासनिक मद में करेंगे, लेकिन वह कमी नहीं हो सकी। उसमें से करीब ४४ लाख रुपया पुलिस के रिऑर्गेनाइज़ेशन के वक्त कमी करने का सोचा था। लेकिन वह भी कमी नहीं कर सके चुनावों के कारण।

आप प्रशासनिक ढांचे में इतनी कमी कर लीजिए जिससे आप १.२७ लाख की बचत कर सकते हैं। वैसी हालत में यह जो १.२७ लाख के टैक्स के प्रोपोज़ल्स रखे हैं वे रखने नहीं पड़ते। वित्त मंत्री महोदय ने अपने इस बजट में ५० लाख की कमी करने का विवरण दिया है। इस बारे में कहा गया है कि हम ५० लाख की कमी की पूर्ति के लिए प्रशासनिक व्यय में कमी करने का प्रयत्न करेंगे, उसके लिए कमर कसेंगे लेकिन यह ५० लाख की भी कमी कर पायेंगे यह संभव दिखाई नहीं देता। इसके लिए मेरा निवेदन है कि इस पचास लाख की कमी की पूर्ति के लिए सरकार की अपनी जो ब्यूरोक्रेसी है, सेक्रेटेरिएट है उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको स्पेशल पे दी जाती है; उन अधिकारियों से जिनको स्पेशल पे मिलती है उनसे कहा जाय कि हमारे ६२-६३ के बजट में घाटा है इसलिए आप अपने आप स्पेशल पे में कटौती कर दीजिए ताकि हमारे बजट में जो घाटा है उसकी पूर्ति हो सके और आइन्दा साल में हमारा बेलेन्सिंग बजट हो इसके लिए सरकार को मदद दें। लेकिन मेरा ख्याल है आप ब्यूरोक्रेसी का टेस्ट नहीं लेना चाहते, सरकार को ब्यूरोक्रेसी पर भरोसा नहीं; इसलिए वह उनके खर्च में किसी प्रकार की कमी करने को तैयार नहीं होगी। उस घाटे की पूर्ति के लिए नये नये टैक्स प्रोपोज़ल्स रखे जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि हमारे सामने तीसरी योजना को पूरा करने का प्रश्न है। अगर नये टैक्स नहीं लगाते हैं तो तीसरी योजना किस प्रकार पूरी हो सकेगी? पिछले वर्ष १.३५ लाख का घाटा टैक्स लगाकर पूरा किया। इस साल १.२८ लाख का घाटा पूरा कर रहे हैं टैक्स लगा कर। इस तरह से इन दो सालों में २ करोड़, ६३ लाख रुपये के हम टैक्स लगा चुके हैं और इस तरह से आपका कहना है कि हमें टैक्स से २० करोड़ रुपया वसूल करना है। आने वाले तीन सालों में १७ करोड़ और कुछ लाख रुपये के टैक्स लगाने पड़ेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जनता की इतनी शक्ति कहां है कि २७ करोड़ रुपये के नये टैक्सेज़ के बोझ को वह सहन कर सके ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : असंभव है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : असंभव तो है, लेकिन हमारी सरकार इस पर डटी हुई है कि वह १७ करोड़ रुपया आने वाले तीन सालों में जनता से टैक्स के रूप में वसूल करे।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : आपने जो टैक्सेज़ के बारे में बताया है वह इस तरह से नहीं है। हमने गत साल जो १.३८ लाख के टैक्स लगाये वे पांच साल तक

Page No 83

(श्री नाथूराम मिर्धा)

चलेंगे। उससे ७॥ करोड़ रुपया और इस साल १.२८ लाख के टैक्स लगाये हैं वे चार साल तक चलेंगे। इस तरह से ६ करोड़ रुपया है इस तरह से कुल मिला कर २० करोड़ रुपया ही नहीं करना है; बल्कि ३२ करोड़ करना है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अगर आपकी सरकार इस बात के लिए तैयार है तो विरोधी दल इस बात का विरोध करेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : हमको तो ३२ करोड़ रुपया पूरा करना है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस लिए हम विरोध करते हैं ३२ करोड़ रुपये के टैक्स का। आज गरीब जनता इस प्रकार के टैक्सेज़ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। इसके बारे में मैथेमेटिकली मैं बाद में निवेदन करूंगा।

सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय समझाने की बात करते हैं। अगर वे समझना या समझाना चाहें तो लॉबीज़ में चले जायं। वहां बड़ी सुविधा होगी। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं, चाहे आप २० करोड़ रुपया वसूल करें या ३२ करोड़ रुपया, लेकिन राजस्थान की जनता अब इन टैक्सेज़ को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फिर; जिस तरीके का टैक्स गढ़ा है वह गढ़ा है इन्-डाइरेक्ट। इस टैक्स से आम जनता की कमर टूटती है। सोशलिस्ट विचार-धारा के आधार पर मैं अर्ज करूं कि यह इनडाइरेक्ट टैक्स गरीब को और गरीब बना रहा है और अमीर को और अमीर बनाने की ओर ले जा रहा है। आपके बजट को हां, पक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा कि यह डॉकूमेन्ट ऑफ डेवलपमेन्ट होना चाहिये। पर यह डॉकूमेन्ट ऑफ डेवलपमेन्ट नहीं है। डॉकूमेन्ट ऑफ ओप्रेशन है जो इस टैक्स के द्वारा गरीब जनता पर लादा गया है और उनका शोषण करेगा। इसलिये मैं इसका शत प्रतिशत विरोध करता हूँ और कांग्रेस सरकार की अगर हिम्मत हो तो इन्हीं विषयों पर वह इन विचारों की पृष्ठभूमि में अपना स्पष्टीकरण दे। तो मेरी यह धारणा है कि ये टैक्स प्रोपोज़ल्स पास होने लायक नहीं हैं।

सरकार शराब पर टैक्स लगाये; पर यह डाइरेक्ट होना चाहिये। गरीब जनता पर प्रच्छन्न रूप से इसका भार नहीं पड़ना चाहिए।

आज जो हमारी वित्तीय स्थिति है, सरकार कहती है कि प्रति व्यक्ति हमारी राष्ट्रीय आय २३७)रु० से बढ़कर २४६) रु०हो गई है यानी ६) रुपया पांच साल में बढ़ा है। यह आपकी इस बजट स्टडी पुस्तिका में है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस सम्बन्ध में कि प्रति व्यक्ति जो आय बढ़ी है उसके मुकाबले में आप यह भी देखिये कि प्रति व्यक्ति टैक्स का भार कितना बढ़ा है? सन् ५५-५६ में यह टैक्स का भार जहां ६) रु० प्रति व्यक्ति था वहां ६२-६३ में १७) रु० हो गया; यानी प्रति व्यक्ति पहले से ८) रु० का टैक्स का वजन और बढ़ गया है और सरकार ने प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की है २३७)रु० से २४६) रु० यानी ६) रु० बढ़ी; तो ६) आपने बढ़ाये और उसमें से ८) रु० टैक्स भार की वृद्धि के रूप में सरकार ने

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

अपने खजाने में वापिस ले लिये । मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा मजाक समाजवाद का नाम लेकर जनता के साथ और कोई भी सरकार नहीं कर सकती, जितना इस राजस्थान की सरकार ने किया है । जो टैक्स की रेवेन्यू पहले सन् ५१-५२ में, दस साल पहले, ११ करोड़ थी, आज ३४ करोड़ हो गई है । इस टैक्स की रेवेन्यू से अगर आप देश की प्रगति को आंकना चाहते हैं तो यह नहीं आंकी जा सकती । इसके साथ यह भी देखना पड़ेगा कि प्रान्त में रहने वाली जनता की आर्थिक स्थिति भी कितनी बढ़ी है और इस बारे में गवर्नर महोदय ने कहा है ६)रु० प्रति व्यक्ति बढ़ी है । ये सरकार के आंकड़े हैं जो मैं उद्धृत कर रहा हूँ, मेरे अपने आंकड़े नहीं हैं । इन आंकड़ों को तो, मैं समझता हूँ, सरकार भी चुनौती नहीं देगी । तो ६)रु० बढ़ाकर आपने ८) रु० वापिस उनकी जेबों से निकाल लिए हैं । तो इसके लिये यह सरकार बधाई की पात्र नहीं हो सकती ।

श्री सभापति: I think per capita tax revenue is 14.62, not 17.

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह एक ही किताब से मैं और आप दोनों पढ़ रहे हैं । मैं दूसरे सफे से पढ़ रहा हूँ और आप पहले सफे से । मैं पेज सात से पढ़ रहा हूँ । मैंने पहले भी कहा था कि इस सरकार के आंकड़ों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता । आज आप जो फरमा रहे हैं उस पर से मेरी वह बात सही साबित हो रही है कि इस सरकार के सारे आंकड़े गलत हैं । हमारे प्रान्त का कुल कलेक्शन ३,४३१.५० लाख है और हमारे प्रान्त की कुल पापुलेशन दो करोड़ है, इससे साफ तौर से १७ पड़ता है । पर इसके पिछले आंकड़ों में जहां पर दूसरी स्टेटों के मुकाबले में स्टेटिस्टिक्स दिये गये हैं वहां पर आप फरमा रहे हैं वैसे दिया गया है । यह जो सरकार ने अपनी स्टेटिस्टिक्स की इन्स्टी-ट्यूट बना रखी है और जिस पर लाखों रुपया खर्च किया जाकर जिसे मेन्टेन किया जा रहा है मैं निवेदन करूं कि अगर वह इस तरह के आंकड़े ही तैयार करती है तो व्यर्थ है यह सारा खर्चा । ऐसा लगता है उसके पास काबिल आदमी नहीं हैं । अगर काबिल आदमी नहीं हैं तो उनको सरकार बदले और दूसरे काबिल आदमियों को अवसर दें, काबिल आदमियों की कमी नहीं है । इतना तो होना ही चाहिए कि एक ही डॉकूमेन्ट में इतना कॉन्ट्राडिक्शन आंकड़ों में तो नहीं दे और यह कॉन्ट्राडिक्शन है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर-कपिटा इन्कम में । तो दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों में तो न जाने कितने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटिस्टिक्स होंगे । मैं समझता हूं, जो भी मिनिस्टर-इनचार्ज इस विभाग के हों वे इसका जवाब देंगे । जब यह साफ मालूम है कि १७ है तो फिर क्यों १४) रु० और कुछ आने दिखाये गये हैं ?

तो सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हमारी आर्थिक स्थिति जिस प्रकार की है वह स्पष्ट है कि अच्छी नहीं है, बड़ी दयनीय है । फिर मैं और निवेदन करूं कि हमारे यहां लैंड रेवेन्यू सबसे ज्यादा है । मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने भी इस ओर सरकार का ध्यान दिलाया कि हमारे यहां प्रति व्यक्ति लैंड रेवेन्यू ४ रु० ५३ न. पै. प्रति

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

व्यक्ति वसूल की जाती है। अन्य किसी भी स्टेट में इतनी लैंड रेवेन्यू नहीं है; जब कि हमारे यहां काफी हिस्सा रेगिस्तानी है। इसे देखते हुए और हमारे यहां की परिस्थिति को देखते हुए, जमीन की पैदावार को मुकाबले में रखते हुए भी यह वसूली न्यायोचित नहीं कही जा सकती।

साथ ही मैंने एक्साइज़ के टैक्सेशन को देखा। यह भी सारे अन्य राज्यों के मुकाबले में ज्यादा है। तो सभी स्टेटों के मुकाबले में हम प्रगति पर मालूम पड़ते हैं इन मामलों में। पर पर-केपिटा इन्कम हमारी जो है उससे हम सब स्टेटों के मुकाबले में तेरहवें-चौदहवें नम्बर पर हैं। इस सबके बावजूद भी आज यह हुकूमत कहती है कि हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। मैं कहता हूँ, आपने प्रगति इन आंकड़ों में की है जिसके सही होने के बारे में अभी मैंने आपको स्टेटिस्टिक्स के आपके आंकड़ों से ही बताया। आम हालत तो आदमी की यहां गिर रही है।

मैं अब थोड़ा प्रशासन के बारे में और उसके खर्च के बारे में भी अर्ज कर दूं। ६० करोड़ की कुल आमदनी में से आप प्रशासन पर खर्च कर रहे हैं १४ करोड़ रुपया ८ करोड़ व कुछ लाख रुपये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर और पांच करोड़ और कुछ लाख रुपये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च किया जा रहा है। और प्रशासन का हाल यह है कि कागजों का पता ही नहीं लगता। एक कागज एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में तब तक नहीं जाता जब तक आदमी लगातार उसका पीछा न करे और कोशिश न करे उसको निकलवाने की। और मिनिस्टरों का हाल यह है कि वे नौकरशाही के हाथ की कठपुतली मात्र रह गये हैं। आज नौकरशाही उन पर इतनी हावी हो गई है कि मिनिस्टर चाहे कि कोई फाइल आज उसको मुहैया कर दी जावे तो मैं बड़े अदब से निवेदन करना चाहता हूँ सभापति महोदय, कि नौकरशाही उनको भी यही जवाब देती है कि अभी फाइल का पता नहीं है और तीन-तीन दिन तक फाइल का उनको इन्तजार करना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूं, जनतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के शासन में इस तरह की स्थिति अच्छी नहीं है, बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, इस स्थिति को हमें जनतन्त्र के हित में जल्दी से बदलना होगा और अगर इस स्थिति को जल्दी से यह हुकूमत बदलने में कामयाब नहीं होती है तो हमें इस हुकूमत को बदलना होगा और इसे राजस्थान की जनता बदल कर रहेगी।

रेशनलाइज़ेशन ऑफ पे स्केल्स की बात कही गई। मैं नहीं समझ पाया कि 'रेशनलाइज़ेशन' वर्ड का इस्तेमाल इस पे स्केल में किस कारण से इस सरकार ने किया है? कौनसी रेशनलाइज़ेशन की बात कही है? नीचे के लोगों की तनख्वाह वही ४५-१-७० है अब डीयरनैस अलाउन्स को पे में मिलाने के नाम पर क्या किया कि जो ग्रेड जहां जाकर समाप्त होता था बड़ी बड़ी नौकरी का वहां उनकी दरें बढ़ा दी। नीचे वालों का कुछ नहीं किया, बड़ों की दरें भी बढ़ा दी। ६००) रु. वालों को ११००) रुपये पर ले गये, २५) रुपया वार्षिक ग्रेड को ३०) रु. कर दिया और यह रेशनलाइज़ेशन ऑफ पे स्केल हो गया। इसके आधार पर आज की यह सरकार देश में और अपने राज्य में समाजवाद लाने की

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

बात कहती है ! कितनी विडम्बना है। जिस चपरासी को ७०)रु. मिलते हैं उसको उतने ही मिलेंगे, ग्रेड का उसका एक रुपया प्रति वर्ष है तो उसको वही एक रुपया मिलेगा। पर डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी को जो ग्रेड मिलता था वह बढ़ा दिया। सालाना इन्क्रीमेंट सौ से दो सौ कर दिया, २५) से ३०) कर दिया १००) से १५०) रु० कर दिया। इस तरह की बात को अव्यवस्था कहा जा सकता है, रेशनलाइज़ेशन तो कतई नहीं। आज भी ३००)रु. से नीचे के सरकारी कर्मचारी की हालत खराब है। ऊपर के जो कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत फायदा रेशनलाइज़ेशन के नाम पर लिया है। इसकी जांच की जानी चाहिये। इसके नाम पर, मंहगाई भत्ते को मिलाने के नाम पर ग्रेड़ें बढ़ाई हैं। पर इस सरकार को ये सारी बातें दिखती नहीं हैं। उनको शायद यह डर है कि चुनावों की सरगर्मी में राजस्थान असेम्बली में उनकी गिनती काफी कम हो गई है। अब अगर इस नौकरशाही को बिगाड़ दिया या नाराज कर दिया तो कहीं रही सही उनकी शान भी जाती न रहे।

तीसरी योजना की बात करते हैं। मैं एक मामूली सी बात पूछता हूँ। इस तीसरी योजना का प्रचार कौन करेगा ? सरकार जवाब देती है, हमारा यह जन-सम्पर्क विभाग करेगा और इसके संचालकजी किस तरह के व्यक्ति हैं, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। तीसरी योजना के प्रारूप की बात मेरे सामने आई। पर मालूम पड़ा कि यह प्रारूप छप कर राजस्थान में आज तक बिक नहीं सका है, बंट नहीं पाया है और हम तीसरी योजना के दूसरे साल में प्रवेश कर रहे हैं। मैंने कल टेलीफोन करवाया जन-संपर्क विभाग में यह जानने के लिए अपने एक मित्र के द्वारा कि तीसरी योजना का प्रारूप हमें कहां मिल सकेगा बाजार में, इसके बिना हमें जानकारी प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है। डिप्टी डाइरेक्टर, पब्लिक रिलेशन्स-महोदय ने जवाब दिया कि अभी तक तो छपा ही नहीं है यह प्रारूप; वह छपा ही नहीं तो बाजार में मिलेगा कहां से ? तो यह स्थिति है हमारे इस विभाग की ! इसके संचालक महोदय ऐसे हैं जिन पर चार्जशीट लगाई गई है, हिसाब में लाखों रुपयों के घोटाले करने के जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, जिन्होंने विज्ञापन की नीति में इस सरकार को बदनाम करने में कोई कसर नहीं उठा रखी है, इस बदनामी में शायद मिनिस्टर से भी ज्यादा जिम्मेदारी अगर किसी की रही है तो इनकी रही है। कई तरह के इन पर चार्ज लगाये गये हैं। होम मिनिस्टर साहब ने इन्क्वायरी कर ली, ऑडिट रिपोर्ट हो गई, सब कुछ हो गया, सबको मालूम हो गया कि ये किस तरह के हैं पर आज तक कोई इनको हटा नहीं सका। मैं कहना चाहता हूं कि वे होम मिनिस्टर तो गये जो इनकी रक्षा करना चाहते थे आज नये होम मिनिस्टर आये हैं। वे इनकी फाइलों की तरफ देखें, ऑडिट रिपोर्टों को पढ़ें और इसको इनकी बिना पर फौरन सस्पेन्ड करें, बाद में इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट की जावे कि कैसे इनके कारण लाखों रुपयों का नुकसान हुकूमत को हुआ है।

डिप्टी डाइरेक्टर टेम्पोरेरी तरीके से रखा गया था उसकी मार्फत लाखों रुपये खर्च कर दिये। प्रदर्शनियां लगाई गई और उनका लाखों रुपयों का हिसाब हमारी सरकार के पास नहीं।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

यह हमारे जनसम्पर्क विभाग का तरीका है। इसलिए मेरा कहना है कि जो इस प्रकार से प्रदर्शनियों आदि पर अनापशनाप खर्च किया जाता है उसको रोका जाना चाहिए। हिन्दुस्तान कॉन्फरेंस कमीशनने और राजस्थान की एडीटर्स कान्फ्रेंस ने सिफारिश की थी कि प्रचार विभाग अलग होना चाहिए और विज्ञापन विभाग अलग होना चाहिए ? लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। चाहे हिन्दुस्तान का प्रेस कमीशन कुछ भी कहता रहे, चाहे राजस्थान की एडीटर्स कॉन्फरेन्स कुछ भी कहती रहे लेकिन हमारे जन-सम्पर्क विभाग और राजस्थान सरकार को इसकी कोई चिन्ता नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि सारी गड़बड़ियों को और स्थिति को ठीक करना है तो हमें हमारे खर्चों में कमी करनी पड़ेगी, खर्चों में मितव्ययता लानी पड़ेगी और तभी हमारी पंचवर्षीय योजनायें सफल हो सकती हैं, अन्यथा सफल होने का अंदेशा नजर नहीं आता है।

जो हमारे सरकारी कर्मचारियों को रिक्रूट करने की मशीनरी है पब्लिक सर्विस कमीशन, अब मैं उसके बारे में बताऊं। इस विभाग का बजट १९६१-६२ में ८३,२६०' रुपये का था और वह ६७,६४० रिवाइज़ हो गया और १९६२-६३ में क्या हुआ ? जो प्रपोज़ल किया है हमारे वित्त मंत्री ने, ८३ हजार से एस्टीमेट आता है १ लाख ५४ हजार ८०० रुपया यानी दुगुने से थोड़ा सा कम यानी पौने दो गुना से भी ज्यादा। मिनिस्ट्रियल हैड में खर्च करने का यह प्रपोज़ल है और क्लास फोर एम्पलॉईज़ पर कितना खर्च करना चाहते हैं इस पब्लिक सर्विस कमीशन में, वह मैं आपको बताता हूं। पहले क्लास फोर एम्पलॉईज़ पर १० हजार रुपया खर्च किया और अब उसको देखते हैं तो २३,५२० रु० खर्च करना चाहते हैं। इसका मतलब है दो गुना से भी ज्यादा खर्चा हम क्लास फोर एम्प्लॉईज़ पर करने जा रहे हैं। फिर मैंने देखा कि इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसको डिटेल में देखा कि इस पब्लिक सर्विस कमीशन में कितने ऑफिसर्स हैं, तो मालूम हुआ कि ४ तो मेम्बर्स हैं, १ सेक्रेटरी हैं, १ अकाउन्टेन्ट है और बाकी दूसरे मिलाकर १० ऑफिसर्स बनते हैं। अब १० ऑफिसर्स के लिए चपरासियों का खर्चा डबल से भी ज्यादा कर दिया। मैं नहीं समझा कि यह किस तरह की बुद्धिमानी है और अगर इस प्रकार से खर्चा हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन में बढ़ता है तो यह और कुछ नहीं, बल्कि निकम्मेपन का सुबूत है। इस स्थिति को हमें जल्दी से जल्दी बदलना चाहिए, जब कि यह विभाग आज दिन तक डॉक्टरों को अपोंइन्ट नहीं कर सकता है, जब कि हमारे यहां डॉक्टरों की इतनी जरूरत है; यह मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। यही कारण है कि विभागों को टेम्पोरेरी अपोइन्टमेन्ट्स देने पड़ते हैं और जब तक उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन की कॉन्करेन्स नहीं मिलती तब तक सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिलती इसी कारण कई केसेज़ में ऐसा देखा गया है कि सरकारी गजटेड ऑफिसर्स को एक एक साल तक तनख्वाह नहीं मिलती और तनख्वाह के अभाव में वे किस प्रकार से अपना काम चलाते हैं ? ऐसी परिस्थिति में हम यह कैसे अन्दाजा लगा सकते हैं कि वे ईमानदारी से काम चलायेंगे ? मैं कहूंगा कि अगर सरकार यह सोचती है कि ऐसी परिस्थिति में सरकारी

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कर्मचारी ईमानदारी से काम चलावेंगे तो सरकार भ्रम में है। यह मैं सैकड़ों ऑफिसर्स के बारे में कह रहा हूँ कि पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कॉन्करेन्स नहीं पहुंचती और इस कारण उनको तनख्वाह तक नहीं मिलती। इसकी डिटेल्स यदि मंत्री महोदय चाहें तो दे सकता हूं और ऐसे सैकड़ों की तादाद में केसेज़ बता सकता हूँ और विभागों को कितने ही टेम्पोरेरी अपॉइन्टमेन्ट्स देने पड़े हैं। इस कारण उनको बहुत तकलीफ हो रही है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी नौकरशाही करप्ट न हो तो उनको समय पर तनख्वाह देने की जरूरत है और अगर हमारी सरकार सोचती है कि हमें तो करप्ट शासन ही चलाना है और इसी तरह काम करते रहना है तो ठीक है; फिर तो तनख्वाह लोगों को दो दो साल में दो। पर आप स्थिति को वास्तव में बदलना चाहते हैं तो आपको बड़ी गम्भीरता से पब्लिक सर्विस कमीशन की जो फंकशनिंग है उसको कन्ट्रोल करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि जो मिनिस्ट्रियल एक्सपेन्सेज़ के लिए प्रपोज़ल किया गया है उसका मैं विरोध करना चाहता हूँ और क्लास फोर एम्पलॉईज़ खर्चे को जो डबल कर दिया है उसको भी मैं ठीक नहीं समझता। आज आपने क्लास फोर एम्पलॉईज़ की जो स्थिति बना रखी है वह सभी लोग जानते हैं और उसको जल्दी से जल्दी बदलना चाहिए।

और चीजों के साथ साथ हमारे पुलिस डिपार्टमेन्ट का क्या हाल है? उसके ऊपर कुल ५ करोड़ का खर्चा किया जाता है। इसमें से १६ लाख रुपया क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेन्ट के लिए खर्च किया जाता है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इस विभाग पर इतना ज्यादा खर्च करने की क्या आवश्यकता है। बारवाड़ी में गोलियां चलती हैं, सरदारशहर में कत्ल होते हैं लेकिन हमारा क्रिमिनल इनवेस्टीगेशन डिपार्टमेन्ट उनकी एक रिपोर्ट सही नहीं भेजता। हमने कभी नहीं सुना कि क्रिमिनल इनवेस्टीगेशन डिपार्टमेन्ट की रिपोर्ट आने के आधार पर पुलिस विभाग के किसी कर्मचारी के ऊपर एक्शन ले लिया हो। यदि हमारा क्रिमिनल इनवेस्टीगेशन डिपार्टमेन्ट इतना निकम्मा है कि साल में मुश्किल से जो दस-बीस काण्ड होते हैं उनकी भी वह सही रूप से रिपोर्ट नहीं दे पाता तो फिर मैं कहूँगा कि इस डिपार्टमेन्ट को आप री-ऑर्गेनाइज़ कीजिए। अगर यही हालत है तो फिर इसको युटीलिटी क्या है? अगर इसकी कोई युटीलिटी नहीं है तो फिर आप इसको खत्म कर दीजिए। मैं माननीय गृह मन्त्रीजी से कहना चाहता हूँ, हालांकि वे अनुपस्थित हैं, कि एक-दो केसेज़ में उन्होंने बहुत जल्दी दिखाई है, लेकिन आज बीसियों ऐसे केसेज़ हैं कि जो पेन्डिंग हैं और जिन पर जल्दी की जानी चाहिए। कल ही सदन में सवाल आया और किसी ने पूछा था कि एन्टीकरप्शन बोर्ड के सामने कितने मामले हैं? उसके बारे में बताया गया कि बोर्ड के सामने मामले ८०० से ज्यादा हैं और उनमें से २८ मामलों का चालान किया गया है। इस २ करोड़ की राजस्थान की जनसंख्या में जहां सैकड़ों काण्ड होते हैं वहां केवल २८ मामलों का ही चालान किया और बाकी में कब निर्णय लेंगे, पता नहीं। यह हमारा पुलिस विभाग और क्रिमिनल इनवेस्टीगेशन डिपार्टमेन्ट कितना बड़ा है

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

और इस पर कितना खर्च किया जाता है फिर भी हमारी कोई सुरक्षा नहीं है ! हमारे सभापति महोदय ने भी, जो इस समय सभापति पद पर विराजमान हैं, कहा था कि अभी थोड़े समय पहले डाकू जगमालसिंह ने बीकानेर में ४ डकैतियां डालीं। वहां पर जगमालसिंह तो आज से नहीं, बल्कि पिछले दस साल से डाका डाल रहा है पर उसको पकड़ा नहीं जा सका है। अभी भी वह डाका डाल कर पाकिस्तान की हद में चला गया और सरकार उसको पकड़ने में बिल्कुल असमर्थ रही है और यह अब की बार हमारे गृह मन्त्रीजी का टैस्ट है कि इस बार वे गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया से सम्पर्क स्थापित करके पाकिस्तान को किस प्रकार जगमालसिंह को वापिस सुपुर्द करने को बाध्य करते हैं। इसका तो एक-दो महीने में मालूम पड़ेगा कि वे कहां तक इस टैस्ट में उतरते हैं। यह हमारी ब्यूरोक्रेसी का भी टैस्ट है कि १ करोड़ २७ लाख का टैक्स नहीं लगायें और वह कम हो तो कोई हर्ज नहीं है। आप एक दूसरी तरह से बचत कर सकते हैं और वह इस तरह कि आप जो बड़े बड़े सरकारी कर्मचारियों को स्पेशल पे २००-२५० रु. देते हैं उसको यदि खत्म कर दिया गया तो काफी बचत हो सकती है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का विभाग है जो यह सब काम करता है उसके ऊपर बहुत गहराई से विचार किया जाये।

इन्डस्ट्री की बात लीजिए। हमारी सरकार क्या कहती है ? इन्डस्ट्री विभाग के द्वारा लाखों रुपया इन्डस्ट्रीज़ को उधार दिया गया है और मैं उसकी डिटेल में यहां नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ७५ लाख रुपया जयपुर उद्योग को उधार दिया गया। लाखों रुपया ऐसी कम्पनीज़ को दिया गया जो आज दिन बन्द पड़ी हैं। ये इन्वेस्टमेन्ट के आंकड़े बजट डिपार्टमेन्ट ने छाप कर दिये हैं बजट स्टेडी बुक में। इसके इन्वेस्टमेन्ट के चैप्टर में पढ़े तो मार्जिन पर बीसियों ऐसी कम्पनियां मिलती हैं जिनके ऊपर लिखा है "नोट फंक्शनिंग"। यह बीसियों पर लिखा है "Not functioning", "Has gone into voluntary liquidation", किसी को २० हजार, किसी को ३० हजार और किसी को ४० हजार दे रखे हैं और यह रकम अभी तक बकाया है। कुछ ऐसी कम्पनियां हैं जो कलकत्ता, बम्बई और इलाहाबाद में चल रही हैं, उनको भी पैसा दे रखा है। राजस्थान के नाम से कोई कलकत्ते में कम्पनी फ्लोट कर ली उसको १० लाख रुपया मिल सकता है। मंत्री महोदय के नाम पर कोई कम्पनी फ्लोट कर ली उसको भी एक लाख रुपया मिल सकता है ! बड़े ताज्जुब से मैंने देखा कि हरिश्चन्द्रजी हमारे मिनिस्टर साहब हैं उनके नाम से एक कम्पनी बनी हुई हैं, 'हरिश्चन्द्र पोटेरीज़ वर्क्स, झालावाड़' और उसके अन्दर हमारी सरकार ने १०,०००) की रकम उसको उधार दे रखी है ! रुपया देते हैं क्योंकि मिनिस्टर साहब के नाम पर कम्पनी खोलो।

श्री सभापति (श्री भीमसेन) : यह कम्पनी स्टेट के टाइम की होगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : राजस्थान सरकार ने १०,०००) रु० दिये हैं और २२-४-५८ से फन्क्शन नहीं कर रही है।

Page No 90

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : Sir, I think the name was given to the firm when he was the actual Ruler of that state, thereforehis implication is not correct.

श्री मानिकचन्द सुराणा: When this grant was made ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : Do you mean that the name should de changed now ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : इनको सब देते हैं। सरकार ने १०,०००) रु० दिया है और फन्क्शन नहीं कर रही है ! माननीय सदस्य इस बात की वकालत नहीं करना चाहते हैं कि जो कम्पनी फन्क्शन नहीं कर रही है उसको सरकार उधार दे। एक नहीं, बीसों कम्पनियां हैं। तीन लाख रुपये 'अम्बिका एयरलाइन्स, बम्बई,' को दिये गये हैं जिसके नीचे लिखा है, 'under voluntary liquiation.' मैं नहीं समझता कि इस तरह से वॉलेन्टरी लिक्विडेशन में जाने वाली कम्पनियों को उधार देकर क्या युटीलिटी गरीब जनता के पैसे की कर रहे हैं ? उद्योगों की प्रगति के नाम पर लाखों रुपये अपने समर्थक पैदा करने के लिए दे दिये हैं और एक मशीन का चक्का भी वहां नहीं चला, छोटी-मोटी मशीन भी वहां नहीं लगी और कम्पनी वॉलेन्ट्री लिक्विडेशन में जा रही है। ७५ लाख रुपये 'जयपुर उद्योग' का दे रखे हैं, 'मान इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन' को लाखों रुपये दे रखे हैं और अपने आपको समाजवादी कहते हैं ! कांग्रेस पार्टी के उन लोगों को जो अपने आपको समाजवादी कहते हैं मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो बड़े बड़े कॉर्पोरेशन्स को लाखों रुपये उधार देना चाहते हैं, उनके साथ में पार्टनरशिप करती है स्टेट और एक तरफ अपने आपको समाजवादी कहते हैं ! यह कैसे समाजवादी हैं ? पब्लिक अन्डरटेकिंग की हालत क्या है कि उसमें मुनाफा कम है। कुल मिला कर जितना रुपया दिया है उसका डेढ़ पर्सेन्ट आपकी सरकार को नहीं मिलता है। आखिर यह जनता का पैसा है। ६ पर्सेन्ट तो कम से कम ब्याज देना पड़ता है और उन सारी कम्पनियों में जिनको लाखों रुपया उधार दिया गया है उनमें डेढ पर्सेन्ट मुनाफा हैं। यह स्थिति उद्योग मंत्री के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। राजस्थान में उधार दिया जाता है, पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट किया जाता है कि राजस्थान सरकार का यदि पैसा लगता है तो राजस्थान की इन्डस्ट्रीज़ में लगना चाहिए और राजस्थान के बाहर लगता है तो विशेष स्थिति होनी चाहिए। इलाहाबाद में दे दिया, बम्बई में दे दिया,' अम्बिका एयरलाइन्स' को दे दिया तो राजस्थान के निवासी उसी एयरलाइन्स में ट्रेवल कर सकते थे, अन्यथा ट्रेवल नहीं कर सकते थे। ऐसी कम्पनियां लिक्विडेशन में चली गई। आप लोग कहते हैं कि सुझाव देना चाहिए और टैक्स के लिए इस तरह से कहेंगे कि डाइरेक्ट जनता पर उसका वजन भी नहीं पड़े। हम कहना चाहते हैं कि आप यदि अपने इनवेस्टमेंट के पैटर्न में तब्दीली कर लें तो लाखों रुपये बच सकते हैं और यदि आप करने को तैयार नहीं हैं तो विरोधी दल को उपदेश देना, मैं समझता हूं कि कोई मायने नहीं रखता है।

इन्डस्ट्रीज़ के नाम पर आज करोड़ों और लाखों रुपये दिये जाते हैं। यदि कांग्रेस पार्टी

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

को चुनाव के लिए चन्दे की जरूरत है, यह सिर्फ उसी दृष्टिकोण से दिये जाते हैं तो पार्टी लाइन्स पर उसका जस्टीफिकेशन हो सकता है, लेकिन राजस्थान के दृष्टिकोण का जस्टी-फिकेशन इस तरह से उधार देकर नहीं किया जा सकता ।

माइन्स का हाल देखिये। मिनरल्स के प्रोडक्शन के बारे में बहुत कुछ बातें कही जा सकती हैं ! सन् ५६ के भाषण में पलाना के बारे में कहा गया है कि पलाना को कौयले की खान के लिए नये तरीके ईजाद कर लिये हैं। उसके लिए राज्यपाल महोदय के भाषण में कहा गया है। वह कौनसा नया तरीका है ? मैं ६ साल से वहीं रहता हूँ और देखता हूँ और माइन्स मैनेजर से बातें करता हूँ तो कोई भी नया तरीका नहीं ईजाद किया गया है। यह राजस्थान की जनता को गलत तथ्य सन् ५६ में दिये गये। आज तक ओपन कास्ट माइनिंग जिसके लिए भारत सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने राय दी थी कि ८ पर्सेन्ट कोयले के प्रोडक्शन में वृद्धि की जा सकती है - आज तक ओपन कास्ट माइनिंग की तरफ कदम नहीं बढ़ा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पलाना खान के लिए दो करोड़ रुपये रखे गये थे। वे दो करोड़ रुपये बिल्कुल बेमत-लब गये। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना में साढ़े तीन करोड़ रुपये रखे गये हैं, तो मैं खान मंत्री और उपमंत्री से निवेदन करूंगा कि वे फौरन मौके पर जाकर सारी स्थिति को समझें। आखिर ८० पर्सेन्ट प्रोडक्शन बढ़ाने का सवाल है। एक्सपर्ट कमेटी ने पिछली बार कहा था। उनकी १०० पेज की रिपोर्ट को खुद पढ़ें, डिप्टी मिनिस्टर को पढ़ावें और अपने सेक्रेट्री और डिप्टी सेक्रेटरी को कहें कि वे पढ़ें कि पलाना खान के लिए एक्सपर्ट कमेटी ने क्या बात कही है। एक्सपर्ट कमेटी ने कहा है कि फर्टीलाइज़र फैक्ट्री उसके साथ में लगाई जाय, उसके साथ में सीमेंट फैक्ट्री लगाई जाय। फर्टीलाइज़र फैक्ट्री लगाना तो दूर रहा, सीमेन्ट फैक्ट्री लगाना तो दूर रहा कोयले का उत्पादन नहीं बढ़ा है। वे केवल सामन्तवाद का विरोध करते हैं तो साम-न्तवादी राज्य में मैं कहता हूं कि ६७,००० टन कोयला पैदा होता था और आज ३०,००० टन पैदा होता है। ३७,००० टन का नुकसान हुआ है। कम से कम ८ लाख रुपये का नुकसान एक महीने में पलाना खान के अन्दर कर रहे हैं। और ८ लाख का नुकसान एक महीने में होता है तो वह १२ महीने में ६६ लाख के प्रोडक्शन का नुकसान सिर्फ पलाना की खान में कर रहे हैं। इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूं कि पलाना लिग-नाइट कोल माइन्स को ओपन कास्ट माइन में कन्वर्ट करें और सरकार जितना जल्दी हो सके वह नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाये।

माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने राज्यपाल महोदय के भाषण के सिलसिले में यह कहा कि पलाना खान को भारत सरकार ने लेने से इन्कार कर दिया। मैं समझ नहीं पाया कि इस स्टेटमेंट से क्या मतलब था उनका। उसकी मालिक राजस्थान सरकार है। देश की कोई भी कोयले की खान ऐसी नहीं है जो नुकसान में जा रही हो, लेकिन राजस्थान सरकार की कोयले को खान ही एक ऐसी है जिसमें हर साल नुकसान होता है और वहां पर

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी यह शिकायत है कि जो वर्कलोड उन पर आज है उसके अनुसार एक्सपर्ट कमेटी की राय के अनुसार जितने भी आदमी काम करते हैं उनसे दुगुना प्रोडक्शन होना चाहिये। अगर प्रोडक्शन दुगना नहीं होता है तो जितने कर्मचारी हैं उनसे आधे कर्मचारी रखने चाहिये। सरकार को रिपोर्ट देखने की फुरसत नहीं। उसको देखकर ६६लाख की पलाना से रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ाने की फुर्सत नहीं। उसके लिए दिमाग की अन्धता को दूर करने को तैयार हों इसलिए मैं खान मन्त्री और डिप्टी मिनिस्टर से, सभापति महोदय, आपके मार्फत यह कहना चाहूंगा कि पलाना खान के मैटर को अर्जेन्ट प्रायोरिटी दें। उसके साथ ही सोडियम सल्फेट जो डीडवाने में है और जो जल्दी ही लगना चाहिए उसके मेटर के अन्दर बहुत फुर्ती करें।

माइन्स के बारे में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि सरकार यह भूल जाय कि टैक्सेज़ के जरिये वे तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बना सकते हैं। मेरी निश्चित राय है कि टैक्सेज़ के वजन को अब राजस्थान की जनता पर नहीं बढ़ाया जाना चाहिये, यदि हम नॉन टैक्सेज़ रेवेन्यु की आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसलिए सरकार फैसला कर दे कि जहां १ लाख या ५०,०००)की आमदनी हो उसको वह स्टेट एन्टरप्राइज़ की तरह शुरू करेगी। तो मैं समझता हूं कि करोड़ों रुपये खनिज पदार्थों के जरिये प्राप्त हो सकते हैं और करोड़ों रुपयों के टैक्सेज़ का राजस्थान की जनता पर वजन नहीं पड़ेगा और तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रोडक्शन के लक्ष्य को पूरा करना है, टार्गेट तक पहुँचना है, वे लक्ष्य पूरा कर सकते हैं।

आखिर माइका का उद्योग भीलवाड़े में इतना बड़ा उद्योग प्राइवेट एन्टरप्रेन्योर्स को देते हैं उन्होंने क्या किया कि जगह २ खड्डे कर दिये हैं। वैज्ञानिक ढंग से कहीं माइनिंग नहीं किया है। सरकार के डाइरेक्टरऑफ माइन्स एन्ड ज्योलोजी जो हैं वे बहुत कुछ समझते हैं, बहुत ही होशियार आदमी हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी होशियारी का और परीक्षण गरना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि भीलवाड़ा के अन्दर नये एन्टरप्राइज़ स्टेट बेसिस पर शुरू करना चाहते हैं। स्टेट उसकी मालिक होगी। स्टेट एक्स्केवेशन करेगी माइका का। प्राइवेट पार्टीज़ को लीज़ दिया जाना बन्द कर देना चाहिए। स्टेट माइन्स को हाथ में लेकर खनिज पदार्थ पैदा करें।

इसलिए खनिज पदार्थ और फोरेस्ट ये दो ही ऐसे राजस्व के मद हैं, हिस्से हैं जिनकी ओर यदि सरकार ध्यान दे तो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिल सकती है। यदि माइन्स के जरिये यह संतोष करलें कि ५० लाख से आमदनी बढ़ कर १ करोड़ हो गई तो यह गलत दृष्टिकोण होगा। यदि सरकार चाहे तो माइन्स के जरिये ५० लाख से १ करोड़ की ही नहीं; ५ करोड़ को रेवेन्यू कर सकती है, यदि प्राइवेट पार्टीज़ को लीज देना बन्द करदे तो।

फोरेस्ट के वर्किंग को लीजिये। फोरेस्ट के मन्त्री महोदय यहां उपस्थित नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : बैठे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : फोरेस्ट से ६५ लाख की रेवेन्यू होती है और ६१ लाख का एक्सपेन्डीचर करते हैं। सारे राजस्थान का फोरेस्ट सिर्फ ४ लाख की रेवेन्यू या बचत सरकार को देता है। मैं मन्त्रीजी से कहना चाहूंगा कि ४ लाख की रेवेन्यू होती है आपको फोरेस्ट से, आप अन्दाजा लगाइये ६१ लाख का जो खर्चा करते हैं उनमें से कितना प्रशासन पर करते हैं? आपको मालूम होगा कि ४० रुपये प्रशासन पर खर्च करते हैं। फोरेस्ट जैसे विभाग में ६५लाख में से ४० लाख रुपये प्रशासन का खर्चा है बाकी कंजरवेन्सी और दूसरे मदों पर खर्चा है तो मैं कहना चाहता हूं कि यदि सही माने में मन्त्रीजी कहना चाहें कि हमने अपने फर्ज को निभाया है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि फोरेस्ट की रेवेन्यू ४ करोड़ की हो सकती है। नॉन टैक्सेशन के जरिये यदि सरकार अपनी आमदनी बढ़ाना चाहती है तो यह एक बहुत अच्छा जरिया है। हम तो सुझाव देते हैं लेकिन उस पर अमल भी होना चाहिये। यदि कमी है तो एक टेबल पर बैठ कर बात करिये, आपकी ब्यूरोक्रेसी को भी बुलाइये, हम बताने को तैयार रहेंगे कि इस तरह से बढ़ाना चाहिए। नॉन टैक्सेशन के जरिये बहुत आमदनी बढ़ सकती है, लेकिन आज उससे आमदनी घट रही है। हम उसका विरोध करते हैं। आज आप ८७ सदस्य हैं लेकिन हो सकता है कि सन् ६७ में ४७ भी न आवें। हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग आपकी जगह बैठें। हम कहते हैं कि आप ही ट्रेज़री बैन्चेज़ पर बैठें, लेकिन हम नॉन टैक्स से रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं। हमारे राजस्थान में २७ करोड़ रुपये नॉन टैक्स के वित्त मन्त्रीजी ने बजट में आंके हैं। मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि १० करोड़ रुपयों की बढ़ोत्तरी वित्त मन्त्रीजी ने आंकी है लेकिन मुझे इस आमदनी के होने में पूरा शक है। सिर्फ ४ करोड़ रुपये जो ग्रान्ट-इन-एड के जरिये मिलनेवाली है वे तो निश्चित रूप से आ सकते हैं क्योंकि भारत सरकार देगी। लेकिन इन ४ करोड़ के अलावा मुख्य किस मद में बढ़ोत्तरी की है; मैंने यह समझने की कोशिश की लेकिन मुझे मालूम हुआ कि मिस्लेनियस हैड में ४ करोड़ के इजाफे की बात कही है। इजाफे का हैड फोरेस्ट, इर्रिगेशन, माइनिंग आदि नहीं मिला। केवल मिस्लेनियस में ४ करोड़ का इजाफा आंका गया है। सन् ६१-६२ में मिस्लेनियस हैड में रेवेन्यू ४ करोड़ की आंकी गई थी वहां अब ८ करोड़ ८१ लाख की आंकी गई है। मैं नहीं समझ सकता कि ४ करोड़ की मिस्लेनियस में कैसे बढ़ोत्तरी होगी। ४ करोड़ ग्रान्ट-इन-एड के जोड़े हैं वह तो ठीक है भारत सरकार देगी लेकिन ४ करोड़ मिस्लेनियस में बताया है वह मैं कहता हूँ नहीं मिलेगा और जो सरप्लस बजट १ लाख को दिखाया है वह बजट सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स द्वारा साल के अन्त में ४.६ करोड़ का घाटे का मिलेगा। जिस प्रकार ७ करोड़ की सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट इस साल ली है उसी तरह से ७ करोड़ की सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट साल के अन्त में और ले लेंगे........

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : The Head 'Miscellaneous' includes Mines also.

श्री मानिकचन्द सुराणा : और साल के अंत में इसी तरह से यह सरप्लस बजट डेफिसिट में कन्वर्ट हो जायेगा। एक माननीय

Page No 94

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

सदस्य ने अभी कहा है कि मिस्लेनियस हैड में माइन्स को इन्क्ल्यूड कर लिया है........

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हमेशा से है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मिस्लेनियस में माइन्स को इन्क्ल्यूड किया तो यह साफ हो जाता है, आप कहते हैं ६१ लाख का खर्चा करते हैं और ६५ लाख की कमाई करते हैं। इस वर्ष निर्णय किया है कि ४ लाख की नहीं करनी है बल्कि ४ करोड़ की कमाई माइन्स से करनी है; तो हम इसका स्वागत करते हैं लेकिन इतने वर्ष यह कमाई क्यों नहीं मिली? खैर, यह साल के अंत में मालूम हो जायेगा, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। मुझे मालूम है कि १० करोड़ की रेवेन्यू साल के अंत में नॉन टैक्स से करने की बात कही है वह सही नहीं है। ये आंकड़े गलत ढंग से तैयार किये हैं। जिस नॉन टैक्सेशन की रेवेन्यू १८ करोड़ ६०-६१ में थी १७.२७ करोड़ ६१-६२ में आंकी थी वह भी नहीं मिली तो ६२-६३ में २७ करोड़ कैसे हो जायगी? ६०-६१ में जो १८ करोड़ की आंकी गई थी वह ६१-६२ में १७ करोड़ रह गई। उसके बारे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वह १० करोड़ इस वित्तीय वर्ष में बढ़ जायेगी, यह किस तरह बढ़ जायेगी, यह देखेंगे।

मैंने फोरेस्ट के बारे में कुछ निवेदन किया। अब मैं कुछ बातें राजस्थान केनाल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मसला है........

श्री सभापति (श्री भीमसेन) : आपने काफी समय ले लिया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं कल कन्टिन्यू करूंगा।

श्री सभापति : कल नहीं, आज ही समाप्त करिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मुझे अभी समय लगेगा। आज तो ५ ही मिनट शेष रह गये हैं।

श्री सभापति : आप काफी बोल चुके हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : राजस्थान केनाल के बारे में विरोधी दल से जनसंघ के नेता ने कहा था कि राजस्थान केनाल को लम्बा कर दें तो हर्ज नहीं है, जो काम १० साल में पूरा करना है वह १५ साल में पूरा हो तो क्या नुकसान है। मैं कहना चाहूंगा कि जैसी मंशा है जनसंघ के नेता की उसे तो राजस्थान सरकार ने ही पूरा कर दिया है क्योंकि पहले केनाल के लिये एक मन्त्री अलग हुआ करते थे जिनका डेज़िग्नेशन राजस्थान केनाल मिनिस्टर था लेकिन वह पद अब तोड़ दिया गया है क्योंकि सरकार की मंशा दरअसल में यह है कि इसको जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है, १५-१६ वर्ष में पूरा करना है और जिस तरीके से काम हो रहा है उसको देखते हुए इसमें १५-१६ साल और लगेंगे। लेकिन जब यह बात विरोधी दल के नेता की तरफ से कही जाती है कि इस काम को लम्बा किया जाय तो मैं साफ तौर से कह सकता हूं कि जयपुर में रहने के कारण शायद उनको पता नहीं है जो लोग रेगिस्तान के इलाके में रहते हैं उनके लिये पानी का क्या महत्व है, उनको मालूम नहीं है कि

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

वहां के लोगों के लिये इस केनाल का कितना महत्व है। उनको इसका महत्व मालूम नहीं है क्योंकि वहां कोई जनसंघ की शाखा नहीं है और न वहां से उनका कोई सदस्य चुन कर आया है। इसलिये उनको इस केनाल के महत्व का ज्ञान नहीं है। राजस्थान नहर का कितना बड़ा महत्व है यह तो उस इलाके के रहने वाले ही जान सकते हैं जो यह जानते हैं कि यह नहर लाखों बीघा बंजर भूमि में पानी देकर उसको उपजाऊ बनायेगी। इसको आप लम्बा करना चाहते हैं। 'ना पक्ष' के लोग 'हां' पक्ष के लोगों को इस लाइन पर चलाना चाहते हैं। यह ६० करोड़ का बजट है। इसमें एक जगह घटाओ, दूसरी जगह बढ़ावो तो राजस्थान केनाल को घटा कर स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसको यदि पनपाना है तो राजस्थान नहर को छेड़ने की जरूरत नहीं है। स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज़ को अगर चलाना है तो पहले इन्वेस्टमेंट पेटर्न को डिटर्मिन करिये। जो ८८ लाख रुपये इस समय रखे हैं उनके बारे में आपको फैसला करना चाहिये कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को सहायता न देकर स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज़ में लगावें तभी जाकर उद्योगों का विकास हो सकता है। यदि आज जयपुर उद्योग लिमिटेड में ७५ लाख रुपये के शेयर्स सरकार ने रखें हैं तो क्या जरूरत है इन शेयर्स को रखने की? मैं मांग करता हूं कि ये ७५ लाख रुपयों के शेयर्स बेच दें। हमको जरूरत नहीं है इन शेयर्स की, इनको डाइवर्ट कर दें स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज़ में। हमको नहीं चाहिये एस. पी. जैन और करोड़पतियों की सहानुभूति, हमको नहीं चाहिये १।। परसेन्ट का व्याज, जहां २५०) रु. या ५००) रु. का एम्पलॉयमेंट मिलता हो, आज हमको इन्डस्ट्रीज़ चाहिये जिनमें छोटे छोटे लोगों को एम्पलॉयमेन्ट मिलता हो। आज देखना है कि एम्पलॉयमेंट की पोटेन्शियेलिटी क्या है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस पर बहुत बड़ा एम्फेसिस देना चाहिये।

इस बारे में विकास में ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा महत्व है। इसको आपने कितना निभाया है? सिर्फ नेशनलाइज़ेशन की बात कही जाती है। राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीयकरण किस तरह किया जाता है? हम नहीं चाहते कि मोटर पार्ट्स या मशीनरी के जो हिस्से हजार, डेढ़ हजार में मिलते हैं वे सरकारी कर्मचारियों की मारफत २०० रू. में बेचे जावें। यह एक करप्शन का बेसिस बन गया है उसके हम तीव्र विरोधी हैं। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीयकरण करें लेकिन यह नहीं चाहते कि इसमें करप्शन या बुराई आवे। एक तरफ आप राष्ट्रीयकरण करते हैं और दूसरी तरफ टैक्सेज़ लगाते हैं। जो आर. टी. ए. बना रखे हैं उनकी मीटिंग २१,२२ महीनों तक नहीं होती है और उनके कारण पचासों रूटों पर परमिट नहीं देने के कारण लोस होता है और जो लाखों रुपयों की बकाया होती है उस तरफ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का ध्यान नहीं है। बीकानेर में आर. टी. ओ. ने पिछले ३ लाख रुपयों का टैक्स माफ किया है लेकिन आपको फुर्सत नहीं है यह देखने की कि कितना माफ कर दिया। अपने अधिकारों के बाहर अधिकारी टैक्स माफ करते हैं जो वाजिब नहीं हैं; लेकिन आपको फुरसत नहीं है यह देखने की कि राजस्थान में आर. टी. ओ. ने कितना टैक्स माफ कर दिया। और इसे माफ

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

करना उनके अधिकार में था या नहीं। इसकी जांच करने के लिए एक कमेटी बैठानी चाहिये और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को पूरी रिपोर्ट लेनी चाहिये और यदि अधिकार के बाहर माफ किया है तो सख्त कार्यवाही उनके खिलाफ करनी चाहिये।

अन्त में बजट प्रपोज़ल्स में जो टैक्सेज़ लगाये हैं उनके बारे में पहले भी निवेदन किया है। विरोधी दल के लोग विस्तार से इस बारे में कह चुके हैं कि हम विरोध करते हैं इनडाइरेक्ट टैक्सेज़ का। ५६.५७ से इनडाइरेक्ट टैक्सेज़ बढ़ रहे हैं। बजट स्टडी साफ कहती है कि डाइरेक्ट टैक्सेज़ ५५-५६ में ५७.८ थे उनको ६२-६३ में ४३ परसेन्ट कर दिया है। गर्ज यह कि डाइरेक्ट टैक्सेज़ कम हो रहे हैं, आपके राज्य में और इन्डाइरेक्ट टैक्सेज़ बढ़ रहे हैं। मैं वित्त मन्त्रीजी से यह कहना चाहता हूँ कि यह समाजवाद का रास्ता नहीं है। समाजवाद में अमीर और गरीब का भेद मिटाया जाता है लेकिन आपके तरीके से गरीबों पर अमीर पला करते हैं। आपके रास्ते से अमीर और अमीर बनता है और गरीब और गरीब बनता जा रहा है। इसलिये जो समाज वाद की बात कह रहे हैं उनका विरोध करता हुआ मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री सभापति (श्री भीमसेन) : सदन की कार्यवाही कल प्रात:काल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ५ बजे, शुक्रवार, दिनांक ३० मार्च १६६२ के म० पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त–विवरण

(गुरुवार, २६ मार्च, १६६२)

	स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	१४३०
भाखरा योजना के अन्तर्गत विद्युत् वितरण।	
नगरपालिका, बीकानेर के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल।	
ग्राम इशवाले से माहोली (उदयपुर) तक सड़क–निर्माण।	
जिला झुंझुनू के अन्तर्गत बनने वाली सड़कों की योजना।	
राजस्थान रोडवेज़ की बसों पर नियुक्त कर्मचारी।	
नीम का थाना से उदयपुर जाने वाली पक्की सड़क का निर्माण।	
चूड़ियों पर बिक्री कर।	
तिजारा तहसील में भाखरा की बिजली।	
कार्य–सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन तथा उस पर विचार	१४५०

श्री मथुरादास माथुर, गृह मन्त्री ने कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

	स्कम्भ
उन्होंने निम्नांकित प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जो सदन द्वारा स्वीकार किया गया :—	
"यह सदन कार्य—सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।"	
आय-व्ययक (बजट), १६६२–६३ : प्रथम अवस्था–सामान्य वाद-विवाद	१४५०

आय-व्ययक, १६६२-६३ पर आज भी वाद–विवाद जारी रहा जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

(१) श्री नारायणसिंह
(२) श्री बृजसुन्दर शर्मा
(३) श्री भीमसेन
(४) श्री मुरलीधर व्यास
(५) श्री दुर्गालाल बाढदार
(६) श्री ज्वालाप्रसाद
(७) श्री विजयसिंह
(८) श्री फूलचन्द जैन
(९) श्री मानिकचन्द सुराणा

सदन की बैठक ठीक ५ बजे शुक्रवार, दिनांक ३० मार्च, १६६२ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

Page No 98

स्कम्भ

शुक्रवार, ३० मार्च, १६६२ की
कार्य-सूची

१. आय-व्ययक पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद

२. जन-लेखा एवं प्राक्कलन समितियों के निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४६ का उत्तर देखिये)

List of proposed Metalled roads and Tarred roads during the III Five Year Plan in District Jhunjhunu.

1)	Metalled road from Jhunjhunu to Mandawa.	4 Miles.
2)	Metalled road from Jhunjhunu to Shrimadhopur Via Guda and Udaipur.	27 Miles.
3)	Construction of road from Chirawa to Pilani.	1 Mile.
4)	Metalled road from Surajgarh to Chirawa.	6 Miles.
5)	Bitumen treatment of Shahpura, Jhunjhunu road via Nimkathana, Nimkathana, Singhana and Chirawa (P. L.)	34 Miles.
6)	Bitumen treatment of Jhunjhunu to Sikar Road.	7 Miles.
New Works:—		
7)	Completing the remaining portion of painted road from Jhunjhunu to Sikar via Mukandgarh-Nawalgarh.	9 Miles.
8)	M/R. Singhana to Satnali up-to Rajasthan Border Via Bhuwana.	7 Miles.
9)	M/R Bisau to Mandawa.	6 Miles.
10)	Construction of Udaipur-Nawalgarh Road.	5 Miles.
11)	M/R Mandawa to Fatehpur.	2 Miles.
12)	M/R Jhunjhunu to Sankhu via Alsisar—Malsisar.	7 Miles.
13)	M/R from Mukandgarh to Railway Station.	1/2 Miles.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४७ का उत्तर देखिये)

नगरपरिषद्, बीकानेर

म्युनिसिपल कर्मचारी संघ की मांगें

१) रोजमर्रा की समस्याओं के हल के लिये इम्पलिमेन्टेशन कमेटी बनाना।
२) प्रोविडेन्ट फण्ड की पास बुक व वर्दियां देना।
३) नये ग्रेड्स देना।
४) भिश्तियों को मशक अलाउन्स देना।
५) समस्त पुराने समझौतों पर अमल करना।
६) कर्मचारियों का बोनस बैंक में जमा कराना।
७) ग्रेच्युइटी की व्यवस्था करना।
८) निःशुल्क मेडिकल एड दी जाय।
९) लीव रीजर्व की नियुक्ति शीघ्र की जाय।
१०) फिक्सेशन १-४-५० से समस्त कर्मचारियों का किया जाय।
११) ओवर टाइम भत्तों का भुगतान किया जाय।
१२) प्रोमोशन सीनियरिटी के आधार पर किये जांय।
१३) भैंसे वालों को हार्ड ड्यूटी अलाउन्स देना।
१४) विनोबा बस्ती के हरिजनों को कर्ज की राहत में सहयोग देना।
१५) सेनिटरी इन्सपेक्टरों को वर्दियां भत्ता बढ़ाया जावे।
१६) ग्रेडस् इन्क्रीमेन्ट समय पर दिया जाय।

———

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार दिनांक २६ मार्च, १९६२)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१४३६	अन्तिम पंक्ति	अपोइन्टमेट	अपोइन्टमेन्ट
१४३७	१४	डाइवर्स	ड्राइवर्स
१४४२	२	तिजरा	तिजारा
१४४५	अन्तिम से ४	कार्ययाही	कार्यवाही
१४४८	२	लैठर	लैटर
१४५०	१८	श्री अध्यज्ञ	श्री अध्यक्ष
१४५१	२८	LandRe venue	Land Revenue
१४५२	२६	६१ में ६२ में और ६२–६३	६१–६२ में और ६२–६३ में
१४५३	५	५७,५	५७.५
१४५८	२१	कन्यूमर	कन्ज्यूमर
१४६३	२१	अलवा	अलावा
१४७०	१५	इन्डिन्ट्रयल	इन्डस्ट्रियल
१४८३	२६	आम आवाम	आम अवाम
१४८५	२४	imstalment	instalment
१४८६	४	अनुपात	अनुपात में
"	९–१०	ऑरगेनाइजेशन	आर्गेनाइज़ेशन
१४८८	२०	मेनज	मेनेज
१४९१	८	ऑर्नामेंन्ट्स	ऑर्नामेन्ट्स
१४९३	२६	रिमाक्सं	रिमार्क्स
१४९७	५	ईस साल	इस साल
१५०१	१५	जोरों	ज़ीरो
१५०७	१६	चलने बसों	चलने वाली बसों

Page No 102

१	२	३	४
१५०७	अन्तिम से ३	मदरेणा	मदेरणा
१५०८	१५	कढ़वी	कड़वी
१५१३	२६	ओरत	औरत
१५१७	शीर्षक	वाद-विषाद	वाद-विवाद
१५१९	९	प्राक्लन	प्राक्कलन
१५२४-२५, १६१६-१७व १६१८-१९	शीर्षक	माच	मार्च
१५२५	१३,१४व१५	लेकिन सोशलिस्ट पार्टी का मंत्री मंडल बना, ढाई साल तक केरल में प्रजा का काम किया।	लेकिन केरल में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का मंत्री मंडल बना, ढाई साल तक काम किया।
१५२७	११	अर्नामेंट्स	ओर्नामेन्ट्स
,,	२२-२३	होगा क्योंकि क्योंकि	होगा क्योंकि
१५४४	२५	बढ़ाने क	बढ़ाने का
१५४६	१६	है यह	है-कि यह
१५४८	३	सवाल	का सवाल
१५७६	अंतिम पंक्ति	हू'	हूं
१५८८	२७	स्पोर्टस	स्पोर्ट्स
१५९३	२०	२७ करोड़	१७ करोड़
१५९४	१६	मैंथमेटिकली	मैथमेटिकली
१५९५	१	हां, पक्ष	'हां' पक्ष
१६०३	२०	सकता है	सका है
१६०८	३	de	be
१६०८	१८-१९	liquation	liquidation
१६१३	११	गरना चाहिये	करना चाहिये
१६१८	२८	रुपर्यों	रुपयों